

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

भारत से इन्दिरा और इन्दिरा से भारत



गोपी किशन शर्मा

साहित्यागार, जयपुर



प्रथम संस्करण : 1987

मूल्य : चालीस रुपये

© गोपीकिशन शर्मा

प्रकाशक : साहित्यागार

एस. एम. एस. हाईवे

जयपुर

मुद्रक : मनोज प्रिन्टर्स

जयपुर



मेरी दोनों बहिनें
चन्द्रमणी व मंजू
को
जिनकी केवल स्मृतियाँ
शेष हैं ।

—गोपीकिशन शर्मा

प्रकाशकीय

श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी विश्व विख्यात महान नेता के जीवन पर जितना लिखा जाय थोड़ा ही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विलक्षण प्रतिभा के घनी के घर जन्म लेकर जीवन की विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए ही प्रियदर्शनी इन्दिरा जी ने अपने जीवन का निर्माण किया और एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व की घनी बनी। पंडित जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। प्रतिक्षण राष्ट्र की समस्याओं से चिन्तित पंडित जवाहरलाल नेहरू को कभी घर की ओर ध्यान देने का जैसे अवसर ही न था। ऐसे में घर में पुत्र न होना और भी चिन्तनीय था। घर में नहीं बच्ची प्रियदर्शनी इन्दिरा जी को वाल्यकाल में ही बहुत कुछ समस्याओं से जूझने की शिक्षा मिली। एक महान व्यक्तित्व का निर्माण वाल्यकाल में ही प्रारम्भ हो गया था। अंग्रेजों से मोर्चा, बान्दर सेना का गठन और अनेकानेक घटनाएं उनके जीवन से जुड़ता चली गयीं।

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश की प्रधान मन्त्री बनने का अवसर मिला कोई यह नहीं जानता था कि यह महिला वर्षों तक प्रधानमन्त्री रह कर अपनी विशिष्ट छाप देशवासियों के दिलों पर छोड़ेगी। प्रधान मंत्री के पद पर रहते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के बहुमुखी विकास में महान योगदान दिया।

अकाल, अतिवृष्टि, गरीबी और अशिक्षा जैसी समस्याओं के समाधान में प्रयत्नशील रहते हुए देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु अन्ततः देश हित में अपने आपका बलिदान भी कर दिया। इस आणविक युग में विश्वशान्ति को कायम रखने और सम्पूर्ण मानवता के हित में विश्व स्तर पर अनेकानेक समस्याओं के समाधान में रत रह कर अपना और भारत का गौरव बढ़ाया। ऐसी विश्व विख्यात महान नेता के जीवन पर प्रस्तुत लघु कृति 'भारत से इन्दिरा और इन्दिरा से भारत' एक नवोदित लेखक की लेखनी के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है। आशा है भावी पीढ़ी को महान नेता के कृत्यों से अवगत कराने, देश सेवा में रत रहने को प्रेरित करने में यह पुस्तक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी।



भूमिका

आधुनिक भारत की निर्माता प्रधानमंत्री “भारत रत्न” श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन पर जितना लिखा जावे वो बहुत कम है। फिर भी इस पुस्तक में श्रीमती गांधी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के कार्यों एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में लिखा है।

यह पुस्तक छात्रों, शिक्षाविदों, राजनेताओं तथा समाज के हर वर्ग के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन पर जोन आफ आर्क के दर्शन का प्रभाव पड़ा। जोन आफ आर्क फ्रान्स के चरवाहे की पुत्री थी और पशु चराकर खुश रहती थी। एक दिन एक सन्त ने उससे कहा “जोन” जब अंग्रेज तुम्हारे देश पर शासन कर रहे हैं, तब भी तुम खुश हो ?

सन्त की बात सुनकर जोन आफ आर्क ने अपने प्यारे पशुओं और माता पिता को छोड़कर ग्रामीणों की एक सेना इकट्ठी करके एक दिन अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर दिया, वह सबसे आगे तलवार लेकर लड़ी। इस भयंकर युद्ध में अंग्रेज हार गये और फ्रांस की सेना जीत गयी। फ्रांस की जनता ने जोन ऑफ आर्क को फ्रांस की महारानी बना दिया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था “बचपन में जब मैंने जोन आफ आर्क की वलिदान की कहानी पढ़ी, मुझे देश की सेवा करने के लिये इतना जोश आया कि मैं भी जोन आफ आर्क जैसे देश भक्त बनूंगी।”

श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे देश के लिये जोन आफ आर्क ही सिद्ध हुईं। उन्होंने हमारे देश की बागडोर लगभग सतरह वर्षों तक संभाली, इस कालान्तर

में उन्होंने देश का विकास भी तेजी से किया तथा देश की एकता और अखण्डता के लिये स्वयं का बलिदान भी दे दिया ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदर्शों और मूल्यों पर चलकर ही हम हमारी दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजली अर्पित कर सकते हैं तथा हमारे देश को सम्पन्नता एवं वैभव की तरफ ले जा सकते हैं ।

मैं श्री रमेश वर्मा संचालक साहित्यागार का आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे पाठकों के समक्ष एक लेखक के रूप में प्रस्तुत किया ।

गोपीकिशन शर्मा

व्याख्याता

राजकीय उच्च माध्य० विद्यालय

भालामन्ना नगर,

बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)

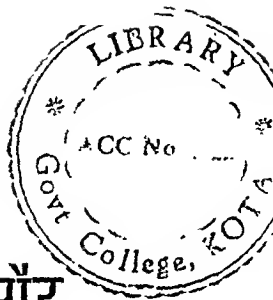


अनुक्रम

1. भारत से इन्दिरा और इन्दिरा से भारत	1
2. श्रीमती इन्दिरा गांधी का पारिवारिक जीवन	8
3. श्रीमती गांधी और राजनीति	15
4. प्रधानमंत्री पद पर	19
5. चुनाव हारने के कारण	24
6. जनता पार्टी शासन और श्रीमती इन्दिरा गांधी	26
7. 1980 में सत्ता में वापिस आने के कारण	31
8. श्रीमती गांधी और उनकी उपलब्धियां	34
9. कृषि उत्पादन के क्षेत्र में	44
10. औद्योगिक क्षेत्र में	48
11. शिक्षा के क्षेत्र में	51
12. पशुधन के क्षेत्र में	54
13. देश की रक्षा के क्षेत्र में	57
14. अन्तरिक्ष के क्षेत्र में	61
15. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में	64
16. जनसंख्या नियन्त्रण के क्षेत्र में	67
17. परमाणु उर्जा के क्षेत्र में	69
18. विदेश नीति के क्षेत्र में	71
19. पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये किये गये कार्य	77
20. जातिवाद का उन्मूलन	79
21. घम और श्रीमती इन्दिरा गांधी	84
22. श्रीमती गांधी और देश की महिलाएं	87
23. राष्ट्रीय एकता एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी	90

24. फिल्म उद्योग और श्रीमती इन्दिरा गांधी	94
25. विदेशी व्यापार और श्रीमती इन्दिरा गांधी	96
26. वन और श्रीमती इन्दिरा गांधी	98
27. यातायात के साधनों का विकास और श्रीमती इन्दिरा गांधी	99
28. खनिज सम्पत्ति एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी	100
29. विज्ञान और श्रीमती इन्दिरा गांधी	102
30. श्रीमती गांधी का दृष्टिकोण	103
31. वैज्ञानिक आत्म-निर्भरता	106
32. कला एवं साहित्य और श्रीमती इन्दिरा गांधी	108
33. श्रीमती गांधी और उनका दर्शन	117
34. खेल और श्रीमती इन्दिरा गांधी	121
35. श्रीमती गांधी और राजस्थान	123
36. श्रीमती इन्दिरा गांधी की नरेना यात्रा	127
37. श्रीमती इन्दिरा गांधी की अन्तिम राजस्थान यात्रा	130





भारत से इन्दिरा और इन्दिरा से भारत

मशाल बुझ गयी। यह वाक्य रेडियो प्रसारण से सुनते ही सारा राष्ट्र शोक में डूब गया। यह मशाल हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी थी।

श्रीमती गांधी विश्व की महान्तम एवं वरिष्ठतम नेता थी जिनकी हत्या उनके ही अंगरक्षक सतवंतसिंह और वेअन्तसिंह ने कर दी। कांस्टेबल सतवंतसिंह के हाथ में स्टेनगन थी और दूसरे हत्यारे वेअन्तसिंह के हाथ में रिवाल्वर थी। वेअन्तसिंह ने पांच गोलियां दागी और सतवंतसिंह ने चौदह राउण्ड गोलियां चलायी थी, जिनमें से बीस ने हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री के शरीर को छलनी कर दिया था। यह घटना बुधवार 31 अक्टूबर, 1984 की थी। रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तो उसका कोई भी निदान नहीं कर सकता है।

वेअन्तसिंह लगभग 8 वर्ष से प्रधान मंत्री निवास में कार्यरत था तथा प्रधान मंत्री का विश्वासपात्र भी था। यह हत्यारा किसी विदेशी शक्ति एवं आतंकवादियों के इशारे पर कार्य कर रहा था।

ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जब दिवंगत प्रधान मंत्री के सामने यह पत्रावली प्रस्तुत की गई कि इन दोनों अंगरक्षकों को सुरक्षा गार्ड से हटा दिया जावे तब प्रधान मंत्री ने यह टिप्पणी की कि धर्म-निरपेक्षता का मतलब यह नहीं होता है कि सुरक्षा गार्ड में कार्यरत सिखों को हटा दिया जावे।

श्रीमती गांधी का धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में पूरा विश्वास था। वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य धर्मावलम्बियों को समान दृष्टि से देखती थी। श्रीमती गांधी सारे राष्ट्र को प्यार करती थी और सभी को एक मानव के रूप में देखती थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपनी मृत्यु का आभास पूर्व में ही हो गया था।

भुवनेश्वर की एक जन सभा में बोलते हुये उन्होंने कहा था कि “मुझे चिन्ता नहीं कि मैं जीवित रहूँ या नहीं जब तक मुझ में साँस है तब तक मैं सेवा करनी रहूँगी और जब भी मेरी जान जायेगी मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती देगा और अखण्ड भारत को जीवित रखेगा।”

श्रीमती गांधी की हत्या का कारण भारतीयकरण का अभाव था। आतंकवादी अपने आपको भारतीय नहीं समझते थे। उनमें से सतवंतसिंह और वेअन्तसिंह भी थे। अकालियों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना था न कि पंजाब की समस्याओं को सुलझाने का। अकालियों द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन आतंकवादियों के हाथों में चला गया जिससे सारे राष्ट्र में हत्याओं का दौर शुरू हुआ। हत्याओं से ग्राम जनता का मनोबल गिर गया था। हत्याओं का दौर पंजाब केसरी अखबार के प्रधान सम्पादक लाला जगत नारायण से शुरू हुआ। इसके बाद से ही आतंकवादियों का मनोबल बढ़ गया था और ग्राम जनता का मनोबल गिर गया था। उस समय विपक्षी पार्टियाँ भी अस्थिरता पैदा करना चाहती थी क्योंकि उनको भी सत्ता की लालसा थी। आतंकवादी खालिस्तान की मांग कर रहे थे और अकाली आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को स्वीकार करने की। दोनों ही मांगें राष्ट्रहित में नहीं थी। अमृतसर का स्वर्णमन्दिर युद्ध-स्थल बन गया था। आतंकवादी हत्याएँ करके स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश कर जाते थे।

पंजाब में श्री दरबारासिंह सरकार के इस्तीफे के बाद प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रही थी। पंजाब सरकार के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आतंकवादियों से मिले हुये थे। उस समय पंजाब में तो क्या सारे भारत में आतंक छाया हुआ था और ग्राम जनता भी भयभीत थी। आतंकवादियों ने बड़े बड़े हथियार इकट्ठे कर लिये थे। आतंकवादियों का मनोबल काफी ऊँचा हो गया था। और उस समय इस आतंकवाद का नेतृत्व संत जर्नेल्सिंह भिण्डरवाला कर रहे थे। उनके सलाहकार वर्खास्त मेजर जनरल सुवेर्गसिंह एवं भाई अमरीकसिंह थे। पंजाब की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही थी। पंजाब जल रहा था। वहाँ का व्यापार और उद्योग लगभग समाप्त हो गया था। आतंकवादियों के शिकार हिन्दू और सिख दोनों ही हुये।

आतंकवाद पर काबू पाने के लिये श्रीमती गांधी सरकार को अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में सेना भेजनी पड़ी। आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिये सेना को टैंकों तक का उपयोग करना पड़ा। आतंकवादियों ने युद्ध जैसी तैयारी कर रखी थी।

पंजाब समस्या के बारे में श्रीमती गांधी का हमेशा ही नरम रुख रहा और वे इस समस्या का समाधान भी करना चाहती थीं। मगर अकाली समय-समय पर अपनी मांगों पर स्थिर नहीं रहते थे।

जब श्रीमती गांधी ने स्वर्ण मन्दिर में सेना भेजी उसी दिन उन्होंने अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर दिये थे। श्रीमती गांधी स्वयं भी जानती थी कि मुझे भी आतंकवादियों का निशाना बनना पड़ सकता है।

वास्तव में श्रीमती गांधी आतंकवादियों की गोलियों की शिकार हुयी और उसने देश की एकता और अखण्डता के लिये स्वयं का बलिदान भी दे दिया।

श्रीमती गांधी की हत्या जिस दिन की गई उस दिन उनके पुत्र एवं वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उनको सूचना दी गई। लेकिन जब तक वे नहीं दिल्ली पहुँचे तब तक उनकी एवं राष्ट्र की माता के प्राण पखेरू उड़ चुके थे।

राष्ट्रपति विदेश में दौरे पर गये हुए थे। वे भी श्रीमती गांधी की हत्या की सूचना पाकर तुरन्त स्वदेश लौटे। संसदीय बोर्ड के निर्णय के अनुसार श्री राजीव गांधी को प्रधान मन्त्री पद की शपथ दिलायी गई। देश में दंगे भड़क उठे। अरबों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हुई। कई बेगुनाह लोग मारे गये। लेकिन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस नाजुक घड़ी में देश के सभी नागरिकों की जानमाल की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कानून और व्यवस्था को बनाये रखा।

श्रीमती गांधी की हत्या के समाचार सुनकर ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री मारग्रेट थैचर रो पड़ी थी। उस समय सारा राष्ट्र शोक में डूब गया था। राष्ट्रमाता श्रीमती गांधी का अन्तिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ 3 नवम्बर, 1984 को, उनके पुत्र प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ किया। एक सौ बीस से अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधि उनके दाह संस्कार में सम्मिलित हुये। जिनमें रूस के प्रधान मन्त्री, अमेरिका के विदेश मन्त्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक तथा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात प्रमुख थे।

देश के प्रमुख नेताओं ने अपनी श्रद्धान्जली दिवंगत नेता को अर्पित की।

श्रीमती गांधी को विपक्ष की ओर से बेहतर श्रद्धांजली देने के बाद नानाजी देशमुख ने अस्थिरता लाने के वातावरण का जायजा लेकर पंजाब के विघटनकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में कहा, “इस घड़ी में देश के सामने जो चुनौती है। उसका मुकाबला करने के लिये जात-पात, भाषा, धर्म, क्षेत्र या राजनीतिक लगाव से उठ कर सभी देशवासियों को राजीव गांधी को पूरा समर्थन और सहयोग देना चाहिये। मेरी इच्छा है और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें ऐसी आन्तरिक शक्ति और क्षमता दें कि वह अपने देशवासियों को एक सन्तुलित, मजबूत और निरपेक्ष सरकार दे सकें तथा देश को सम्पन्नता एवं वैभव की तरफ ले जा सकें।”

आतंकवाद का जन्म भारतीयकरण के अभाव में हुआ। आतंकवाद जब ही समाप्त हो सकता है, जब प्रत्येक भारतीय का भारतीयकरण हो। हमारी दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी की इच्छा भी यही थी। भारतीयकरण (Indianization) की परिभाषा कई विद्वानों ने दी। लेकिन सार्वभौम परिभाषा इस प्रकार से है। “देश के प्रति रागात्मक एवम् भावनात्मक सम्बन्ध ही भारतीयकरण है।”

आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। इसका समाधान सारे राष्ट्र आपस में मिलकर कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने में लगा हुआ है।

कुछ वर्ष पूर्व भारतीय राजनयिक रवीन्द्र हरेश्वर महात्रे की ब्रिटेन में अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई थी। यह हत्यारे काश्मीर मुक्ति संगठन से सम्बन्धित थे और पाकिस्तान के नागरिक थे। इनकी मांग यह थी कि काश्मीर मुक्ति मोर्चे के अव्यक्त मकबूल वट्ट को रिहा करो।

मकबूल वट्ट को रिहा नहीं किया गया, उसे राष्ट्र के हित में रिहा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसने भारत की सीमा में घुसकर सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर श्री अमरसिंह की हत्या कर दी थी। इस अपराध में वट्ट को फांसी की सजा सुनाई गयी थी। इस व्यक्ति पर बैंक डकैती, जेल तोड़कर भागने तथा अन्य व्यक्तियों की हत्याएँ करने के आरोप भी थे।

भारत सरकार ने अपहरणकर्त्ताओं की मांग स्वीकार नहीं की। इसलिए इन अपहरणकर्त्ताओं ने भारतीय राजनयिक रवीन्द्र महात्रे की हत्या कर दी। लेकिन इसके जवाब में भारत सरकार ने मकबूल वट्ट को तुरन्त फांसी दे दी जो कि राष्ट्र हित में तथा मानवीय दृष्टिकोण से उचित निर्णय था।

हमारी दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भी आतंकवाद से काफी चिंतित थीं। इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिये श्रीमती गांधी ने अन्तिम दम तक संघर्ष किया और स्वयं का बलिदान भी दे दिया।

श्रीमती गांधी को स्वयं की चिन्ता बिल्कुल नहीं थी। बल्कि उन्हें केवल राष्ट्र की एवं राष्ट्र की जनता की चिन्ता थी।

जिस समय ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया, उससे पहले सरकार ने अकाली दल से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। क्योंकि उस समय स्वर्ण मन्दिर पर गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का प्रशासन नाममात्र बा था। स्वर्ण मन्दिर पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। आतंकवादियों के ही आदेश चलते थे। उनके आदेशों की अवहेलना गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी कर सकती थी।

अकाली अपनी राजनीति शुरू से ही धर्म के आधार पर चला रहे थे। इन्होंने भी सिखों को उत्तेजित करने की नाकाम कोशिश की।

ब्लू स्टार ऑपरेशन से पहले सेना ने स्वर्ण मन्दिर में जितने भी लोग जमा थे उनसे आग्रह किया की आग सभी लोग बाहर आकर आत्म-समर्पण कर दें। कई व्यक्तियों ने एवं महिलाओं ने आत्म-समर्पण किया उनमें अधिकतर आतंकवादी थे।

सेना के सामने आतंकवादी अधिक समय तक मुकाबला नहीं कर सके। ब्लू स्टार ऑपरेशन में हमारे देश के कई सैनिक शहीद हुए तथा काफी संख्या में आतंकवादी भी मारे गये। आतंकवादियों से ऐसे हथियार भी बरामद किये गये जो कि विदेशों से लाये गये थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार स्वर्ण मन्दिर में सेना बहुत पहले ही भेज देती लेकिन वे कभी भी सिखों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थीं। श्रीमती गांधी पंजाब समस्या का समाधान राजनैतिक ढंग से करना चाहती थीं। लेकिन आतंकवादी न तो कोई राजनैतिक समाधान चाहते थे और न ही देश की एकता चाहते थे। सरकार ने बहुत से प्रस्ताव अकालियों के सामने रखे, उन्हें कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं था।

ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों पर

नियंत्रण हुआ। यह नियंत्रण सेना के द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन से अकाल तख्त को भी क्षति पहुँची क्योंकि सभी आतंकवादी अकाल तख्त में रुके हुये थे।

ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैलसिंह भी स्वर्ण मन्दिर गये और कुछ दिनों बाद हमारी दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी भी वहाँ गयीं।

सरकार अकाल तख्त की मरम्मत करवाना चाहती थी। अकाली अकाल तख्त को उसी हालत में रखना चाहते थे और साम्प्रदायिक भावना भड़काना चाहते थे। लेकिन अकालियों की यह योजना सफल नहीं हुई।

कार सेवा के लिये बाबा संतासिंह को आमंत्रित किया गया। बाबा ने कार सेवा का कार्य अपने पाँच सौ अनुयायियों के साथ शुरू कर दिया तथा अकाल तख्त की कार सेवा भी पूरी कर दी। कार सेवा में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया।

कार सेवा करने पर बाबा संतासिंह एवं श्री बूढासिंह (केन्द्रीय गृह मन्त्री, भारत सरकार) को सिख ग्रन्थियों ने, अकालियों एवं गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के इशारे पर तनखैया (अपराधी) घोषित कर दिया। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने तनखैया घोषित होने के बाद भी कार सेवा का कार्य जारी रखा।

वैसे सिखों और हिन्दुओं में कोई भेद नहीं है। सिख अपनी लड़की का विवाह हिन्दू के साथ करते हैं और हिन्दू भी अपनी लड़की का विवाह सिख के साथ करते हैं। यह दोनों कौम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती हैं। क्योंकि एक सिख की रिश्तेदारी किसी न किसी रूप में किसी न किसी हिन्दू के साथ जरूर है। दोनों कौमों में सद्भावना भी है।

कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सरकार किसी भी मन्दिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे से अपराधियों को निकालने के लिए, पुलिस या सेना को भेज सकती है। अगर किसी भी धार्मिक स्थान पर अपराधी छिपा हुआ है और उसको वहाँ की प्रबन्ध समिति आश्रय देती है तो वो स्थान वास्तव में धार्मिक स्थान के नाम से नहीं पुकारा जा सकता। गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने आतंकवादियों को स्वर्ण मन्दिर में संरक्षण दिया। अगर गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अपना दायित्व निभाती तो स्वर्ण मन्दिर में सेना भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न ही स्वर्ण मन्दिर में इतना खून खरावा ही होता।

हत्यारों का कोई धर्म नहीं होता और न ही हत्यारे किसी धर्म में विश्वास करते हैं। किसी भी धर्म की किसी भी पुस्तक में हत्या करने को सही नहीं माना गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की अन्तिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को, गंगोत्री की वर्षीली पहाड़ियों पर, उनके पुत्र तथा देश के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने, विसर्जित किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी की भौतिक यात्रा तो उसी समय समाप्त हो गयी थी, जिस दिन हत्यारों ने विश्व की शक्तिशाली महिला की हत्या करके जघन्य अपराध किया था, श्रीमती गांधी, देश के लिए शहीद हो गयीं लेकिन उन्होंने अपना नाम इतिहास में जरूर लिखवा लिया।

वुलेट से कभी भी देश कमजोर नहीं होता है। भारत-विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है। हमारा देश आज भी श्रीमती गांधी के आदर्शों और मूल्यों पर ही चल रहा है। अगर आगे भी इन्हीं आदर्शों और मूल्यों पर चलता रहा तो देश दिनोदिन प्रगति करेगा। इस प्रगति को कोई भी विदेशी ताकत नहीं रोक सकती है।

जनता की आवाज ने स्व० श्रीमती गांधी के पुत्र को देश का प्रधान मन्त्री चुना। जो कि देश की जनता का विवेकपूर्ण निर्णय था।

श्रीमती गांधी का जन्म भारत के लिए हुआ था। श्रीमती गांधी का जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। अगर इन्दिरा (Indira) के नाम में से आर को हटा दिया जाये तो यह नाम इण्डिया (India) हो जाता है। इण्डिया में आर जोड़ दिया जाये तो इन्दिरा हो जाता है।

श्रीमती गांधी अमर हैं, और अमर रहेंगी। इस समय एक नारा जो चलन में है वो यह है “जब तक सूरज चांद रहेगा, इन्दिरा तेरा नाम रहेगा।”

श्रीमती गांधी ने हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण श्रेय प्राप्त किया तथा देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा।

प्रधान मन्त्री जैसे उच्च पद पर वही व्यक्ति पहुँचता है जो पूर्व जन्म में तप करके आता है।

अब तक दिल्ली के तख्त को दो महिलाओं ने सुशोभित किया है, उनमें एक रजिया सुल्तान थी और दूसरी श्रीमती इन्दिरा गांधी, इन दोनों की हत्या उनके ही श्रंग रक्षकों ने की। यह दोनों विश्व इतिहास की उल्लेखनीय घटनाएँ हैं।



श्रीमती इन्दिरा गांधी का पारिवारिक जीवन

श्रीमती इन्दिरा गांधी का जन्म 19 नवम्बर, 1917 को आनन्द भवन, इलाहाबाद में हुआ। उस समय नेहरू परिवार इलाहाबाद में आनन्द भवन में रहता था।

सन् 1857 का समय काफी संघर्षपूर्ण समय था। उसी तूफानी समय में काश्मीर घाटी से उठा हुआ नेहरू परिवार दिल्ली में नहर के किनारे रहता था।

नेहरू परिवार के मुखिया श्री गंगाधर नेहरू थे। जो उस समय दिल्ली में कोतवाल थे। दिल्ली में मुगलों का शासन था। सन् 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम भी चल रहा था। लेकिन 1857 की यह क्रान्ति असफल हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में श्री गंगाधर नेहरू ने दिल्ली को छोड़ दिया और वे आगरा में जाकर के बस गये। आगरा में इस परिवार को अधिक समय रहते हुए नहीं बीता था। अचानक 34 वर्ष की उम्र में गंगाधर नेहरू का निधन हो गया। गंगाधर नेहरू के दो पुत्र थे। इन दोनों पुत्रों पर सारे परिवार का बोझ पड़ गया।

गंगाधर नेहरू के देहान्त के तीन महीने बाद विधवा इन्द्राणी ने एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मोतीलाल रखा गया।

यह वही मोतीलाल नेहरू थे जो कि हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के पिता और हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के दादा थे।

श्री मोतीलाल नेहरू बहुत ही मेधावी व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने 39 वर्ष की उम्र में आनन्द भवन को खरीद लिया था और जीवनपर्यन्त इसी भवन में रहे। श्री नेहरू विश्व के माने हुये बैरिस्टर थे। इन्होंने उस समय करोड़ों रुपये कमाये।

श्री मोतीलाल नेहरू स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े और कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गये। स्वतन्त्रता संग्राम को गति देने में श्री नेहरू का महत्त्वपूर्ण हाथ था।

पं० मोतीलाल नेहरू ने देश की जन, मन और धन से जो सेवा की हमारा देश उसे कभी भी नहीं भूल सकता है।

पं० मोतीलाल नेहरू के एक मात्र पुत्र पैदा हुये वे पं० जवाहरलाल नेहरू थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री भी चुने गये।

नेहरूजी की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हुई। बाद में हैरो पब्लिक स्कूल इंग्लैण्ड में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वे स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े और देश को आजादी दिलवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

नेहरूजी को बच्चों से बहुत अधिक प्यार था। आज भी बच्चे उन्हें "चाचा नेहरू" के नाम से पुकारते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह श्रीमती कमला के साथ हुआ था। विवाह के ठीक 23 महीने बाद नेहरूजी के घर एक सन्तान पैदा हुई। वे श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं।

आजादी के पूर्व का समय नेहरू परिवार के लिये बहुत ही संघर्षपूर्ण समय रहा। नेहरूजी अधिकतम समय जेलों में रहे। अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाये। जिस दिन इन्दिरा गांधी का जन्म हुआ, उस समय भारत को किला सरोजिनी नायडू ने कहा था—“जवाहर तुम्हारे घर में भारत की नई आत्मा का आगमन हुआ है।”

श्रीमती गांधी असाधारण व्यक्तित्व की धनी थीं। पं० नेहरू श्रीमती गांधी को बहुत अधिक प्यार करते थे। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का आधार यह है।

वंशानुक्रम (Heredity) एवं वातावरण (Environment) व्यक्तित्व के विकास (Development of Personality) का मुख्य आधार होता है।

श्रीमती गांधी का वंशानुक्रम भी ऐसा ही था, जो कि करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति का होता है और वातावरण भी ऐसा ही था।

श्रीमती गांधी ने जो कुछ सीखा वो अपने पिता पं० जवाहरलाल नेहरू और वातावरण से सीखा ।

श्रीमती गांधी की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हुयी । इसके बाद श्रीमती गांधी को पूना (महाराष्ट्र) में दाखिला दिलवा दिया गया । तीन वर्ष तक पूना में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब श्रीमती गांधी आनन्द भवन वापस लौटी तो उनके पिता पं० जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया ।

उस समय श्रीमती कमला नेहरू का स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था । श्रीमती नेहरू उस समय काफी अस्वस्थ रहने लग गयी थी । इन्दिरा जी की पढ़ाई भी अधूरी थी ।

श्रीमती गांधी को नेहरूजी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के पास शिक्षा के लिए शांति निकेतन भेज दिया ।

इन्दिरा जी ने कला, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन शांति निकेतन में किया । श्रीमती गांधी शांति निकेतन में और भी अधिक समय तक रह करके अध्ययन करना चाहती थी । लेकिन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के पास एक तार आया जिसमें लिखा था कि इन्दिरा की मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है ।

श्रीमती गांधी को तुरन्त शांति निकेतन से आनन्द भवन इलाहाबाद लौटना पड़ा । इन्दिरा जी के वापिस लौटने का दुःख सभी छात्रों, अध्यापकों एवं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी हुआ ।

श्रीमती कमला नेहरू क्षय रोग से पीड़ित थी और उस समय जवाहरलाल नेहरू जेल में थे । इन्दिरा जी को, श्रीमती कमला नेहरू के साथ स्वीटजरलैंड जाना पड़ा । इन्दिरा जी ने अपनी मां की खूब सेवा की । साथ में संघर्ष का नया अनुभव भी प्राप्त किया ।

श्रीमती कमला नेहरू की मृत्यु के एक माह पूर्व श्री जवाहरलाल नेहरू को जेल से रिहा हुए और तुरन्त अपनी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू से मिलने स्वीटजरलैंड चले गये ।

श्रीमती कमला नेहरू का देहान्त 28 फरवरी, 1936 को हुआ । इन्दिरा जी

का मन स्वीटजरलैण्ड में नहीं लग रहा था । नेहरू जी भी, श्रीमती कमला नेहरू के निधन के बाद विचलित हो गये थे । उन्हें इन्दिरा जी की शिक्षा की भी चिंता थी, वे अपनी लाड़ली को हमेशा खुश देखना चाहते थे । लेकिन नेहरू परिवार उस समय नाजुक दौर से गुजर रहा था ।

नेहरू जी हमेशा महिला शिक्षा के समर्थक रहे हैं । उन्होंने अपनी एक पुस्तक “भारत की खोज” (Discovery of India) में लिखा है कि “एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है और एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है । (A boy education is a person education and a girl education is entire family education)

श्रीमती कमला नेहरू के निधन के बाद इन्दिरा जी उदास रहने लगी । नेहरूजी ने वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए इन्दिरा जी को आक्सफोर्ड विश्व-विद्यालय में भर्ती करवा दिया । जहाँ उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया ।

श्रीमती गांधी, स्वयं भी प्लूरीसी नामक बीमारी से पीड़ित हो गयी, स्वयं को भी इलाज के लिए स्वीटजरलैण्ड जाना पड़ा ।

सन् 1939 में श्रीमती गांधी ब्रिटेन में थी । उसी समय उन्होंने अपने पिता पं० जवाहरलाल नेहरू की मदद करना तय कर लिया । उस समय नेहरू जी देश के लिए पूर्ण समर्पित थे ।

सन् 1939 में हिटलर का दबाव सारे विश्व पर था । श्रीमती गांधी ने भी उस समय स्वदेश लौटना तय कर लिया ।

जब इन्दिरा गांधी ने श्री फिरोज गांधी से विवाह करने का इरादा अपने परिवार जनों को बताया तो सारे परिवार में हड़कम्प मच गया । परिवार के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया । लेकिन इन्दिरा जी का इरादा पक्का था । पक्के इरादे के सामने सारे परिवार को हाँ कहनी पड़ी ।

श्रीमती कमला नेहरू जब बहुत गम्भीर रूप से क्षय रोग से पीड़ित थी श्री फिरोज गांधी ने उनकी बहुत सेवा सृश्रुपा की थी । इसी वजह से वह इन्दिरा जी के नजदीक आये थे । श्री फिरोज गांधी पारसी थे । इसलिए कई व्यक्तियों ने इस विवाह का विरोध भी किया । लेकिन इन्दिरा जी के पक्के निर्णय के कारण इस विवाह में किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं आयी । 26 मार्च सन् 1942 को

इन्दिरा जी का विवाह श्री फिरोज गांधी के साथ आनन्द भवन में वैदिक रीति के अनुसार सम्पन्न हुआ ।

इन्दिरा जी, विवाह के बाद आनन्द भवन छोड़कर अपने पति श्री फिरोज गांधी के साथ विदा होकर चली गयी, उन दिनों श्री गांधी भी इलाहाबाद में टाउन हाल के पास रहते थे ।

फिरोज गांधी भी स्वतन्त्रता सेनानी थे । उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया । इन्दिरा जी जैसी पत्नी पाकर के वे भी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, उस समय स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरों पर था । पति-पत्नी दोनों ही समान विचारों के थे, दोनों ने ही स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गये ।

श्री फिरोज गांधी असाधारण प्रतिभा के धनी थे । उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण कार्य किये । जिसे हमारा देश कभी भी नहीं भुला सकता है ।

सन् 1944 में राजीव गांधी ने और सन् 1946 में संजय गांधी ने, इन्दिरा जी की कोख से जन्म लिया । दोनों पुत्रों के जन्म से इन्दिरा जी एवं श्री फिरोज गांधी प्रसन्न थे ।

15 अगस्त, 1947 को, हमारा देश आजाद हुआ । जो स्वप्न हमारे देशवासियों का था, वो पूरा हुआ, अंग्रेज शासक हमेशा के लिए हमारे देश से विदा हो गये । स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू चुने गये और 26 जनवरी, 1950 को नया संविधान देश में लागू हुआ ।

श्री फिरोज गांधी भी लोक सभा के सांसद चुने गये । श्री गांधी उस समय के गतिशील सांसद थे । वे लोक सभा में अत्यधिक लोकप्रिय थे । उनके संसदीय कार्यों को विपक्षी नेता आज भी याद करते हैं । 8 सितम्बर, 1960 का दिन इन्दिरा जी के लिये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा क्योंकि इस दिन इन्दिरा जी के पति श्री फिरोज गांधी का निधन हुआ था ।

इन्दिरा जी पति के निधन से काफी विचलित हो गयी थी । उन्होंने अपने पति के निधन पर केवल इतना ही कहा "वच्चों को अब पिता की जरूरत थी ।"

श्री फिरोज गांधी ने देश के नवनिर्माण में सक्रिय सहयोग दिया । संसद में भी वह आत्म-विश्वास के साथ देश हित में, सही एवं सारगर्भित बात बोलते थे ।

फिरोज गांधी के निधन पर पं० जवाहरलाल नेहरू ने बड़े दुःख के साथ कहा था “सब कुछ कितना जल्दी और अचानक हो गया। अभी तो विल्कुल बच्चा ही था..... और यह तो मुझे आज ही मालूम हुआ कि, इतना लोकप्रिय भी था।”

सन् 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, उस समय न तो हमारी सेना ही तैयार थी और न ही सरकार। यह आक्रमण देश पर गहरा संकट था। उस समय हमारे देश के रक्षा मन्त्री श्री वी० के० कृष्णमेनन थे। इस युद्ध में चीन ने हमारे देश की लाखों कि० मी० जमीन पर अपना अधिकार भी कर लिया जो अभी भी चीन के अधिकार में है।

इस युद्ध के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू अस्वस्थ रहने लगे, उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सारा राष्ट्र भी चिन्तित रहने लगा। 27 मई, 1964 का दिन सारे राष्ट्र के लिए सबसे मनहूस दिन था। इस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था।

नेहरू जी के निधन से इन्दिरा जी को गहरा धक्का लगा फिर भी इस सदमें का धैर्य के साथ सामना किया।

इन्दिरा जी ने जीवनपर्यन्त संघर्ष किया और अकेले चलने में विश्वास भी किया। अपने दोनों लाड़लों की शिक्षा की भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था की।

श्री संजय गांधी ने शुरू में मास्ती कार बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया बाद में राज नीति में आये। श्री राजीव गांधी ने पायलेट की नौकरी कर ली।

श्री राजीव गांधी का विवाह सन् 1968 में इटली की भाग्यशाली लड़की सोनिया के साथ सम्पन्न हुआ तथा श्री संजय गांधी का विवाह कर्नल आनन्द की लड़की मेनका के साथ सन् 1974 में हुआ।

इन्दिरा जी अपने दोनों पुत्रों के विवाह से निवृत्त हो गयी थी और अपने परिवार के साथ आराम का जीवन बिता रही थी। सन् 1980 के लोक सभा चुनावों में श्री संजय गांधी भी अमेठी से चुने गये थे। 23 जून, 1981 को हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया।

श्री संजय गांधी के निधन से इन्दिरा जी को गहरा धक्का लगा। यह एक अनहोनी घटना थी।

श्री राजीव गांधी की प्रधान मन्त्री बनने की इच्छा कभी भी नहीं थी। अगर श्री गांधी की इच्छा प्रधान मन्त्री बनने की होती तो वे श्री संजय गांधी से पूर्व ही राजनीति में आ जाते। श्री गांधी ने नौकरी में रहते हुए कभी भी किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं दिया।

मगर समय और परिस्थितियां, श्री राजीव गांधी को राजनीति में ले आईं।

जब श्री राजीव गांधी ने प्रधान मन्त्री पद की शपथ ली उस समय उनकी मां की अर्थी घर पर रखी हुई थी। देश में साम्प्रदायिक तत्त्व, श्रीमती गांधी की हत्या के बाद सक्रिय हो गये थे। उस समय, प्रधान मन्त्री का पद, एक प्रकार से कांटों का ताज था।

यह कांटों का ताज श्री राजीव गांधी को पहना दिया गया। किसी भी व्यक्ति को प्रधान मन्त्री का पद, जनता की आवाज पर मिलता है।

उस समय जनता की इच्छा भी यही थी कि श्री राजीव गांधी को ही देश का प्रधान मन्त्री बनाया जावे।

जनता की आवाज को पार्लियामेन्ट्री बोर्ड के सदस्यों ने समझा और राजीव गांधी को दल का नेता चुना, इसी आधार पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने प्रधान मन्त्री पद की शपथ दिलाई। देश के नाम पहले प्रसारण में श्री गांधी ने कहा कि “श्रीमती इन्दिरा गांधी मेरी ही माता नहीं थी वल्कि सारे देश की माता थी, इन्दिरा गांधी नहीं रही, लेकिन उनकी आत्मा अमर है, भारत अमर है और भारत की आत्मा अमर है।”



श्रीमती गांधी और राजनीति

श्रीमती गांधी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो कि उस समय हमारे देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था तथा स्वतंत्रता आन्दोलन का नियंत्रण भी उसी भवन से किया जा रहा था, जहां इन्दिरा जी का जन्म हुआ था। उन दिनों अंग्रेज सरकार ने मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जुर्माना कर दिया था पर यह जुर्माना अदा नहीं किया गया था। अंग्रेज सरकार यह जुर्माना वसूल करना चाहती थी। एक दिन अंग्रेज सरकार के नौकर आनन्द भवन आये, जुमनि के बदले में, फर्नीचर तथा अन्य सामान ले जा रहे थे। उस समय घर पर न तो श्री मोतीलाल नेहरू ही मौजूद थे, और न ही श्री जवाहरलाल नेहरू। उस समय केवल घर में नन्हीं इन्दिरा जी थीं। उन्होंने अंग्रेज सरकार के नौकरों को फटकारा और कहा कि गलत जुर्माना गलत ढंग से वसूल नहीं किया जाना चाहिये।

सन् 1921 में गोवा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय इन्दिरा जी की उम्र केवल 3 वर्ष की थी। इन्दिरा जी ने भी अपने पिता के साथ उस अधिवेशन में भाग लिया। गोवा अधिवेशन में जो कार्यवाही हो रही थी उसे वे बड़े ही ध्यान से सुन रही थीं, और देख रही थीं।

इन्दिरा जी ने 12 वर्ष की उम्र में वानर सेना का गठन किया। इस सेना का कार्य आंदोलन में जल्मी लोगों की सेवा करना, भूखे आदमी को रोटी की व्यवस्था करना तथा आंदोलन के नेताओं के संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना था। उस समय वानर सेना के सदस्यों की संख्या लगभग 75,000 थी।

बीस वर्ष की उम्र में इन्दिरा जी ने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया, और वह कांग्रेस पार्टी की युवा सलाहकार कमेटी की सदस्य चुनी गई। सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन चलाया गया। आन्दोलन की गति काफी तेज थी, इस गति से अंग्रेज सरकार घबरा गयी, अंग्रेज सरकार ने दमन चक्र तेज

कर दिया तथा सभी बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। उस समय श्री फिरोज गांधी और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तेरह महीने जेल में एक साथ काटे।

15 अगस्त, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू चुने गये। इसके बाद श्रीमती गांधी अपने पिता का सहयोग करने लगी।

इन्दिरा जी का विचार राजनीति में आने का नहीं था लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री एवं श्री गोविन्द वल्लभ पन्त हमेशा श्रीमती इन्दिरा गांधी को राजनीति की तरफ ध्यान देने का सुझाव देते रहते थे। क्योंकि यह दोनों नेता जानते थे कि भारत को श्रीमती इन्दिरा गांधी की जरूरत है।

सन् 1955 में श्रीमती इन्दिरा गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्य समिति की सदस्य चुनी गयी। चुने गये सदस्यों में, सबसे अधिक मत श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही प्राप्त हुये। यह इस बात का प्रतीक था कि श्रीमती गांधी कांग्रेस पार्टी में काफी लोकप्रिय हो गई थी।

श्रीमती गांधी ने “ग्राम सम्पर्क आंदोलन” आरम्भ किया ताकि ग्रामों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जा सके। इनके उत्साह एवं लगन को देखते हुये दल के नेताओं ने इन्दिरा जी के ऊपर दल की जिम्मेदारी सौंपने की बात सोची।

सन् 1956 में श्रीमती इन्दिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। इससे पूर्व श्री मोतीलाल नेहरू एवं श्री जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये थे। इस पद पर रहकर इन्दिरा जी ने अपनी योग्यता का परिचय दिया तथा कांग्रेस संगठन को भी मजबूत किया।

1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया उस समय नागरिक केन्द्रीय सभा के चेयरमैन की हैसियत से इन्दिरा जी द्वारा किये गये कार्यों की, ग्राम जनता में प्रशंसा हुई।

27 मई, 1964 को, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, निधन के तुरन्त बाद तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी के नेता का चुनाव हुआ, उसमें श्री लालबहादुर शास्त्री को नेता चुना गया।

श्री लालबहादुर शास्त्री मंत्री मंडल में, श्रीमती इन्दिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। क्योंकि श्रीमती गांधी की कला एवं संस्कृति में विशेष रुचि थी। उन्होंने इस पद पर रहते हुये कई महत्वपूर्ण कार्य किये तथा कई योजनायें फिल्म विकास के लिये बनायीं जिससे हमारे देश में फिल्मों का विकास हुआ।

सन् 1965 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारत के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी सेनायें लाहौर तक पहुँच गयीं तथा हमारी सेना का मनोबल भी काफी ऊँचा था। इस युद्ध में हमारा देश विजयी हुआ।

सन् 1965 में हमारा देश खाद्य समस्या का सामना कर रहा था। ऐसे समय में हमारे देश के दिवंगत प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे सोमवार का उपवास रखें। उस समय हमारे देश को अनाज का आयात करना पड़ता था, देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी ने देश को एक नारा दिया “जय जवान-जय किसान” वास्तव में यह नारा सही था।

श्री लालबहादुर शास्त्री लगभग 18 महीने तक हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे। भारत-पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने के पश्चात् दोनों देशों के मध्य समझौता कराने के लिये सोवियत संघ ने पहल की तथा वार्ता के लिये दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ताशकंद में आमंत्रित किया गया।

ताशकंद वार्ता में भारत की तरफ से दल के नेता प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व वहाँ के तानाशाह राष्ट्रपति जनरल अयूब खां कर रहे थे।

ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने के कारण श्री लालबहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हो गया।

श्री लालबहादुर शास्त्री के निधन के बाद तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी-लाल नन्दा को कार्यवाहक प्रधान मंत्री पद की शपथ दिलाई गयी।

1966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी को संसद में कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया एवं प्रधान मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी । उस समय श्रीमती गांधी की उम्र केवल 48 वर्ष की थी तथा उस समय तक जितने भी प्रधान मंत्री चुने गये उनमें सबसे कम उम्र की श्रीमती गांधी ही थी ।

पं० जवाहरलाल नेहरू ने 8 अगस्त, 1933 को एक पत्र इन्दिरा जी को लिखा था “भविष्य की निर्माता तुम और तुम्हारी पीढ़ी है !”

वास्तव में नेहरू जी ने जो बात लिखी वह सही साबित हुयी । श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की लगभग 17 वर्ष तक प्रधान मंत्री रही, तथा उनकी हत्या के बाद 31 अक्टूबर, 1984 को श्री राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री पद की शपथ ग्रहण की ।



प्रधान मंत्री पद पर

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री चुनी गयी उस समय लोगों का यह ख्याल था कि वह प्रधान मंत्री पद पर असफल रहेंगी। लेकिन जब श्रीमती गांधी ने अपना कार्य शुरू किया तब वही लोग उनके कार्य करने के ढंग से दंग रह गये। क्योंकि श्रीमती गांधी असाधारण प्रतिभा की धनी थी। 11/75-8

सन् 1969 में बंगलोर (कर्नाटक) में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेतृत्व श्री मोरार जी देसाई, कामराज नाडार और एस. निजलिगप्पा कर रहे थे, दूसरे गुट का श्रीमती इन्दिरा गांधी कर रही थीं।

सन् 1969 में, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और तत्कालीन वित्तमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया, इसलिए श्रीमती गांधी ने, मोरार जी देसाई से उनके पद से इस्तीफा ले लिया।

12 जुलाई, 1969 को कांग्रेस सिंडीकेट ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिये श्री नीलम संजीव रेड्डी के नाम का प्रस्ताव किया और पार्टी हार्ड कमान ने स्वीकृति भी दे दी लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी रेड्डी के नाम पर सहमत नहीं थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी सिंडीकेट के दबाव की वजह से आजाद महसूस नहीं कर रही थी तथा सिंडीकेट से मुक्त होना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि सिंडीकेट के द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति चुन लिये गये तो सिंडीकेट का कब्जा राष्ट्रपति भवन पर ही जावेगा, ऐसी हालत में उनके द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करना सम्भव नहीं होगा।

उस समय विपक्ष के उम्मीदवार श्री वी० वी० गिरि थे, उनको सभी विपक्षी दल समर्थन दे रहे थे। श्री वी० वी० गिरि अन्तर्आत्मा की आवाज पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। श्रीमती गांधी ने अपने समर्थकों के माध्यम से यह हवा फेंका दी कि राष्ट्रपति के चुनावों में श्री गिरि को मत देवें। इस चुनाव में श्री वी० वी० गिरि हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गये। यह जीत श्री गिरि की नहीं थी; यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की जीत थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने कार्यक्रम में सफल हुयी । इस पर सिंडीकेट ने श्रीमती गांधी को कांग्रेस से निष्कापित कर दिया । कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गयी । कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं का बहुमत श्रीमती गांधी के साथ रहा । कर्नाटक सरकार जिसके मुख्य मंत्री श्री विरेन्द्र पाटिल एवं गुजरात सरकार जिसके मुख्य मंत्री श्री हितेन्द्र देसाई थे, यह दोनों सिंडीकेट के साथ रहे, बाकी सभी राज्यों की सरकारें एवं मुख्य मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ रहे ।

राष्ट्रपति के चुनाव के बाद श्रीमती गांधी सिंडीकेट के दवाव से मुक्त हो गयी थी और खुद ने अपनी योग्यता से अपनी नयी पहचान बनाली थी । वास्तव में यह श्रीमती गांधी का बहुत बड़ा करिष्मा था । जिसका लोहा सिंडीकेट एवं विपक्षी पार्टियों ने माना ।

सन् 1969 से लेकर 1971 के कालान्तर में श्रीमती गांधी ने पूर्ण योग्यता से देश का शासन चलाया तथा जनता का दिल भी जीता ।

सन् 1971 में ग्राम चुनावों की घोषणा हुयी । श्रीमती गांधी ने चुनाव में एक नारा दिया वो था “गरीबी हटाओ” और विपक्षियों का नारा था “इन्दिरा हटाओ” इस चुनाव में श्रीमती गांधी की पार्टी को शानदार सफलता मिली । इस प्रकार उन्हें भरपूर जन समर्थन प्राप्त हुआ ।

1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी की पार्टी के विरुद्ध बड़े-बड़े उद्योगपति एवं राजा महाराजाओं ने भी चुनाव लड़ा लेकिन इन सभी पूँजीपतियों को कांग्रेस के साधारण उम्मीदवारों के सामने भी हार का सामना करना पड़ा तथा विपक्ष का सफाया भी हो गया । यह चुनाव श्रीमती गांधी एवं उनकी पार्टी के लिये महत्त्वपूर्ण चुनाव था ।

चुनाव हारने के बाद श्री राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, उसका निर्णय श्रीमती इन्दिरा गांधी के विपरीत था । यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने सुनाया था । न्यायाधीश श्री सिन्हा ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया था । न्यायाधीश श्री सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी श्रीमती इन्दिरा गांधी को दिया था ।

श्रीमती गांधी ने उच्चतम न्यायालय में अपील भी की, क्योंकि यह अधिकार उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था ।

उस समय बिहार में श्री जय प्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था, तथा उस समय बिहार के मुख्य मंत्री श्री अब्दुल गफूर थे ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फंसले के बाद विपक्षी पार्टियां यह मांग कर रही थी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दें विपक्षी पार्टियों ने सारे भारत वर्ष में आन्दोलन छेड़ दिया तथा जय प्रकाश नारायण की लोक-प्रियता का गलत फायदा भी उठाया ।

कानूनी रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी इस्तीफा देने के लिये बाध्य नहीं थीं। इस्तीफा तब ही दे सकती थीं, जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता । लेकिन विपक्षी पार्टियाँ सत्ता प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए इन पार्टियों ने आन्दोलन तेज कर दिया । ऐसी परिस्थितियों में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 25 जून, 1975 को आपातकाल लागू कर दिया ।

आन्दोलनकारी नेताओं को जेल में बन्द कर दिया गया । जिनमें श्री जय प्रकाश नारायण, श्री मोरार जी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरणसिंह, श्री चन्द्र शेखर एवं बाला साहेब देवरस प्रमुख थे ।

आपातकाल में सांस्कृतिक एवं साम्प्रदायिक संगठनों पर पाबन्दी लगाई गयी। जिनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्गी और जमायते इस्लाम प्रमुख संगठन थे ।

आपातकाल में श्री संजय गांधी तूफान की तरह राजनीति में आये । उस समय न तो श्री संजय गांधी कोई मंत्री थे और न ही सांसद, लेकिन हमारे देश में चापलूस लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने श्री संजय गांधी को आसमान पर चढ़ा दिया ।

उस समय श्री संजय गांधी के सामने केन्द्रीय मंत्री भी बोना नजर आता था । श्री गांधी आपातकाल में शक्तिशाली नेता के रूप में हमारे देश में उभरे थे ।

श्री संजय गांधी भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे । वह चापलूसों के चक्कर में पूर्ण रूप से फंस गये । आपातकाल में श्री संजय गांधी का खतवा बढ़ गया था, क्योंकि उस समय सारे विपक्षी नेता जेल में थे । अखबारों के ऊपर सेंसर था ।

कोई भी अखबार सरकार और श्री संजय गांधी के विरुद्ध कुछ भी नहीं छाप सकते थे ।

आपातकाल में अनुशासन आया । बड़े-बड़े तस्करों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया तथा गुण्डा एक्ट के तहत समाज कंटकों को भी जेल में बन्द किया गया ।

सरकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय जाने लगे । सरकार का कार्य भी सुचारु रूप से चलने लगा । अष्ट अधिकारी भयभीत हो गये । उस समय आम जनता परेशान नहीं थी । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया जिससे काफी सफलता भी प्राप्त हुई ।

श्री संजय गांधी के द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम अलग से चलाया गया । इस 5 सूत्री कार्यक्रम का शोर सारे भारतवर्ष में था । कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, लेकिन इन कार्यक्रमों को लागू करने का ढंग गलत था ।

आपातकाल में परिवार नियोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया । प्रत्येक मुख्य मंत्री यह चाहता था कि लक्ष्य से अधिक परिवार नियोजन किये जावें, क्योंकि श्री संजय गांधी की नजर में अपने आपको सफल मुख्य मंत्री साबित करना चाहते थे ।

हमारे देश की जनसंख्या 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी । जनसंख्या पर नियन्त्रण करना बहुत जरूरी था । कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा सरकारी मशीनरी परिवार नियोजन के कार्य में जुट गयी । कई व्यक्तियों ने एवं महिलाओं ने परिवार नियोजन करवाया ।

सरकारी कर्मचारियों का परिवार नियोजन दवांव से भी किया गया । उस समय शिकारी की तरह पकड़ कर परिवार नियोजन किये गये । इससे लोगों में काफी आक्रोश बढ़ गया । इस आक्रोश का पता न तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को था और न ही संजय गांधी को सभी मुख्य मंत्री लक्ष्य से अधिक परिवार नियोजन करवाना चाहते थे ।

प्रेस सेंसरशिप के कारण आम जनता का अखबारों एवं रेडियो सूचनाओं पर से विश्वास उठ गया था । श्रीमती गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल भी पांच वर्ष से छः वर्ष कर दिया था ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी ने आपातकाल में जनता के सामने अच्छे से अच्छे कार्यक्रम रखे, मगर नीचे के स्तर पर लागू करने का ढंग गलत था ।

ग्राम आंदोलन के दिमाग में भय व्याप्त था । कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था । लोगों को विश्वास नहीं था कि देश में आगे चुनाव भी होंगे ।

उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती गांधी के चुनाव को वैध करार दिया एवं उच्च न्यायालय के निर्णय को नकार दिया ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सन् 1977 में ग्राम चुनाव की घोषणा कर दी । जिन लोगों को यह शक था कि श्रीमती गांधी अधिनायकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, उन्हें राहत महसूस हुयी तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी पर जो अधिनायकवाद का आरोप लगाया गया था वो भी देबुनियाद साबित हुआ ।

श्रीमती गांधी प्रजातान्त्रिक मूल्यों और आदर्शों में विश्वास करती थी । इसलिये ग्राम जनता की उन पर आस्था थी ।

1977 के ग्राम चुनाव हुये । उसमें श्रीमती गांधी की पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा । इस ग्राम चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं उनके पुत्र श्री संजय गांधी भी लोकसभा के चुनाव में हार गये ।

□

चुनाव हारने के कारण

1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारने के निम्न कारण थे—

1. श्री संजय गांधी का कांग्रेस पार्टी में शक्तिशाली नेता के रूप में उभर के आना—आगतवाज में श्री संजय गांधी कांग्रेस पार्टी के श्रीमती इन्दिरा गांधी के बाद सबसे शक्तिशाली नेता थे। लेकिन उनको आम जनता ने नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ वरिष्ठ नेता श्री संजय गांधी के व्यवहार से नाराज थे। श्री जगजीवनराम ने इसी कारण चुनावों की घोषणा के तुरन्त बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से एवं केन्द्रीय मन्त्री मण्डल से इस्तीफा दे दिया था तथा श्री राम ने प्रजातान्त्रिक कांग्रेस के नाम से पार्टी का गठन भी कर लिया था।

2. विरोधी दलों के द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण की लोकप्रियता का उपयोग—1977 के चुनावों में विरोधी दल के नेताओं ने श्री जयप्रकाश नारायण को अपना नेता मान लिया। उस समय श्री जयप्रकाश नारायण को जेल में दुर्दे की बीमारी हो गयी। इसलिये आम जनता की सहानुभूति श्री नारायण के साथ थी। इसका फायदा विरोधी दल के उम्मीदवारों को मिला।

4. आम जनता में गलत अफवाह—विरोधी दल के नेताओं ने आम जनता में गलत अफवाहें फैलायी। उसका प्रभाव भी लोकसभा के चुनाव पर पड़ा।

5. परिवार नियोजन—परिवार नियोजन से सम्बन्धित गलत अफवाहें फैलायी गयी। लेकिन जितनी अफवाहें फैलायी गयी थी उतनी गलत नसबन्दियाँ नहीं की गई थी। देश के सामने जनसंख्या वृद्धि एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। उसका समाधान राष्ट्रहित में करना आवश्यक है। अगर इसके लिये कानून भी बना दिया जावे तो उसे भी सरकार का गलत निर्णय नहीं कहा जा सकता है। लेकिन विरोधी दल के नेताओं ने परिवार नियोजन को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाकर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की पूरी कोशिश की जिसमें वे सफल भी हुये।

6. प्रेस की सेंसर—अपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसर होने के कारण सही समाचार आम जनता के पास नहीं पहुँचते थे। इसलिये उस समय आम जनता का विश्वास श्रीमती गांधी की सरकार से उठ गया था। उस समय आम व्यक्ति प्रेस की विश्वसनीयता पर शक करने लग गया था।

7. नकारात्मक मत—कांग्रेस पार्टी से नाराज लोगों ने नकारात्मक मत जनता पार्टी को दिये; जिससे कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तथा इसका फायदा जनता पार्टी को मिला।

8. सरकारी कर्मचारियों में भय—आपातकाल में सरकारी कर्मचारियों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुयी थी, क्योंकि उस समय कई सरकारी कर्मचारियों को जबरन सेवा-निवृत्त कर दिया गया था। थोड़ी गलती होने पर भी उच्च अधिकारी आपातकाल के नाम पर छोटे कर्मचारियों का शोषण करते थे। इसलिये सरकारी कर्मचारियों का रोष भी श्रीमती गांधी की सरकार के ऊपर आगया था। लेकिन इसके लिये श्रीमती गांधी स्वयं जिम्मेदार नहीं थी। इसके लिये केवल उच्च अधिकारी ही दोषी थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की पार्टी इन कारणों से चुनाव हार गयी इसलिये श्रीमती गांधी को चुनाव हारने के पश्चात् प्रधान मन्त्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

आपातकाल के अन्दर देश में अनुशासन आ गया था तथा देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गयी थी। देश मजबूत भी हुआ और देश के रचनात्मक विकास की गति में भी तेजी आयी।

विरोधी दलों ने आपातकाल में समाज विरोधी तत्त्वों के द्वारा जो गलत फायदा उठाया गया था उसके लिये भी श्रीमती इन्दिरा गांधी को एवं उनकी सरकार को दोषी ठहराया लेकिन आपातकाल में जो अच्छे काम किये गये थे उन कार्यों को प्रचारित करने में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्णरूप से असफल रहे।

श्रीमती गांधी एवं उनके पुत्र श्री सजय गांधी भी लोकसभा का चुनाव हार चुके थे। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के पश्चात् एक कमजोर संगठन नजर आने लग गया था। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता निराश हो चुके थे। कांग्रेस पार्टी के अधिकतम सांसद आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के थे क्योंकि आपातकाल का प्रभाव दक्षिणी राज्यों पर नहीं पड़ा था। बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया था। जनता पार्टी 1977 के चुनावों में भारी बहुमत से विजय हुयी।

जनता पार्टी शासन और श्रीमती इन्दिरा गांधी

1977 में जनता सरकार बनी तथा श्री मोरारजी देसाई इस सरकार के प्रधान मंत्री चुने गये। अब तक जितने भी प्रधान मंत्री बने वे उत्तर प्रदेश के थे लेकिन जनता पार्टी के शासन में श्री मोरारजी देसाई ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हुये जो कि उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं थे। श्री देसाई श्री जयप्रकाश नारायण की इच्छा से प्रधान मंत्री पद पर आसीन हुये। श्री देसाई के नेतृत्व में श्री जयप्रकाश नारायण एवं श्री आचार्य जे० बी० कृपलानी ने सभी जनता पार्टी सांसदों को गांधीजी की समाधि के सामने संगठित रहने की एवं देश के विकास की शपथ दिलाई थी।

जनता पार्टी का मंत्री मण्डल काफी खींचतान के बाद बना। कई व्यक्तियों ने मंत्री मण्डल में शामिल होने से इन्कार कर दिया जिनमें श्री नानाजी देशमुख प्रमुख थे। जनता पार्टी अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई ने प्रधान मंत्री का पद सम्भालने के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर श्री चन्द्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया।

श्री चन्द्रशेखर भी, श्री जयप्रकाश नारायण के विश्वसनीय व्यक्ति थे। इसलिए श्री नारायण ने श्री शेखर को पार्टी का अध्यक्ष चुना। सभी जनता नेताओं को श्री चन्द्रशेखर के नाम पर सहमत होना पड़ा।

जनता पार्टी में कई घटक थे तथा कई विचारधाराओं के लोग थे। सभी घटकों के सांसद भी काफी मात्रा में चुनकर आये थे। वैसे जनता के सामने जनता पार्टी केवल एक पार्टी थी। लेकिन आंतरिक रूप से इस पार्टी के अलग-अलग घटक थे और इन घटकों का नेतृत्व भी अलग अलग नेता कर रहे थे। एक घटक का नेतृत्व श्री अटलबिहारी वाजपेयी, दूसरे घटक का चौधरी चरणसिंह, तीसरे घटक का नेतृत्व श्री मोरारजी देसाई, चौथे घटक का नेतृत्व श्री जवजीवनराम कर रहे थे। इन घटकों के अलावा अन्य छोटे-छोटे घटक भी थे जिनमें समाजवादी प्रमुख थे।

जिस दिन जनता सरकार का गठन हुआ उसी दिन से रेडियो तथा अन्य प्रचार माध्यम श्रीमती इन्दिरा गांधी को रोज याद करने लगे। हर रोज रेडियो समाचार श्रीमती गांधी के लिये कुछ न कुछ जरूर बोलते थे। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी कुछ भी नहीं बोलती थी।

जनता सरकार के द्वारा शाह आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन करने के पीछे केवल यह उद्देश्य था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को कानूनी शिकंजों में फंसाकर राजनीतिक हत्या की जाय। लेकिन इस कार्य में जनता पार्टी के नेता विफल रहे।

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उनको अन्य जनता नेताओं के दबाव के आगे झुकना पड़ा तथा शाह आयोग का गठन करना पड़ा।

शाह आयोग ने लोगों के वयान लेना शुरू कर दिया। कई लोगों ने शाह आयोग के सामने वयान दिये जिनमें प्रमुख श्री मोहन छंगाणी भू० पू० स्वास्थ्य मन्त्री राजस्थान प्रमुख थे। उनका एक वयान तो इतना वचकाना था जिसकी आम जनता ने कड़े शब्दों में उस समय भी निन्दा की थी, उन्होंने इस वयान में कहा कि “देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी, युवकों का नेता श्री संजय गांधी, वच्चों का नेता राहुल गांधी और भाड़ में जावे महात्मा गांधी।”

श्री मोहन छंगाणी कांग्रेस शासनकाल में स्वास्थ्य मन्त्री रहे तथा उन्होंने अन्य विभागों का कार्य भी देखा। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी लोक सभा का चुनाव हार गयी तो श्री छंगाणी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मन्त्री पद से एवं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि यह जनता पार्टी के शासन में भी मन्त्री बनना चाहते थे।

श्रीमती गांधी को जनता सरकार ने जेल भेज दिया, श्रीमती गांधी की गिरफ्तारी के बाद लाखों लोग प्रिय नेता के हाथ मजबूत करने के लिये जेल चले गये। अधिक से अधिक लोगों की गिरफ्तारी देना इस बात का प्रतीक था कि आम जनता को श्रीमती गांधी को जेल भेजना अच्छा नहीं लगा। जेल भेजने के कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी को आम जनता में काफी लोकप्रियता मिली।

श्रीमती इन्दिरा गांधी शेरनी थी और शेरनी की तरह ही चलती थी और अकेले चलने में विश्वास करती थी।

जनता पार्टी के शासन के दौरान कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गयी। एक टुकड़े की अध्यक्षता ब्रह्मानन्द रेड्डी कर रहे थे, दूसरे टुकड़े का नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी कर रही थी।

कांग्रेस के विभाजन के बाद आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान सभाओं के चुनाव हुये जिनमें कांग्रेस (आई) को शानदार सफलता मिली। कर्नाटक में श्री देवराज अर्स को मुख्य मंत्री बनाया गया, आन्ध्र प्रदेश में डॉ. चेन्ना रेड्डी को एवं महाराष्ट्र में दोनों कांग्रेसी दलों ने श्री वसन्त दादा पाटिल को नेतृत्व सौंपा। इन तीनों राज्यों में जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं बन पाया। यह जीत इस बात का प्रतीक थी कि ग्राम जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी में अपना विश्वास प्रकट किया।

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी लोक सभा में संसद की सदस्य नहीं थी तब उन्होंने कर्नाटक राज्य की चिकमंगलूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में श्रीमती गांधी भारी बहुमत से विजयी हुयी।

जनता पार्टी के नेता यह नहीं चाहते थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी संसद सदस्य भी रहे। इन नेताओं ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी को चिकमंगलूर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर के लोकसभा में भेजा था।

जनता पार्टी के नेता उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोकसभा की सदस्यता से वंचित करके यह समझ रहे थे कि इस बात का ग्राम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वास्तव में इस निर्णय का भी ग्राम जनता पर गलत प्रभाव पड़ा।

जनता पार्टी के शासन में श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध जो भी कार्यवाही बढ़ने की भावना से की जा रही थी उसका लाभ जनता पार्टी को मिलने के बजाय श्रीमती गांधी को अधिक से अधिक लोकप्रियता मिल रही थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी कोई भी कार्य पक्के इरादे से तथा निडर होकर करती थी। जब श्रीमती गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी उस समय श्री देवराज अर्स

कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री एवं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री देवराज अर्स को यह आदेश दिया कि आप दोनों पदों में से केवल एक पद पर रहें । यह बात देवराज अर्स को स्वीकार नहीं थी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी थी । पद छोड़ने के आदेश की अवहेलना करने पर कांग्रेस पार्टी से श्री देवराज अर्स को 6 वर्ष के लिये निष्काशित कर दिया । उस समय सभी कांग्रेसी नेता यह कहते थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस नाजुक समय में विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लिया है । उस समय कर्नाटक के अधिकतम विधायक श्री अर्स के साथ थे ।

श्री अर्स कांग्रेस से निष्कासन के बाद भी कर्नाटक के मुख्य मंत्री बने रहे ।

श्री अर्स को कांग्रेस पार्टी से निकालने पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की छवि पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

जनता पार्टी में मंत्री मण्डल के गठन के साथ ही मतभेद शुरू हो गये । चौधरी चरणसिंह ने श्री मोरार जी देसाई की खुली आलोचना करना शुरू कर दी । इसलिये श्री देसाई ने, चौधरी चरणसिंह एवं श्री राज नारायण का मंत्री मण्डल से इस्तीफा भी ले लिया था ।

चौधरी चरणसिंह को दुबारा मंत्री मण्डल में उप प्रधान मंत्री के रूप में शामिल किया, दूसरा उप प्रधान मंत्री बाबू जगजीवनराम को बनाया गया ।

श्री चौधरी चरणसिंह उप प्रधान मंत्री बनने के बाद भी सन्तुष्ट नहीं थे । उन्होंने उप प्रधान मंत्री बनते ही जनता पार्टी के अन्दर तोड़ फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी, क्योंकि श्री चौधरी प्रधान मंत्री बनना चाहते थे ।

जनता पार्टी के अन्दर सांसदों ने दल बदल करना शुरू कर दिया । दल बदल करवाने में चौधरी चरणसिंह का महत्वपूर्ण हाथ था । दल बदल के कारण श्री मोरार जी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गयी, इसलिये श्री देसाई ने नैतिक मूल्यों के आधार पर प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया ।

श्री मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद जनता पार्टी के नेता

श्री जगजीवनराम चुने गये । जिन सांसदों ने दल बदल किया था, उनके नेता चौधरी चरणसिंह चुने गये ।

श्री चौधरी चरणसिंह ने राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी के समक्ष बहुमत के सांसदों की सूची प्रस्तुत की । उस समय चौधरी चरणसिंह का समर्थन दोनों कांग्रेस दलों ने किया । श्री जगजीवनराम ने भी राष्ट्रपति के समक्ष सांसदों की सूची प्रस्तुत की ।

राष्ट्रपति ने दोनों सूचियों की जांच करने के पश्चात् चौधरी चरणसिंह को प्रधान मंत्री पद की शपथ दिलाई तथा एक महीने में लोकसभा के अन्दर बहुमत सिद्ध करने के लिये भी कहा ।

कुछ समय पश्चात् कांग्रेस (आई) ने अपना समर्थन जो चौधरी चरणसिंह को दिया था वो वापिस ले लिया, इस कारण श्री चौधरी चरणसिंह संसद का सामना एक दफा भी नहीं कर सके ।

लोकसभा भंग होने के पश्चात् नये चुनावों की घोषणा हुयी । सभी दलों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा तथा अपना नेता भी घोषित कर दिया । जनता पार्टी ने अपना नेता श्री जगजीवनराम को चुना और यह नारा भी दिया कि अगले प्रधान मंत्री श्री जगजीवन राम ही होंगे ।

लोकसभा में, जो घटनाक्रम जनता शासन के दौरान चल रहे थे, उनका प्रभाव आम जनता पर अच्छा नहीं पड़ रहा था ।

जनता पार्टी को देश की जनता ने भारी बहुमत से विजयी बनाया था और यह उम्मीद की जा रही थी कि यह पार्टी देश को सम्पन्नता एवं वैभव की तरफ ले जावेगी ।

जनता पार्टी की कार्य प्रणाली को देख कर आम नागरिक संतुष्ट नहीं था । उस समय आम नागरिक यह सोचने लग गया था कि देश का शासन अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है । अगर देश का शासन इसी प्रकार से चलता रहा तो देश का विकास अवरुद्ध हो जावेगा ।



1980 में सत्ता में वापिस आने के कारण

1. जनता नेताओं में आपसी मतभेद—जनता पार्टी सत्ता में आयी तभी से इस पार्टी में मतभेद होना शुरू हो गये थे। सभी बड़े नेता अपने-अपने घटकों को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए थे। देश के विकास की तरफ इन नेताओं का ध्यान नहीं था।

2. अस्थायी शासन—जनता पार्टी देश को स्थायी शासन देने में पूर्ण रूप से असफल रही इसीलिए ढाई वर्ष के पश्चात् ही मध्यावधि चुनाव करवाने की आवश्यकता हो गई।

3. सोने की नीलामी—जनता शासन के दौरान सोने की नीलाम किया गया था। जिस देश के कुछ पूँजीपतियों ने खरीद लिया था। इसका प्रभाव भी ग्राम जनता पर अच्छा नहीं पड़ा। सोना वो ही सरकार बेचती है जो कि आर्थिक रूप से दिवालिया हो।

4. श्रीमती गांधी एवं उनके परिवारजनों के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही—जनता पार्टी के कुछ नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध बदले की भावना से कानूनी कार्यवाही कर रहे थे जिसका ग्राम जनता पर गलत प्रभाव पड़ा।

5. किसान विरोधी कृषि नीति—जनता शासन के दौरान कृषि उत्पादन का मूल्य कम हुआ तथा कृषि में काम आने वाले यन्त्रों एवं खाद के भावों में वृद्धि हुई। उत्पादन का लागत मूल्य बढ़ गया और बाजार मूल्य कम हो गया था। उस समय किसानों को गन्ना भी जलाना पड़ा था। जनता सरकार की किसान विरोधी नीति होने के कारण देश का ग्राम किसान दुःखी था।

6. विकास की दर में कमी—जनता पार्टी ने जब शासन संभाला, उस समय देश तेजी से विकास कर रहा था। उत्पादन भी बढ़ रहा था तथा आर्थिक

रूप से भी मजबूत हो रहा था। लेकिन जनता पार्टी जब सत्ता में आयी तो दिनोदिन विकास की दर कम होती गयी। इसका सबसे बड़ा कारण जनता नेताओं का आपसी मतभेद था।

7. कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असफल—जनता पार्टी सरकार देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में पूर्ण रूप से असफल रही। कारखानों में तालाबन्दी, हड़ताल तथा सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी कमी आयी। इस कारण भी देश की जनता ने फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश का नेता चुना।

8. जनता पार्टी के नेताओं द्वारा चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उनको पूरा न करना—1977 के चुनाव में जनता पार्टी के नेताओं ने देश की जनता से विकास के लिए कई तरह के वादे किए थे। मगर जो वादे किये गये थे वो पूरे नहीं किए गये।

9. मती गांधी की लोकप्रियता—जनता पार्टी के नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की लोकप्रियता समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए काफी प्रयत्न भी किए गये। लेकिन इस कार्य में वे सफल नहीं हुए वल्कि श्रीमती गांधी के विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जाती उसका लाभ जनता पार्टी को नहीं मिल करके श्रीमती इन्दिरा गांधी को मिल रहा था।

10. राजनीतिक महत्वाकांक्षा—जनता पार्टी में शुरू से ही प्रधान मन्त्री के पद के लिए कई दावेदार थे। कोई एक नेता नहीं था वल्कि सभी घटकों के नेता थे। सभी घटक एक विचार के नहीं थे। इसी कारण जनता पार्टी का विभाजन हुआ। विभाजन होने के पश्चात् श्री चौधरी चरणसिंह देश के प्रधान मन्त्री बने लेकिन चौधरी चरणसिंह भी इस पद पर अधिक समय तक नहीं रह सके। जनता पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की ही वजह से दो टुकड़ों में विभाजित हुई।

11. काल पात्र की खुदाई—जनता पार्टी शासन के दौरान लाल किले के पास काल पात्र की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। जिसमें लाखों रुपये खर्च हुये जिसका कोई औचित्य नहीं था। इसका भी आम जनता के ऊपर गलत प्रभाव पड़ा।

12. श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोकसभा की सदस्यता से वंचित करना—जब श्रीमती इन्दिरा गांधी लोकसभा से बाहर थी, उस समय उन्होंने 'चिकमंगलूर' लोकसभा से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में वे भारी बहुमत से विजयी हुई थी। यह विजय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी नहीं लगी, इसलिए इन नेताओं ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी को संसद की सदस्यता से वंचित करने का कार्य एक तरह से लोकतन्त्र की हत्या करने के समान था। इस बात का प्रभाव आम जनता पर अच्छा नहीं पड़ा बल्कि इससे जनता पार्टी के नेताओं की छवि को धक्का लगा।

13. सांसदों से जनता का विश्वास उठ जाना—जनता पार्टी जब सत्ता में थी उस समय श्री चौधरी चरणसिंह के नेतृत्व में 80-90 सांसदों ने दल बदल किया था। इसी कारण से श्री मोरारजी देसाई को प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देश की जनता ने जनता पार्टी को पांच साल के लिये सत्ता सौंपी थी लेकिन पद लोलुपता के कारण यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। इसका आम जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा और उस समय के चुने हुए सांसदों पर से जनता का विश्वास उठ गया। लोगों के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि देश का शासन इन परिस्थितियों में श्रीमती इन्दिरा गांधी के अलावा कोई नहीं चला सकता है। इसी कारण से देश की जनता ने सन् 1980 में लोकसभा चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गांधी की पार्टी को फिर से विजयी बनाया और राष्ट्र की वागडोर उनके हाथों में सौंप दी। इस चुनाव में जनता पार्टी को एवं प्रधान-मन्त्री श्री चरणसिंह चौधरी की पार्टी को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा।

□

श्रीमती गांधी एवं उनकी उपलब्धियां

आर्थिक क्षेत्र— श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश को आर्थिक क्षेत्र में सुजवूरी प्रदान की तथा इसका फायदा आम जनता को मिला। श्रीमती गांधी की आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी समाज की नीति रही। इसी नीति के आधार पर सरकार ने कार्य किये। इससे देश में प्रति व्यक्ति औसत आय में भी वृद्धि हुई।

श्रीमती गांधी ने देश के आर्थिक विकास में गति देने के लिए जो कदम उठाये उसकी आम जनता ने तारीफ की तथा इसी कारण से श्रीमती गांधी आम जनता में लोकप्रिय हुई।

श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा आर्थिक क्षेत्र में आम जनता के कल्याण के लिए जो कदम उठाये गए वे निम्नलिखित हैं—

1. **बैंकों का राष्ट्रीयकरण—**श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सत्ता में आने के कुछ वर्षों बाद देश की जनता के कल्याण के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन बैंकों का प्रबन्ध सार्वजनिक कम्पनियों के द्वारा किया जाता था। इन सार्वजनिक कम्पनियों पर बड़े घरानों का कब्जा था। इसलिए यह बैंक राष्ट्रीयकरण से पूर्व जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे थे। इन बैंकों में आम जनता का धन जमा था और उसका फायदा देश के बड़े बड़े उद्योगपति उठा रहे थे।

बैंक राष्ट्रीयकरण नीति से लाभ अधिक था तथा हानि कम थी। बैंक के राष्ट्रीयकरण से जो लाभ हुए वे निम्नलिखित हैं—

1. देश की जनता का धन देश के ही आम व्यक्ति को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया गया जिससे गरीब तबके के लोगों को रोजगार के साधन सुलभ

हो सके। राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस धन का उपयोग बड़े-बड़े उद्योगपति एवं बड़े-बड़े व्यापारी ही करते थे।

2. कृषि उत्पादन में वृद्धि—राष्ट्रीयकरण से पूर्व यह बैंक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण नहीं देते थे, अगर देते भी थे तो बहुत ही कम मात्रा में, इस कारण से कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर बहुत कम थी। क्योंकि किसानों के पास कृषि संयंत्र, खाद एवं बीज खरीदने के लिए धन का अभाव था। धन के अभाव की पूर्ति किसान देशी बैंकर्स से उधार लेकर करता था।

देशी बैंकर्स की व्याज दर काफी ऊँची होती थी। इसलिए किसान हमेशा देशी बैंकर्स के चंगुल में फंसा रहता था। देशी बैंकर्स दिन-दूनी रात-चौगुनी गति के हिसाब से गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। इस कारण से किसान गरीब होता जा रहा था और देशी बैंकर्स गरीब किसानों का शोषण करके और अधिक धनवान बन रहे थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आम किसान को कृषि संयंत्र एवं उर्वरक खरीदने के लिए कम व्याज पर धन उधार मिलने लगा। जिससे किसानों को काफी राहत महसूस हुई। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। जिससे किसानों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ।

बैंकों से ऋण मिलने के कारण किसान देशी बैंकर्स के चंगुल से भी मुक्त होने लगे और आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने लगे। बैंक राष्ट्रीयकरण के कारण आम किसान को जो फायदा हुआ है वे हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीति की देन थी। जिसे हमारे देश के किसान कभी भी नहीं भूल सकते हैं।

3. समाजवादी समाज की स्थापना—बैंक राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों में जमा धन का उपयोग बड़े-बड़े उद्योगपति एवं बड़े-बड़े व्यापारी करते थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद इस धन का उपयोग सभी वर्ग के लोग करने लगे। छोटे छोटे उद्योगों का विकास हुआ जिससे आम व्यक्ति को स्वयं का रोजगार मिलने का अवसर मिला यह सब राष्ट्रीयकरण की ही देन है। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता तो गरीब अधिक गरीब होता हुआ चला जाता और अमीर अधिक अमीर हो जाता। बैंक राष्ट्रीयकरण ने गरीब और अमीर के बीच की खाई को बड़ने से रोका। इसलिए बैंक राष्ट्रीयकरण समाजवादी समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके यह

सिद्ध कर दिया कि उनकी सरकार का समाजवादी समाज में पूर्ण विश्वास है ।

बैंक राष्ट्रीयकरण के दोष

1. बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी—राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन बैंकों का प्रबन्ध एवं संचालन सार्वजनिक कम्पनियों के द्वारा किया जाता था । राष्ट्रीयकरण से पूर्व कर्मचारियों में यह भय बना रहता था कि अगर ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल दिये जावेंगे । इसलिए कर्मचारी अपनी नौकरी का सही अंजाम देता था । लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद कर्मचारी अपने कार्य के प्रति सही अंजाम नहीं देते हैं । क्योंकि कर्मचारी जानते हैं कि बैंक की शाखा घाटे में रहेगी तो भी उनके वेतन और नौकरी को कोई खतरा नहीं है ।

बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक कर्मचारियों की कार्यक्षमता में निश्चित रूप से कमी आयी है । कार्यक्षमता की कमी के लिए बैंक कर्मचारी ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि बैंकों के बड़े अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो उनसे काम लेने में असफल हैं ।

बैंक कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके ।

2. बैंकों में भ्रष्टाचार—बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में भ्रष्टाचार पनपा है । भ्रष्टाचार के लिए सरकार दोषी नहीं है बल्कि रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले अधिकारी इसके लिए दोषी हैं । भ्रष्टाचार एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है जिसका समाधान कोई भी देश नहीं कर पाया है । भ्रष्टाचार तो साम्यवादी देश रूस और चीन में भी भयंकर रूप से व्याप्त है ।

भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार ने समय समय पर कदम भी उठाये लेकिन अधिक सफलता नहीं मिली ।

हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री ने भी सर्वप्रथम बैंकों में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ दिनों पहले बैंकों के भ्रष्ट अध्यक्ष एवं प्रबन्धक संचालकों को बर्खास्त करके महत्वपूर्ण कदम उठाया है । यह कदम ऊपर के स्तर के थे । नीचे के स्तर से भी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए ।

जिससे कि देश के आम नागरिकों को बैंक राष्ट्रीयकरण का फायदा मिले । जिससे हमारी दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का समाजवादी समाज का जो सपना था वो साकार हो सके और देश विकास की ओर अग्रसर हो सके ।

2. राजा महाराजाओं का प्रिविपर्स बन्द करना—जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में कई रियासतें थी और उनके कई राजा थे । जब इन रियासतों का विलीनीकरण हुआ तब इनके बदले में राजा महाराजाओं को प्रिविपर्स देना भी तय हुआ था । प्रिविपर्स की मात्रा इन राजाओं की हैसियत के अनुसार होती थी ।

राजाओं को प्रिविपर्स की गशि प्रति वर्ष सरकार के द्वारा दी जाती थी । देश की आजादी के बाद से लेकर सन् 1970 तक राजाओं को प्रिविपर्स दिया गया । प्रिविपर्स ब्रिटेन के राजा और रानी को भी दिया जाता था । सन् 1970 में जब हमारी दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में देश का शासन था उस समय राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मन्त्री मण्डल की सलाह पर राजाओं का प्रिविपर्स बन्द करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था ।

इस अध्यादेश के विरुद्ध राजा-महाराजाओं ने एक याचिका उच्चतम न्यायालय में पेश की जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर ली । प्रिविपर्स के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने राजा महाराजाओं के पक्ष में फैसला सुना दिया । प्रिविपर्स सम्बन्धी मुकदमें का फैसला कानून में तकनीकी कमी के कारण सरकार के विरुद्ध हुआ ।

प्रिविपर्स सम्बन्धी मुकदमें का फैसला जब सरकार के निर्णय के विरुद्ध हुआ तब उसके कुछ समय पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने प्रिविपर्स बन्द करने का कानून बना दिया । जिससे कि राजाओं का प्रिविपर्स एवं अन्य सुविधायें जो कि सरकार के द्वारा दी जाती थी वो बन्द कर दी गयी ।

प्रिविपर्स एवं अन्य सुविधाओं के नाम पर राजा महाराजाओं के ऊपर सरकार का तथा देश की जनता का जो करोड़ों रुपया खर्च होता था उससे हमारे देश की दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी का समाजवादी समाज की नीति के कारण मुक्ति मिली ।

प्रिविपर्स एवं अन्य सुविधाओं के नाम पर जो धन खर्च होता था वो धन

हमारे देश की विकास योजनाओं में खर्च होने लगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राजा महाराजाओं का प्रिविपर्स वन्द करके समाजवादी समाज की रचना में जो महत्वपूर्ण आर्थिक कदम उठाया था उसे हमारे देश की जनता कभी नहीं भूल सकती है।

3. विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण—हमारे देश में तेल का व्यापार कुछ विदेशी कम्पनियों के द्वारा किया जाता था। इस व्यापार में जो कुछ भी लाभ होता था वो लाभ यह विदेशी कम्पनियां अपने देश में ले जाती थी। इन कम्पनियों से देश को कोई फायदा नहीं होता था बल्कि यह कम्पनियां हमारे देश के आर्थिक ढाँचे को भी कमजोर कर रही थी। इसलिए प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने सभी विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा समस्त तेल का व्यापार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जो कि देश हित में बहुत ही अच्छा निर्णय था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन बड़ी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके हमारे प्रथम प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जो समाजवादी समाज का सपना था उसको साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

वर्तमान में तेल का व्यवसाय हमारी सरकार के हाथ में है और इन विदेशी कम्पनियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

4. 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम—प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की गरीब जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम चलाया। जिसका फायदा देश के ग्राम नागरिक को मिला।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम जन-कल्याण के लिये जनता के सामने रखा। उसकी ग्राम जनता ने तारीफ की तथा यह कार्यक्रम जन-कल्याण के लिए अब तक जो भी कार्यक्रम रखे गये उनमें सबसे अच्छा कार्यक्रम था।

बीस सूत्री कार्यक्रम आपातकाल में चलाया गया था। लेकिन 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने से इस बीस सूत्री कार्यक्रम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही जनता पार्टी ने देश हित में बीस सूत्री कार्यक्रम लागू करने की कोशिश की। इस कारण बीस सूत्री कार्यक्रम का लाभ ग्राम जनता को पूर्णरूप से नहीं मिल पाया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश की जनता ने सन् 1980 में दुबारा प्रधान मन्त्री चुना। सत्ता में आने के तुरन्त बाद राष्ट्र हित में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू किया।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का लाभ फिर से आम जनता को मिलने लगा। जिससे आम जनता के जीवन-स्तर में सुधार हुआ।

बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू करके प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सारे विश्व को यह बता दिया कि हमारी पार्टी का कार्यक्रम समाजवादी समाज की रचना है। उस पर हम आज भी अडिग हैं और आने वाले समय में भी इसके ऊपर अमल करेंगे। जिससे देश की जनता का कल्याण हो सके और देश दिन दूनी और रात चौगुनी गति से विकास कर सके।

5. स्वरोजगार योजना—श्रीमती इन्दिरा गांधी सन् 1980 में जब दुबारा सत्ता में आयीं उस समय हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफी थी। सभी शिक्षित बेरोजगारों को सरकार नौकरी भी नहीं दे सकती थी। लेकिन इन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की थी। इसलिए इन्दिरा सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों की भलाई के लिए एवं उनको रोजगार दिलाने के लिए स्वरोजगार योजना चलायी। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण कोई भी युवक पच्चीस हजार रुपये तक का ऋण ले सकता है।

स्वरोजगार योजना के तहत ऋण देने का तरीका काफी सरल है। क्योंकि यह ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाता है। इस ऋण की राशि से शिक्षित बेरोजगार अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है जो उसको पसन्द हो।

स्वरोजगार योजना के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा ऋण के ऊपर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

स्वरोजगार योजना का फायदा आम शिक्षित बेरोजगार को मिला।

आज भी हमारे देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्वरोजगार योजना चल रही है। इस योजना के कारण कई बेरोजगार नवयुवकों के अपने स्वयं के व्यवसाय

लग गए हैं और आज वे आत्म-निर्भर होकर स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

स्वरोजगार योजना का जो कदम उठाया गया है वो समाजवादी समाज की रचना में एक महत्वपूर्ण कदम है । जिसे हमारे देश के नवयुवक नहीं भूल सकते हैं ।

6. सहकारिता का विकास—आजादी से पूर्व हमारे देश में सहकारिता नाम की कोई संस्था नहीं थी । देश आजाद होने के बाद हमारे प्रथम प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता के महत्त्व को समझा और देश में सहकारी समितियां स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया ।

सहकारी समितियों में सब मिल कर के कार्य करते हैं और उसका फायदा भी सभी सदस्य मिलकर उठाते हैं ।

सहकारी समितियों के विकास से ही देश में समाजवादी समाज की स्थापना हो सकती है ।

आज हमारे देश में सहकारिता के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

वर्तमान समय में कई प्रकार की सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं । उसमें औद्योगिक सहकारी समितियां, कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियां एवं उपभोक्ता सहकारी समितियां प्रमुख हैं ।

सहकारी समितियों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवा का उद्देश्य होता है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सहकारिता के सम्बन्ध में जो नीति रही वो सहकारिता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नीति रही है ।

आज हमारे देश में ग्राम स्तर पर एवं शहरों में भी लगभग सभी जगह सहकारी समितियां औद्योगिक सहकारी समितियां एवं उपभोक्ता सहकारी संघ

स्थापित हो चुके हैं। यह समितियाँ और सहकारी उपभोक्ता संघ अपने अपने स्थान पर सही कार्य कर रहे हैं।

हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की जनता के समक्ष जो सहकारिता की नीति रखी उसका फायदा आम किसान, मजदूर एवं उपभोक्ता को मिला।

कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को समय समय पर खाद और बीज उधार दिया जाता है। कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद रुपया भी उधार दिया जाता है।

सहकारी समितियों के विकास से किसानों को राहत महसूस हुयी। वे देशी बैंकर्स के चंगुल से मुक्त होने लगे।

सहकारिता से ज्यादा फायदा छोटे किसानों को हुआ। कृषि उत्पादन बढ़ने से आम किसान की वापिक आय में भी वृद्धि हुयी, जिससे आम किसान के जीवन स्तर में सुधार हुआ। तथा किसान अपने आप में सुखी महसूस करने लगा। सहकारिता से सभी वर्गों को लाभ हुआ। समाजवादी समाज की रचना में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

हमारे देश में सहकारिता ने जिस प्रकार से विकास किया उसका श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार की अच्छी नीतियों को जाता है। जिन्होंने समय समय पर सहकारिता का विकास करने के लिए म त्वपूर्ण कदम उठाये।

अगर सहकारिता का विकास तेज गति से नहीं किया जाता तो हमारा देश भी पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की तरफ मूड़ जाता। गरीब आदमी और भी अधिक गरीब हो जाता और अमीर और भी अधिक अमीर हो जाता। इस समय हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का बोलवाला है। कई उद्योग सहकारिता के माध्यम से चल रहे हैं, कई उद्योग पूंजीपतियों के नियंत्रण में चल रहे हैं, तथा कई उद्योगों का नियन्त्रण सरकार के द्वारा किया जाता है।

देश हित में सहकारिता का विकास तेजी से किया जाना चाहिये। जिससे हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी का सपना साकार हो सके।

7. भूमि-हीनों को भूमि—श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार ने कृषि भूमि की सीमा निर्धारण करके भूमिहीनों को भूमि आवंटित की, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। जिन लोगों के पास अधिक भूमि थी उन लोगों से सरकार ने सीलिंग कानून पास करके भूमि लेकर भूमि हीनों को बांटी। जो कि समाजवादी समाज की रचना में एक महत्वपूर्ण कदम है।

8. आयकर में छूट—श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार ने मध्यम आय वर्ग के लोगों को आयकर में छूट दी। जिससे मध्यम आय वर्ग के लोग अपना जीवन स्तर सुधार सकें। यह छूट समय समय पर दी गई थी। जिससे मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत महसूस हुयी।

9. कमजोर आय वर्ग के लोगों को मकान—जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है और जो कमजोर आय वर्ग में आते थे उन लोगों को समय समय पर रहने के लिए कम कीमत पर मकान एवं भूमि उपलब्ध करायी गयी। इस कार्यक्रम से कमजोर आय वर्ग के लोगों ने राहत महसूस की।

10. बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन—हमारे देश में बंधुआ मजदूर प्रथा का प्रचलन था। बड़े किसान अपने यहां बंधुआ मजदूर रखते थे और उनके साथ गुलामों का सा व्यवहार करते थे। इन मजदूरों का शोषण बड़े किसानों द्वारा किया जाता था। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने बंधुआ मजदूर प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर इस प्रथा का उन्मूलन किया और जो लोग बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे उनको इस शोषण से मुक्ति दिलवायी। न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा समय समय पर तय की जाती है। इस प्रथा के उन्मूलन से बेगार प्रथा का अन्त हुआ। सभी बंधुआ मजदूर स्वतंत्र भारत में एक स्वतन्त्र नागरिक के रूप में जीने लगे। जिन लोगों ने बंधुआ मजदूर प्रथा का गैर कानूनी ठहराने के बाद भी बंधुआ मजदूर रखे उन लोगों पर सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई।

11. कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा—श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों एवं निजी कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जिससे कि कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा हुयी। सभी प्रकार के कर्मचारी अपनी नौकरी को सुरक्षित समझने लगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाये तथा शोषण से मुक्ति दिलाई ।

वर्तमान समय में चाहे राज्य कर्मचारी हों तथा कारखाने में काम करने वाले मजदूर हों । अब सभी अपनी नौकरी को सुरक्षित समझते हैं । श्रीमती गांधी सरकार ने देश के मजदूरों के कल्याण के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जिसका फायदा देश के आम मजदूर एवं कर्मचारी को मिला ।

कोई भी नियोक्ता (Employer) अपने किसी भी कर्मचारी की मजदूरी का गलत फायदा नहीं उठा सकता है । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कर्मचारियों के हित के लिए जो कार्य किये उसे हमारे देश का कोई भी कर्मचारी नहीं भूल सकता है ।

नौकरी में सुरक्षा की भावना होने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है जिससे देश में सभी प्रकार की सेवाओं का कार्य सही ढंग से होने लगा है ।

12. मुद्रास्फीति में नियंत्रण—श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में मुद्रास्फीति बढ़ने की दर अन्य देशों की तुलना में कम रही । जो कि श्रीमती गांधी की अच्छी आर्थिक नीति की देन थी ।

□

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में

जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय देश के सामने अनाज की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी। हमारे देश को अनाज के मामले में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय देश की आवादी भी कम थी, फिर भी अनाज विदेशों से आयात करना पड़ता था।

कृषि प्रधान देश कहलाकर भी जो देश अनाज के मामले में ही आत्म-निर्भर नहीं हो वो देश क्या विकास कर सकता है। हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अनाज समस्या का समाधान करने के लिए कारगर कदम उठाये मगर फिर भी विदेशों से अनाज का आयात करना पड़ता था, उसके बदले में हमारे देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता था। इस कारण से देश के विकास की गति भी धीमी थी।

पं० जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सन् 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर सम्भाली। इसी कालान्तर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ। जो समस्या पं० जवाहरलाल नेहरू के सामने थी, वो ही समस्या शास्त्री जी के सामने थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने जो समस्याएँ थी उन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने एक नारा दिया था “जय जवान—जय किसान”।

उस समय हमारा देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा था एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध लड़ा जा रहा था दूसरी तरफ देश की जनता के लिए अनाज नहीं था।

श्री लाल बहादुर शास्त्री एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने देश की जनता से एक अपील की, जिसमें यह कह गया कि देश के हर नागरिक को सोमवार का उपवास रखना चाहिए।

श्री लाल बहादुर शास्त्री की इस मामिक अपील का प्रभाव आम नागरिकों पर अच्छा पड़ा। शास्त्री जी ने कहा कि हम भूखे रह सकते हैं मगर विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश पर 18 महीने तक शासन किया। श्री शास्त्री जी के कार्यकाल में सन् 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। सैनिक वड़ी बहादुरी से लड़े और लाहौर तक जा पहुँचे। सारे देश में एक नई लहर दौड़ गई थी। उन्हीं दिनों श्री शास्त्री ने एक नारा दिया “जय जवान—जय किसान” जो पूर्णरूप से सफल रहा।

भारत और पाकिस्तान के बीच जो कटुता पैदा हो गई थी उसे सोवियत संघ वातचीत के जरिये हल करवाना चाहता था। इसलिए भारत की तरफ से श्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में सन् 1966 में एक शिष्ट मण्डल सोवियत संघ की यात्रा पर गया, जहाँ पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ भी वार्ता के लिए पहुँचे। यह वार्ता ताशकन्द में हुई, जहाँ पर शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन से प्रधान मन्त्री का पद रिक्त हुआ उस पद पर स्थाई रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी आसीन हुईं। जो समस्या श्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष थी वो ही समस्या शास्त्री जी के समक्ष थी। शास्त्री जी इस समस्या का समाधान अल्प समय में नहीं कर पाये। खाद्य समस्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए एक चुनौती थी। जिसे पूरा करना उनका पहला कर्तव्य था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रधान मन्त्री पद की बागडोर सम्भालने के बाद अनाज का उत्पादन बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य रहा, जिसे प्राप्त करने के लिए कारगर कदम उठाये गए, जिसमें उनको सफलता मिली तथा देश भी अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो नहीं बना वल्कि उनकी मृत्यु तक अनाज निर्यात करने वाले देशों में एक देश बन गया।

अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाये वो निम्न लिखित थे—

1. बैंकों का राष्ट्रीयकरण—बैंक राष्ट्रीयकरण से पूर्व किसानों को बैंकों से ऋण नहीं मिलता था और अगर मिलता भी था तो बहुत ही कम मात्रा में मिलता था।

राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ऋण मिलने लगा । जिससे किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे तथा कृषि में काम आने वाले अन्य यन्त्र भी खरीदे । इन सब उपायों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई ।

2. कृषि भूमि के लिए हदबन्दी कानून—कृषि भूमि के हदबन्दी कानून से पूर्व कई राजा महाराजाओं एवं सेठ साहूकारों के पास तथा बड़े किसानों के पास भूमि तो अधिक थी मगर वह लोग पूरी भूमि पर खेती नहीं कर पाते थे । इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार ने हदबन्दी कानून बना करके कृषि भूमि की सीमा निर्धारित कर दी । इस सीमा से अधिक कोई भी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं रख सकता है ।

कृषि भूमि हदबन्दी कानून लागू होने के कारण जिन लोगों के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि थी वो भूमि सरकार ने अपने कब्जे में लेकर भूमिहीनों को बांट दी । जिससे देश की समस्त भूमि पर उत्पादन होने लगा एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई ।

3. रासायनिक खाद के उत्पादन में वृद्धि—हमारे देश में केवल गोबर के खाद को ही कृषि भूमि में उपयोग किया जाता था जो कि समस्त कृषि भूमि के लिए कम था, इसलिए रासायनिक खाद की आवश्यकता महसूस हुई ।

खाद की आवश्यकता को देखते हुए, इसकी पूर्ति के लिए देश में बड़े बड़े रासायनिक खाद के कारखाने लगाये गये एवं विदेशों से खाद आयात भी किया गया ।

रासायनिक खाद के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई ।

4. अच्छे बीज का उपयोग—सरकार ने अच्छे बीज का उत्पादन किया अब अच्छे बीज को किसान अपनी भूमि में काम में लेने लगे । जिससे प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई । अच्छे बीज के प्रयोग से कृषि उत्पादन की किस्म में भी आमूल चूल परिवर्तन आया ।

5. सिंचाई के साधनों का विकास—सरकार ने कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध बनवाये । नल कूप लगवाने तथा किसानों को कुये खोदने के लिए प्रेरित किया गया । सिंचाई के साधनों के विकास के कारण जिस भूमि पर

पहले एक फसल पैदा की जाती थी। उसी भूमि पर दो और तीन फसलें पैदा होने लगी।

6. विद्युत् उत्पादन में वृद्धि—श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में विद्युत् उत्पादन में भी वृद्धि हुई। जिससे गांव गांव में विजली पहुंची। खेतों में पानी की पूर्ति विजली के माध्यम से होने लगी, जिससे अधिक भूमि सिंचित होने लगी। विद्युत् का कृषि में उपयोग होने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

7. फसल की बीमारियों से रक्षा—जब फसल में बीमारियां फैलती हैं तो उत्पादन में भी कमी आती है। फसल को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार के द्वारा दवाइयों का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। इन दवाइयों के प्रयोग से फसल की बीमारी पर तुरन्त काबू पा लिया जाता है। इस कारण से भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।



औद्योगिक क्षेत्र में

सन् 1947 से पूर्व हमारे देश का औद्योगिक विकास नाम मात्र का भी नहीं हुआ था। हमारे देश से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाया जाता था और उसके बदले पक्के माल की पूर्ति ब्रिटेन के शासकों के द्वारा की जाती थी। औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ था।

देश के आजाद होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्योगों का विकास करने के लिए सोचा और उसके लिए वातावरण भी तैयार किया तथा देश में बड़े उद्योग धन्वे स्थापित किये गये।

नेहरू जी की मान्यता थी कि औद्योगिक वस्तु का उत्पादन अगर देश में किया जावेगा तो देश के नागरिकों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। नेहरू जी के शासनकाल में हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किये गये। मगर उनके अथक प्रयत्नों के बावजूद भी औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश आत्म-निर्भर नहीं बन सका। क्योंकि उस समय हमारे देश के सामने उद्योगों का विकास करने में कई प्रकार की कठिनाइयां थीं।

श्रीमती गांधी भी अपने पिता श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई औद्योगिक नीति पर चली जिसमें श्रीमती गांधी को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

आज हमारा देश औद्योगिक उत्पादन में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

श्रीमती गांधी ने उद्योगों का विकास करने के लिए कई प्रकार के कारगर कदम उठाये जिससे औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश आत्म-निर्भर हो गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की औद्योगिक नीति के कारण आज हमारा देश कई प्रकार की औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करने लग गया है।

श्रीमती गांधी के द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जो कारगर कदम उठाये गए वे निम्नलिखित हैं:—

1. बड़े उद्योग घन्वे स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा ऋण की व्यवस्था की गई।
2. विदेशों से आने वाली औद्योगिक वस्तुओं पर अधिक कर लगाये गये जिससे हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन का मूल्य विदेशी उत्पादन की तुलना में कम हो गया। माल सस्ता होने के कारण देश की जनता स्वदेशी माल खरीदने लगी।
3. जो उद्योगपति अपने माल को विदेशों में निर्यात करते हैं उन्हें विशेष छूट दी गई।
4. औद्योगिक उत्पादन की किस्म सुधारने के लिए कई प्रकार के शोध केन्द्र खोले गये।
5. छोटे उद्योगों को विकास करने के लिए कई प्रकार के बैंक एवं निगमों की स्थापना की गई जिससे देश का ग्राम नागरिक स्वयं का उद्योग लगा सके।
6. कुटीर उद्योगों से उत्पादित माल को कर-मुक्त किया गया।
7. जिस वस्तु का उत्पादन बढ़ाना हो। उस वस्तु पर सरकार के द्वारा कर कम कर दिया गया। जिससे उस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई।
8. शक्ति के स्रोतों का विकास किया गया।

समाचार माध्यमों के क्षेत्र में

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने समाचार माध्यमों का विकास करने के लिए कारगर कदम उठाये जिससे ग्राम आदमी इनका उपयोग कर सके एवं ग्रनीप-चारिक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए जो कदम उठाये गये वे अग्रलिखित हैं:—

1. रेडियो लाइसेन्स का शुल्क माफ किया गया:—श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार के द्वारा रेडियो लाइसेन्स के शुल्क में छूट देकर एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया । जिससे यह लाभ हुआ कि ग्राम व्यक्ति रेडियो का उपयोग करने लगा । रेडियो के उत्पादन में भारी वृद्धि हुयी तथा कम कीमत पर ग्राम व्यक्ति को उपलब्ध होने लगा ।

2. टेलीविजन का उत्पादन:—विदेशों में तो टेलीविजन का प्रसार काफी समय पूर्व ही हो गया था । लेकिन भारतवर्ष में इसका उत्पादन काफी देरी से शुरू हुआ क्योंकि इसके लिए अन्य तकनीकी विकास करना आवश्यक होता है । इसके लिए श्रीमती गांधी की सरकार ने कारगर कदम उठाये । वर्तमान समय में टेलीविजन अनौपचारिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन है । जिस गति से हमारे देश में टेलीविजन के उत्पादन में वृद्धि हुई वो श्रीमती गांधी की अच्छी नीतियों की देन है ।

वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा टेलीविजन लाइसेन्स का शुल्क माफ करके जो महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है उससे ग्राम आदमी भी भविष्य में टेलीविजन का उपयोग करने लगेगा । किसी समय में टेलीविजन, विलासिता का साधन समझा जाता था । आज वो ही टेलीविजन हर परिवार के लिए अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है ।

3. टेलीफोन एवं अन्य संदेशवाहन के साधनों का विकास:—आज से कुछ वर्षों पहले टेलीफोन का प्रयोग बहुत ही कम लोगों के द्वारा किया जाता था । लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने संचार के साधनों को गाँव गाँव में पहुँचा दिया जिसका फायदा देश के ग्राम नागरिक को मिल रहा है ।

पुराने टेलीफोन यन्त्र से जो परेशानी होती थी वो स्वचालित टेलीफोन यन्त्र से दूर की गई ।

टेलीप्रिण्टर के उपयोग से बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को बहुत फायदा हुआ है । यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की अच्छी तकनीकी नीति की देन है । क्योंकि इन साधनों का विकास तेजी से नहीं किया जाता तो हमारा देश व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में काफी पिछड़ जाता ।

शिक्षा के क्षेत्र में

सन् 1947 से पूर्व अंग्रेज शासकों ने हमारे देश के नागरिकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों का उद्देश्य केवल देश की जनता का शोषण करना ही था। उस समय केवल शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी आम व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। क्योंकि न तो अधिक विद्यालय थे और न ही कोई शिक्षा का स्तर ही था।

अंग्रेज सरकार ने लार्ड मेकाले के सुझाव पर एक शिक्षा नीति तैयार की थी। इस शिक्षा नीति से केवल अंग्रेजों का यही उद्देश्य था कि भारतीय केवल क्लर्क से अधिक आगे नहीं बढ़ पावें। यह शिक्षा भी बहुत ही कम लोगों को मिल पा रही थी। अधिकतर बड़े पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जाती थी। भारतीयों की नियुक्ति बिल्कुल ही नहीं की जाती थी। भारतीय नागरिकों की नियुक्ति केवल क्लर्क एवं चंपरासी के ही पद पर की जाती थी, क्योंकि भारतीयों की शिक्षा भी इसी स्तर की दी जाती थी।

जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय साक्षर नागरिकों का अभाव था। आजादी के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने देश की बागडोर सम्भाली तब उनका उद्देश्य यही था कि देश का प्रत्येक नागरिक साक्षर हो। इसके लिये उन्होंने कारगर कदम भी उठाये तथा राष्ट्र भाषा का स्थान भी हिन्दी को दिया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में देश के आम नागरिकों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला तथा साक्षर लोगों के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई। पं० जवाहरलाल नेहरू भी लार्ड मेकाले के सुझाव पर आधारित शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर पाये। क्योंकि उस समय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का वातावरण नहीं था।

शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिये कई शिक्षा आयोग बनाये गये । जिसमें मुदालियर आयोग कोठारी शिक्षा आयोग एवं राधाकृष्णन आयोग के द्वारा जो भी सुझाव दिये गये वे पूर्ण रूप से लागू नहीं किये गये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमन्त्री पद सम्भालने के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात सोची । श्रीमती गांधी देश में एक ऐसी शिक्षा नीति लागू करने का विचार रखती थी जो कि बालक को शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी सुलभ कराये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में जगह जगह विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और शिक्षा को गांव गांव में पहुंचाने के लिये समय समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाये गये ।

जो लोग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाये थे उनके लिये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया जिसका फायदा देश की आम निरक्षर जनता को मिला ।

श्रीमती गांधी की सरकार ने शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिये नई शिक्षा योजना कई राज्यों में लागू की । नई शिक्षा का रूप $10+2+3$ हमारे देश में लागू किया गया ।

$10+2+3$ शिक्षा की नीति सभी राज्यों में तो आर्थिक कारणों से लागू नहीं की जा सकी । फिर भी कई राज्यों में यह लागू की जा चुकी है । जिन राज्यों में यह पेटर्न लागू किया गया, वहां पूर्णरूप से यह पेटर्न सफल हुआ ।

वर्तमान समय में हमारे देश में शिक्षा का एक पाठ्यक्रम नहीं है क्योंकि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार का कार्य राज्य सरकारों के अधीन है ।

किसी भी देश को अगर एक साथ आगे बढ़ाना हो तो शिक्षा का पाठ्यक्रम और पेटर्न समान होना चाहिये तथा हर कक्षा का पाठ्यक्रम केन्द्रीय सरकार के द्वारा तैयार किया जाना चाहिये जिससे कि हमारा देश सर्वांगीण विकास कर सके । तथा देश की आने वाली पीढ़ी को रोजगार के अवसर भी सुलभ हो सकें । शिक्षा का माध्यम अलग अलग हो सकता है लेकिन देश हित में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक होना चाहिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में साक्षर लोगों के प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई क्योंकि प्राथमिक शिक्षा तक किसी भी छात्र से किसी भी प्रकार का कोई

शुल्क सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महा-विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में भी जो शुल्क छात्रों से लिया जाता है वह भी नाम मात्र का वसूल किया जाता है।

वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा उच्च माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त करने वाली देश की सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का जो कारगर कदम उठाया गया है वह स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिये महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की प्रत्येक गरीब बालिका भी शिक्षा ग्रहण कर सकेगी।



पशु धन के क्षेत्र में

पशुधन हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इसकी रक्षाकरना देश की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमारे देश की जनसंख्या वर्तमान समय में भी कृषि एवं पशुधन पर आधारित है।

पशुधन के विकास से ही राष्ट्र का विकास सम्भव है। आजादी से पूर्व हमारे देश के पशुधन पर अंग्रेज सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। उस समय देश में पशुधन की संख्या तो अधिक थी लेकिन दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है।

आजादी के बाद पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये कई कारगर कदम उठाये गये मगर यह कदम विशेषरूप से सफल नहीं हुये।

जिस देश का पशुधन कमजोर होता है, वो देश भी कमजोर होता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने पशुधन की उपयोगिता बढ़ाने के लिए जो कारगर कदम उठाये वे निम्नलिखित हैं:—

1. पशुओं की बीमारियों में रोकथाम—पशुधन में जब बीमारियों का प्रकोप होता है तब अधिक मात्रा में पशुधन मरता है। पशुधन की रक्षा के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने कारगर कदम उठाये, जिससे पशुधन की मृत्यु दर में भारी कमी आयी है।

2. पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए सरकारी सहायता—श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये पशु पालकों को सभी प्रकार की सहायता दी, जिसमें काफी सफलता भी मिली। पशुओं की नस्ल सुधारने

से ही देश में दुग्ध का उत्पादन बढ़ेगा। जिस देश में पशुधन शक्तिशाली होगा उस देश की जनता भी शक्तिशाली होगी एवं वह देश भी शक्तिशाली होगा।

3. दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की स्थापना—प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की स्थापना की गई। यह सहकारी संस्थाएँ पशु पालकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं तथा पशुधन से प्राप्त दुग्ध को उचित कीमत पर पशु पालकों से खरीदती हैं।

सहकारी समितियों के विकास से देश के ग्राम किसानों की पशु पालन की तरफ रुचि बढ़ी है।

4. गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन—पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता है वो बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। मगर हमारे देश में गोबर के कंड़े बना कर जलाया जाता है। इस वजह से गोबर का केवल सीमित उपयोग ही होता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने गोबर की उपयोगिता को समझते हुये, गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए पशु-पालकों को प्रेरित किया तथा गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी गयी क्योंकि गोबर गैस संयंत्र से बिजली पैदा की जा सकती है, खाना तैयार किया जा सकता है तथा खेतों में उपयोग के लिए अच्छा खाद भी तैयार किया जा सकता है। जो कि कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होता है।

गोबर गैस संयंत्र का प्रचार अभी तक हमारे देश में सीमित मात्रा में हुआ है। बहुत ही कम लोगों ने गोबर गैस संयंत्र लगाये हैं।

हमारे देश को सम्पन्नता एवं वैभव की तरफ लेजाने के लिये गोबर गैस की उपयोगिता को समझाने के लिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाने चाहिये जिससे देश का ग्राम किसान एवं पशु पालक पशुधन के महत्त्व को समझ सके।

गोबर गैस संयंत्र विविध के प्रयोग से देश के ग्राम किसान को, पशु पालक को, समाज के हर वर्ग को तथा राष्ट्र को लाभ होगा और हमारी दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो सपना था वो भी साकार होगा।

पशुधन को समाज के एक अंग के रूप में समझना चाहिये । क्योंकि पशुधन समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी है, पशु जब तक जिन्दा रहता है तब तक समाज की एवं देश की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करता है । मृत्यु के बाद भी पशु से चमड़ा, हड्डियां एवं उसके बाल भी किसी न किसी रूप में काम आते हैं । इसलिये देश के हर नागरिक का एवं सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह पशुओं की देखभाल एवं उनके स्वास्थ्य के लिये सभी प्रकार के उपयुक्त उपाय करे ।



देश की रक्षा के खेल में

हमारा देश बहुत विशाल है। हमारे देश की सीमा एक तरफ पाकिस्तान से मिली हुई है। दूसरी तरफ चीन से, जिसने कि तिब्बत पर अपना राज्य स्थापित कर रखा है और हमारे देश की भी सन्-1962 से काफी जमीन दबा रखी है। अन्य देशों में बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, मालदीप, अफगानिस्तान, नेपाल एवं श्रीलंका जो कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। इनसे भी हमारी सीमायें मिली हुयी हैं।

सन् 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चीन ने जब आक्रमण किया था उस समय भारत एवं चीन के बीच काफी मित्रता थी, उस समय हमारा देश कभी भी नहीं सोच सकता था कि चीन मित्रता के नाम पर आक्रमण जैसा धोखा कर देगा।

जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया उस समय युद्ध के लिए न तो हमारे देश की सेना ही तैयार थी और न ही देश की सरकार। इस युद्ध में चीन ने हमारी लाखों वर्ग कि० मी० जमीन पर कब्जा कर लिया, जो कि आज भी बरकरार है।

चीन के युद्ध से पूर्व सरकार ने सेना को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया था क्योंकि 1962 से पूर्व भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध थे।

सन् 1962 में भारतीय सेना को मजबूत करने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ।

देश की सेना को मजबूत करने के लिए भारत ने सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रों की सहायता भी ली। उस समय विदेशों से युद्ध में काम आने वाली सामग्री खरीदी गयी एवं नई तकनीक का भी आयात किया गया।

सन् 1965 में भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के हाथों में देश की वागडोर थी। भारत ने पाकिस्तानी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब श्रीमती गांधी ने देश की वागडोर संभाली उस समय तक दो युद्ध लड़े जा चुके थे।

सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद देश की सीमा की रक्षा करने की ओर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुयी। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में सेना को मजबूत करने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया।

भारतीय सीमा की रक्षा करने के लिए देश में कई प्रकार के उत्पादन शुरू हुए जिनमें विमान, टैंक एवं अन्य यन्त्र प्रमुख हैं। हमारा देश रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भर बन चुका है।

वर्तमान समय में हमारे देश की सेना की गिनती विश्व की मजबूत सेनाओं में आती है। हमारा देश किसी भी बाहरी खतरे से निपटने में सक्षम है।

सन् 1962 के बाद सरकार ने सेना के तीन अंगों के आधुनिकीकरण (Modernisation) के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये। जिसमें हमारे देश की सरकार को सफलता भी प्राप्त हुई।

सन् 1971 में पाकिस्तान ने हमारे देश पर जोरदार हमला किया। उस समय बंगला देश में गृह युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय याह्या खां थे।

श्री याह्या खां ने राष्ट्रपति पद श्री अयूब खां का तख्ता पलट करके प्राप्त किया था। श्री याह्या खां ने पाकिस्तान में ग्राम चुनाव करवाये। जिसमें पूर्वी पाकिस्तान (बांग्ला देश) में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान में श्री जुल्फीकार अली भुट्टो की पीपुल्स पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था लेकिन उस समय जन संख्या की दृष्टि से पूर्वी पाकिस्तान (बांग्ला देश) की जन संख्या पश्चिमी पाकिस्तान से ज्यादा थी तथा संसद सदस्य भी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के ही अधिक थे।

वैधानिक रूप से उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जन आकांक्षियों के अनुरूप श्री शेख मुजीबुर रहमान को बनाया जाना चाहिए था। मगर श्री याह्या खां की इच्छा यह थी कि पूर्वी पाकिस्तान को नागरिक देश का प्रधानमंत्री किसी भी हालत में नहीं बने।

शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सत्ता नहीं सौंपने के कारण पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन छिड़ गया। इस आंदोलन को दवाने के लिए सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया तथा इस अहिंसात्मक आंदोलन को दवाने के लिए श्री याह्या खान सरकार ने सेना का उपयोग किया।

सेना ने पूर्वी पाकिस्तान (बांग्ला देश) में जनता के साथ दमन की तथा महिलाओं के साथ बलात्कार की नीति अपनायी जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नीति नहीं थी। पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्मों के कारण एक करोड़ के आस-पास बांग्ला देश के नागरिक अपनी मातृभूमि से पलायन कर गये।

भारत सरकार ने पलायनकारी नागरिकों को शरण दी तथा उनकी रक्षा के लिए कारगर कदम भी उठाये। शरणार्थियों पर उस समय हमारे देश का अरबों रुपया खर्च हुआ।

भारत सरकार के लिये बांग्ला देश के शरणार्थियों की एक समस्या बन गई क्योंकि इन सभी शरणार्थियों के कारण सरकार के ऊपर बहुत ही अधिक आर्थिक भार पड़ रहा था।

हमारा देश शरणार्थी समस्या का राजनीतिक हल निकालना चाहता था लेकिन पाकिस्तान उस समय पूर्वी पाकिस्तानियों (बांग्लादेशीयों) के प्रति दमनात्मक रवैया अपनाया हुआ था।

पूर्वी पाकिस्तान (बांग्ला देश) के प्रति नरम रख से नाराज होकर के पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया।

जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया था उस समय पूर्वी पाकिस्तान (बांग्ला देश) में गृह युद्ध भड़क रहा था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिकों के साथ दमनपूर्ण माहोल में एक देश के नागरिक के रूप में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वे प्रजातान्त्रिक सरकार की स्थापना शेख मुजीबुर-रहमान के नेतृत्व में करना चाहते थे।

सन् 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ। उस समय तक हमारा देश सैन्य शक्ति के मामले में काफी शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था।

भारतीय सेनाओं ने इस युद्ध में पाकिस्तानी सेनाओं का जोरदार मुकाबला किया। इस युद्ध में थल, जल एवं वायु सेना का भी प्रयोग किया गया।

पाकिस्तान की सेना सन् 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पायी ।

सन् 1971 का युद्ध भारत के लिए काफी नाजुक चुनौती थी । जिसका मुकाबला हमारे देश के सैनिकों ने बड़े ही धैर्य के साथ किया ।

सन् 1971 के भारत पाक युद्ध की विशेषता यह रही कि पाकिस्तान के एक लाख सैनिकों को ले. ज. नियाजी के नेतृत्व में भारतीय ले. ज. श्री जगजीतसिंह अरोड़ा के समक्ष आत्म-समर्पण करना पड़ा ।

एक लाख सैनिकों के द्वारा आत्म-समर्पण की घटना पहले कभी भी नहीं घटी थी । जो कि सन् 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान घटी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में भारतीय सेना की गिनती विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में की जाने लगी क्योंकि श्रीमती गांधी ने देश की एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए जो कारगर कदम उठाये उसी कारण से हमारे देश की सेना विश्व में एक शक्तिशाली सेना के रूप में उभर कर आयी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में सेना के काम में आने वाले सभी उपकरणों का उत्पादन हमारे देश में शुरू हुआ, इन सैन्य उपकरणों के उत्पादन से हमारे देश में एक नई तकनीक का विकास हुआ । जो उपकरण पहले हमारे देश को आयात करने पड़ते थे तथा उसके बदले भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का मुगतान भी करना पड़ता था, उतना मुगतान आज हमारे देश को नहीं करना पड़ता है, इस कारण से हमारे देश को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ ।

□

अंतरिक्ष के क्षेत्र में

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। उसी प्रकार से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और भी अधिक विकास कर सकता है लेकिन हमारे देश के पास विकास करने के लिए न तो अधिक धन ही था और न ही वैज्ञानिक क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त, 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस कारण देश की आर्थिक स्थिति, विरासत के रूप में हमारे देशवासियों को काफी कमजोर मिली। दूसरा कारण यह रहा कि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सुविधाओं के अभाव में अपने खुद के अच्छे भविष्य के लिये दूसरे देशों में पलायन कर गये।

फिर भी हमारे देश ने सभी समस्याओं का सामना करते हुये कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जिनमें आर्यभट्ट, एप्पल, रोहणी, इन्सेट-1, इन्सेट-2 और इन्सेट-3 प्रमुख हैं।

3 अप्रैल, 1984 को भारत और सोवियत संघ ने सोयूज टी-11 भी अंतरिक्ष में भेजा। इस साझा उड़ान का प्रमुख उद्देश्य भूगर्भीय प्रयोगों को करना तथा उनकी तस्वीरों को खींचना था, जिससे पृथ्वी के गर्भ में छिपे तेल तथा अन्य खनिज पदार्थों के स्थानों का पता लगाया जा सके।

भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा इस अंतरिक्ष अभियान में शोधकर्ता अंतरिक्ष यात्री थे, जिन पर विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का दायित्व सौंपा गया था, अपनी नौ दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान श्री शर्मा ने पदार्थ विज्ञान और जैव चिकित्सा के क्षेत्र में 13 प्रयोग किये तथा भारहीनता की स्थिति में शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की योगासनों के द्वारा जानकारी प्राप्त की।

श्री राकेश शर्मा ने शक्तिशाली कैमरों की सहायता से भारतीय घरती के 100 से अधिक काले सफेद और इनफ्रारेड चित्र भी खींचे।

सोयूज टी-11 क अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने प्रयोगों के दौरान विशेष किस्म के कैमरों की मदद से 4 मिनट 20 सैकण्ड तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों और पूर्वी समुद्र के चित्र भी खींचे।

सोयूज टी-11 भेजने से पहले सोवियत संघ अब तक 10 अन्य सोयूज विमानों को अंतरिक्ष में भेज चुका है पर सोयूज टी-11 इस उड़ान के लिए विशेष ढंग से तैयार किया गया था। इस यान का वजन 608 टन था और लम्बाई सात मीटर थी तथा इस यान की रफ्तार 480 कि०मी० प्रति मिनट से भी अधिक थी।

इस यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तीन चरणों वाला विशेष किस्म का प्रक्षेपण रॉकेट बनाया गया था, रॉकेट के प्रथम भाग में चार इकाइयां थी, प्रत्येक इकाई की लम्बाई 19 मीटर और चौड़ाई तीन मीटर थी। इनमें चार चेम्बरों वाले इंजन लगे हुये थे।

दूसरे भाग की लम्बाई 28 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 2.6 मीटर थी। रॉकेट की कुल लम्बाई 50 मीटर तथा अधिकतम चौड़ाई 10.3 मीटर थी, रॉकेट का भार 300 टन से भी अधिक था।

उड़ान के दूसरे दिन यानी 4 अप्रैल, 1984 को भारतीय समय के अनुसार शाम 8 बजकर एक मिनट पर अंतरिक्ष यान सोयूज टी-11 पृथ्वी के 18 चक्कर लगाने के बाद अंतरिक्ष प्रयोगशाला सैल्यूट-7 से जुड़ गया था।

सैल्यूट-7 सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल, 1982 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। यह सोवियत संघ का दूसरा अंतरिक्ष केन्द्र है।

सोयूज टी-10 पिछले 2 महीनों से अंतरिक्ष में एक ओर से जुड़ा हुआ था यानि यह पहला अवसर था, जब 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक साथ मौजूद थे।

सोयूज टी-11 वेकनूर से ठीक 295 कि०मी० की ऊंचाई पर सैल्यूट-7 से आकर जुड़ा था। जैसे ही आपस में जुड़े, अभियान नियन्त्रण कक्ष में बैठे भारतीय और रूसी दोनों खुशी से झूम उठे थे।

श्री राकेश शर्मा की पत्नी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा था कि यह विश्व की सबसे महान घटना है। मैं अब बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे उनके कुशलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौटने का वेसत्री से इंतजार रहेगा।

भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी दल का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा खींचे गये चित्रों से भारत की बदलती हुयी समुद्री रेखा, अरब सागर में मछली के भण्डार तथा राजस्थान में तेल और गैस का पता लग सकेगा। अगर इन सब चीजों का भण्डार भारत में मिल गया तो हमारा देश इन सब चीजों के मामले में आत्मनिर्भर हो जावेगा।

11 अप्रैल, 1984 का दिन भारत एवं सोवियत संघ के लिये खुशी का दिन था क्योंकि इस दिन हमारे देश के प्रथम अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा दो सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफल प्रयोग करके लौटे थे। श्री राकेश शर्मा ने अपना नाम प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास में लिखवा लिया और हमारा देश भारत भी उन 13 देशों में शामिल हो गया, जो पहले ही अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं।

कमांडर यूरी मेलीशेव ने उड़ान से पहले जारी एक सन्देश में कहा कि यह अभियान अंतरिक्ष शोध के लिये सोवियत संघ और भारत की बढ़ती साझेदारी का प्रतीक है तथा इस अभियान से दोनों देशों के बीच मैत्री और सद्भावना और भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अंतरिक्ष के शोध के क्षेत्र में जो सफलता हमारे देश को मिली है। उसमें हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिसे कभी भी नहीं मुलाया जा सकता है।



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में

हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। किसी भी देश की सरकार की पहली नैतिक जिम्मेदारी यह है कि वह अपने देश के नागरिकों को स्वस्थ रखे। जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे वह देश ही सम्पन्नता एवं वैभव की चोटी पर पहुँचेगा। समाज के हर वर्ग के लोग देश के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे।

जब कोई भी मानव शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है तो वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होता है। इसलिये देश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रखना आवश्यक है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में देश के नागरिकों के कल्याण के लिये कई स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाये गये। जिसमें उनकी सरकार को सफलता भी मिली।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के द्वारा देश के नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जो कारगर कदम उठाये गये वे निम्नलिखित हैं—

1. चेचक उन्मूलन—हमारे देश में चेचक का रोग मयंकर रूप से फैलता था। जिसमें लाखों बच्चों की मृत्यु हो जाती थी और कई बच्चे अंधे एवं अन्य किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हो जाते थे।

चेचक एक महामारी के रूप में फैलता था। जब इस रोग की शुरुआत होती थी तब सम्पूर्ण परिवार ही इस रोग से पीड़ित हो जाता था। इस रोग का उन्मूलन बहुत आवश्यक था।

हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चेचक उन्मूलन के लिये कारगर कदम उठाये। जिसमें उनकी सरकार को सफलता भी प्राप्त हुई। आज हमारे देश से चेचक का रोग हमेशा के लिये खत्म हो गया है।

2. कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिये कारगर उपाय—25 सितम्बर, 1984 को नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्वी एशिया के स्वास्थ्य मन्त्रियों की बैठक में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि कुष्ठ रोग हमारा पुराना शत्रु है और इसे जड़ से ही समाप्त कर देना चाहिये। भारत में हमने एक राष्ट्रीय अभियान चलाया है। हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुष्ठ रोग के उपचार के लिये एक बहु औषध चिकित्सा का विकास किया है इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आये हैं। लेकिन भय और सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण बड़ी संख्या में कुष्ठ रोगी अपना इलाज कराने से वंचित रह जाते हैं। इस रोग में समय पर उपचार बहुत आवश्यक होता है। कुष्ठ रोग के प्रभावी उपचार के लिये अनुसंधान में तेजी लानी चाहिये। इस रोग को हमेशा हमेशा के लिये इतिहास की कब्र में दफना दिया जाना चाहिये।

कुष्ठ रोग के उन्मूलन में विशेष सफलता तो नहीं मिली। लेकिन आने वाले समय में इस रोग का उन्मूलन करने में हमारे देश की सरकार को जरूर सफलता मिलेगी वशतः देश की जनता इस “कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम” में अपना सहयोग दे।

3. बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके—हमारे देश में कई प्रकार की बीमारियों का चलन है। इन बीमारियों से बचने के लिये, सम्बन्धित बीमारी का टीका लगाने का कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के द्वारा क्षय, पोलियो, हैजा एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिये जो कार्यक्रम चलाये उसमें उनकी सरकार को सफलता मिली। इस कार्यक्रम का प्रभाव यह हुआ कि मृत्यु दर में भारी कमी आयी।

4. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार—प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में चिकित्सालयों एवं चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है।

5. अनुसंधान सम्बन्धी कार्य—श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान करने के लिये सरकार के द्वारा वैज्ञानिकों को सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करवायी गयी। जिससे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देश की जनता की भलाई के लिये कई प्रकार के अनुसंधान किये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार की योजनाबद्ध विकास की नीति के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्लेग और चेचक जैसी घातक बीमारियों का उन्मूलन किया जा चुका है, जिनसे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौत के शिकार हो जाया करते थे। मलेरिया पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कुष्ठ रोग तथा तपेदिक से अभी भी बड़ी मात्रा में लोग पीड़ित होते हैं। पीण्डिकता की कमी, बीमारी या मोतिश्रावित्व से अब भी लोग नेत्र ज्योति से हाथ धो बैठते हैं, हालांकि सतर्कता बरतने से इन रोगों से बचा जा सकता है। पीण्डिकता की कमी, पानी से होने वाले रोगों तथा दूषित वातावरण के कारण रंगणता की दर भी अभी काफी ज्यादा है।

श्रीमती गांधी का सपना था कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाये रखने के लिए सन् 2000 तक सभी उचित सुविधायें मिल जाएंगी। उसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिये। जिससे देश के ग्राम नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

जनसंख्या नियन्त्रण के क्षेत्र में

हमारे देश के सामने जनसंख्या की समस्या बहुत ही नाजुक समस्या है। जिसका समाधान करना हमारी सरकार और देश की जनता का एक नैतिक कर्त्तव्य है।

भारत की जनसंख्या सन् 1947 में 34 करोड़ 20 लाख थी लेकिन यह जनसंख्या सन् 1981 में 68 करोड़ 40 लाख हो गयी। अगर हमारे देश की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो विकास कार्य से मिले सभी प्रकार के लाभ बेकार हो जावेंगे। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयी है। लेकिन वच्चों की जन्म दर में विशेष कमी नहीं आयी है। सन् 1971 और 1981 के बीच में जन्म दर 37 प्रति हजार रही। अगर जनसंख्या की वृद्धि दर इसी प्रकार से रही तो हमारे देश की जन संख्या सन् 2000 तक एक अरब हो जावेगी।

भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण

1. गर्भ जलवायु—हमारे देश की जलवायु बहुत गर्म है इसलिए हमारे देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यूरोपियन देशों से बहुत अधिक है।

2. मनोरंजन के साधनों का अभाव—हमारे देश में मनोरंजन के साधनों का अभाव है, इस कारण से हमारे देश की जन्म दर दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक है।

3. धार्मिक भावनाएँ—हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। कई परिवार नियोजन को अपनाते हैं, मगर कई व्यक्ति जनता में धार्मिक भावना भड़का करके परिवार नियोजन कार्यक्रम को असफल करते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है कि किसी भी धर्म की पुस्तक में परिवार नियोजन को गलत नहीं बताया है।

परिवार नियोजन एक कार्यक्रम है जिसे सफल बनाने के लिए देश के नागरिकों को अपना सहयोग देना चाहिये ।

जनसंख्या वृद्धि की दर एक प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये । अगर जन्म दर एक प्रतिशत से अधिक होगी तो विकास की दर की गति भी कम हो जावेगी ।

पादरी माल्थस ने कहा था कि अगर मानव ने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया तो प्रकृति निश्चित सीमा के बाद जनसंख्या पर नियंत्रण करेगी । प्रकृति के द्वारा किया गया नियंत्रण काफी दर्दनाक होता है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने परिवार नियोजन को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया । इस कार्यक्रम में श्रीमती गांधी की सरकार को सफलता प्राप्त हुई ।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण-सिंह ने कहा था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार को इसके लिए कानून बना देना चाहिए ।

परिवार नियोजन के क्षेत्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने जो माहौल तैयार किया उसका फायदा देश की वर्तमान सरकार को तेजी से उठाना चाहिए ।

□

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में

कोई भी देश जब ही विकास कर सकता है जब उसके पास ऊर्जा के अच्छे साधन हों क्योंकि ऊर्जा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंध होता है ।

परमाणु भट्टी का विश्व में सर्वप्रथम निर्माण सन् 1942 में विज्ञानी फर्मी के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय में किया गया । हमारे देश में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अक्सरा नाम की परमाणु भट्टी तैयार की जिसने 4 अगस्त, 1956 को कार्य करना प्रारम्भ किया । परमाणु भट्टी नियंत्रित अवस्था में परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का एक साधन है । 11 जुलाई, 1960 को भारत की द्वितीय भट्टी ने भी कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । इस परमाणु भट्टी का निर्माण कनाडा के सहयोग से किया गया था इसलिए इसका नाम “कनाडा इण्डिया भट्टी” रखा गया । इसे साइरस के नाम से भी जाना जाता है । तीसरी परमाणु भट्टी “जरीलिना” भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के मार्गदर्शन में ट्राम्बे के अन्दर तैयार की गई । चौथी परमाणु भट्टी “पूणिमा” भी ट्राम्बे में है ।

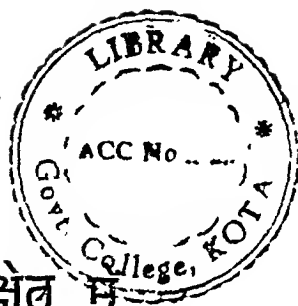
परमाणु ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्य में किया जा सकता है । इसके द्वारा विद्युत् उत्पादन, यातायात, चिकित्सा, खानों को गहरा करने, नदियों की गुप्त धाराओं को बाहर लाने तथा अन्य नाभिकीय उपयोग से अन्य कार्य भी सम्पन्न किये जा सकते हैं । परमाणु विस्फोट से सृजनात्मक कार्य भी किए जा सकते हैं और विनाशकारी कार्य भी । जिसका उदाहरण सन् 1945 में हिरोशीमा और नागासाकी शहरों में हुए विनाशकारी विस्फोट हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में हमारे देश ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है । परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी सृजनात्मक कार्य में किया गया है । शान्तिपूर्ण कार्य के उद्देश्य से भारत में पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट 18 मई, 1974 को राजस्थान में पोकरण में किया गया । भूमिगत

परमाणु शक्तियों] की पंक्ति में भारत का नाम विश्व में छठे स्थान पर जुड़ गया है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वही नीति रही जो कि हमारे प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की थी । परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में अधूरे रह गये कार्य श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा पूरे किये गये । हमारा देश श्रीमती गांधी के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया ।

□



विदेश नीति के खेल में

हमारे देश की विदेश नीति श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में वही रही जो कि श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तय की गई थी। विदेश नीति के मामले में अपने पिता तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित की गई नीति का ही अनुकरण देश हित में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया।

15 अगस्त, 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय विश्व दो गुटों में बंटा हुआ था। जिनमें एक गुट में पूंजीवादी देश थे। जिनका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तथा दूसरा गुट साम्यवादी गुट था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था।

111758

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की बागडोर संभाली जब पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देशों के बीच में आपसी तनाव था। श्री नेहरू ने किसी भी गुट में देश को शामिल नहीं होने दिया और आजादी के बाद उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। बल्कि एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा तथा पंचशील के सिद्धान्तों पर चलता रहेगा। सन् 1946 में सरकार का दायित्व संभालते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इस संकल्प की घोषणा की थी कि "हम एक दूसरे के विरुद्ध गुटों में बंधी शक्तियों अथवा समूहों से अलग रहेंगे जिनकी वजह से पहले भी विश्व युद्ध हुये हैं तथा भविष्य में भी और बड़े पैमाने पर विध्वंस हो सकते हैं।" वाद में अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि "वैदेशिक संबंध आपके हाथ से निकलकर किसी दूसरे हाथ में चले जायें तो उस सीमा तक आप स्वतन्त्र नहीं हैं....."। इसलिए हमारी नीति न सिर्फ गुटबंदी से अलग रहने की होगी बल्कि हम यह कोशिश भी करेंगे कि मैत्रीपूर्ण सहयोग संभव हो। हम समूचे संसार के साथ दोस्ती चाहते हैं।"

गुट निरपेक्ष सदस्यों की संख्या वेलग्राद सम्मेलन में सिर्फ 25 थी और अब यह संख्या बढ़कर 100 तक पहुँच गई है जो यह सिद्ध करती है कि गुट निरपेक्षता

विभिन्न महाद्वीपों के विशाल समुदाय की मन चाही आवश्यकताओं को पूरा करती है ।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के महत्त्व को इस बात से नहीं आंका जा सकता है कि हमारे पास कितनी फौज अथवा कितनी विध्वंसक शक्ति का भंडार है, बल्कि इसका पैमाना है शान्ति, स्वतन्त्रता, विकास और न्याय को कितनी ईमानदारी से, कितनी गंभीरता से चाहते हैं ।

गुट निरपेक्षता का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और स्वाधीनता है और यह शान्ति और लड़ाई से बचाव का पक्षधर है । इसका उद्देश्य सैनिक गुट-बंदियों से दूर रहना है । यह राष्ट्रों के बीच समानता और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और प्रजातान्त्रिक मूल्यों का समर्थक है । यह पारस्परिक लाभ के आधार पर विकास के लिए सार्वभौम सहयोग चाहती है । यह विश्व की विविधता को मान्यता प्रदान करने और उसे अक्षुण्ण बनाये रखने की नीति है ।

7 मार्च, 1983 को गुटनिरपेक्ष देशों के सातवें सम्मेलन के उद्घाटन पर बोलते हुए हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि आज मानव जाति एक ऐसे नाजुक कगार पर खड़ी है जहां विश्व आर्थिक व्यवस्था कभी भी ढह सकती है और नाभिकीय युद्ध की लपटों में मनुष्य जाति का कभी भी सर्वनाश हो सकता है । क्या इन विभिन्निकाओं को मान्यता दी जा सकती है । क्या हमसे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, दक्षिण का हो या उत्तर का, पश्चिम का हो या पूर्व का इससे बचने की उम्मीद कर सकता है ।

गुट निरपेक्षता की नीति पर हमारा देश विश्वास करता है और उसके पांच सिद्धान्तों में अपने दृढ़ विश्वास की पुष्टि करता है, जो है, संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ।

हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को सातवें गुट निरपेक्ष आन्दोलन के देशों का जो सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था उसमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष चुना गया, जो कि हमारे देश के लिए गर्व की बात है ।

गुट निरपेक्ष देशों के सातवें सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण करते समय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के 7 मार्च, 1983 को प्रकट किये गये विचार इस प्रकार से हैं जो कि हमारे देश की विदेश नीति को स्पष्ट करते हैं—

“हम भारत के लोगों को इस बात पर गर्व है कि हमें इस महान और महत्त्वपूर्ण आन्दोलन की सेवा का अवसर मिला। मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने आज सवेरे के अधिवेशन में भाग ले लिया। गिनी के राष्ट्रपति महामान्य कामरेड अहमद सिकुतसेरे, जोर्डन के शाह महामान्य हुसैन बिन तलाल, साइप्रस के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति महामान्य लियोन फोर्ब्स सैम्पसन बर्नहैम, स्वापो के महामान्य कामरेड सौमनुजोमा के हार्दिक उद्गारों के प्रति मैं अपनी और अपने देश की ओर से आभार प्रकट करती हूँ।

इथोपिया के अस्थायी सैनिक प्रशासन परिषद् के अध्यक्ष श्री मरियम, मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री महाथिरबिन मुहम्मद, साइप्रस के राष्ट्रपति श्री साइप्रस केप्रियानो, अर्जेन्टिना के राष्ट्रपति जनरल एनतोनियो और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष महामान्य श्री यासर अराफात ने मेरे नाम का प्रस्ताव करते समय जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। मैं इन भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुई। इस प्रोत्साहन से मैं भावविभोर हो गई। मैं इस सम्मान को व्यक्तिगत रूप से अपने लिए नहीं समझती बल्कि यह तो महान परम्परा को अर्पित है। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

महिलायें राष्ट्रपति सिकुतोरे को धन्यवाद देंगी। जिन्होंने उनकी हिमायत की। भेदभाव युक्त समाज में उन्होंने दायित्व निभाने के लिए स्वेच्छा से सहयोग दिया और न्याय के लिए बलिदान दिया। उनकी इच्छा है कि वे भी पुरुषों की तरह अपनी क्षमतायें विकसित कर सकें।

आपने मुझे महान दायित्व सौंपा है। खेमों में बंटे विश्व में मैं गुट निरपेक्षता से संबंधित हूँ। सम्पन्न देशों के प्रभुत्व के बीच मैं एक निर्धन और विकासशील देश से संबंधित हूँ, पुरुष प्रधान देश में एक महिला हूँ। इस तरह मेरा काम बहुत मुश्किल है। किन्तु मैं वह भार अपने कंधे पर ले रही हूँ जिसे हमारे युग के श्रेष्ठतम नेताओं ने उठाया और अभी अभी जो विश्व के विख्यात और महान क्रांतिकारी महामान्य राष्ट्रपति कास्त्रो के कंधे पर था। मैं बहुत ही आदर के साथ इस दायित्व को स्वीकार करती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सब मुझे भरपूर समर्थन देंगे। ऐसे शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष या अध्यक्षा को अगले तीन वर्षों तक इस आन्दोलन का प्रवक्ता समझा जावेगा। आवाज मेरी हो सकती है लेकिन मैं आशा करती हूँ कि वह विश्व समीपता के साथ पूरे आन्दोलन के विचारों और भावों को प्रतिध्वनित करेगी। मैं आपकी अमूल्य सहायता पर निर्भर करूंगी। भारत ने अनेक भार वहन किये हैं और हममें इनके सहने का धैर्य भी है लेकिन यह भार तो हमसे भी बड़ा है और इसके लिए हमें पूरे आन्दोलन की सहायता की

आवश्यकता होगी। भारतीय परंपरा रही है कि अधिक से अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त किया जावे। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भी यह परम्परा रही है कि उसने सदा आम सहमति के लिए प्रयत्न किया है। कई विषयों में हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है इसलिए हमें ऐसे क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित रखना चाहिये जिन पर मोटे तौर पर सहमति हो और इसे ईमानदारी से आगे बढ़ाना चाहिये।

हमारा यह सम्मेलन विशेष संगम है। हम किसी शक्ति के माध्यम से एकत्र नहीं हुए हैं और न ही दूसरों से लाभ उठाने या उन्नत शोषण करने की गरज से इकट्ठे हुए हैं। हम किसी को धमकाने नहीं। दरअसल हम तो विश्व को धमकियों से बचाना चाहते हैं। हमें प्रभुत्व नहीं चाहिये और हमें कोई प्रभुत्व बनाना भी नहीं है।

हमारे आंदोलन में सभी बराबर हैं। हम सहयोगी हैं। हमारे बीच कोई नेता नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है। नेतृत्व की होड़ से बड़ी हानि हुई है। विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा मौजूद रही है और यही संसार के लिए संकटों का मूल कारण बनी है। हमारे देश के एक महान संत सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने अब से लगभग 500 वर्ष पहले कहा था जिसका अर्थ है कि मानव बंधन मुक्त पैदा होता है। यही बात राष्ट्रों के बारे में भी लागू होती है। लेकिन आर्थिक स्वार्थों, सैनिक शक्ति और औद्योगिक उन्नति ने बहुत से लोगों को दास बना दिया है। औपनिवेशिक दासता की एक लम्बी काली रात के बाद स्वाधीनता का सूर्य उगा है किन्तु आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र की पुरानी दासता अभी भी हमारे पीछे पड़ी हुई है।

यह सोचने वाली बात है कि प्राचीन संस्कृतियों के देशों को जिनका सबसे पहले कृषि और औद्योगिक विकास हुआ आज विकासशील देश कहा जाता है औद्योगिक दृष्टि से हम विकासशील हो सकते हैं। सैनिक दृष्टि से कमजोर हो सकते हैं लेकिन स्वाधीनता के प्रति हमारी भावनार्थ उन्नत और सुदृढ़ हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए वे दुर्दमनीय हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में हानि लाभ में हमारी बराबरी की और सम्मानजनक हिस्सेदारी होनी चाहिये।

हम एकता से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यह उद्देश्य केवल हमारे ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए हैं। शान्ति जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं उनके लिए भी लाभकारी है जो गुटों में बंटे हुए हैं। गुणवत्ता में मुश्किल से ही शुद्धता रहती है और जो इसमें विश्वास नहीं रखते। निर्बल और शक्तिमान

सापेक्ष शब्द है। गुणवत्ता में मुश्किल से ही शुद्धता रहती है और उसमें भिन्नता आ जाती है। कमजोरी में भी अपनी शक्ति होती है और बलशाली भी कभी कभी अपनी ही शक्ति से भस्मीभूत हो सकता है। आज सम्पन्न और शक्तिशाली देश भी इससे बढ़कर आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त नहीं हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को इसी से लाभ होगा कि वे हमारी अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित करें। विश्व एक इकाई है। अगर आप इसको विद्युत् धारा समझते हैं तो इसके उतार-चढ़ाव से कोई अप्रभावित नहीं रह सकता और यह धारा कट जायेगी तो अंधकार सभी को घेर लेगा।

मैंने उन मामलों पर चिन्ता व्यक्त की है जिनका हमसे संबंध है। इनमें से सबसे अधिक जटिल है मानव जाति के अस्तित्व को खतरा क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम परमाणु युद्ध से अपने को अलग भी रखें तो भी इसकी रेडियोधर्मिता देश की सीमाओं से बंधी नहीं रहेगी और न ही यह सापेक्ष निरपेक्ष का ख्याल रखेगी। कोई भी इसके भयंकर परिणामों से नहीं बच पावेगा। परमाणु हथियारों का भण्डार और अन्य आसुरी हथियार बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं और शांति के लिए हमें और ज्यादा सतर्क रहने को बाध्य करते हैं।

सुरक्षा का अर्थ यह नहीं कि हम सैनिक शक्ति बढ़ायें जो अपनी चंचल प्रवृत्ति के कारण अनिवार्य रूप से हथियारों की अंधी दौड़ को जन्म देती है और न ही परमाणु अस्त्र परित्याग सुरक्षा कायम रखने का स्थायी आधार हो सकता है, क्योंकि आशंकाओं के वातावरण में परित्याग संदिग्ध होता है। परमाणु युद्ध की आशंकायें भारी मात्रा में परमाणु हथियार जमा करने, उनके वाहन तंत्र, उनको और खतरनाक बनाये जाने और उनकी गति तथा अचूकता बढ़ाने तथा साथ ही उनके इस्तेमाल के लिए अजीब दलीलों से उत्पन्न होती है।

अब से पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आयी कि देश जो एक दूसरे से तना-तनी रखते हों उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति में विनाश तथा प्रकृति की विकृति के लिए उन हथियारों के इस्तेमाल के जरिये खतरा पैदा कर दिया हो जिन्हें वे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक बताते हों। सभी देशों का एक नैतिक दायित्व है कि ऐसा वेमिसाल सर्वग्राही खतरा पैदा न होने दें लेकिन उनकी तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। हो सकता है इस समय हमारे इस कथन पर ध्यान न दिया जावे लेकिन हमें इस पर जोर देना चाहिये। उच्च आदर्शों और विचारों को बहुत देर तक दबाये नहीं रखा जा सकता। वे मूर्त होने चाहिये।

हम भारतीय विश्वासों वाले व्यक्ति हैं। हमारे त्योहारों में आनन्द भरा हुआ है और उनसे पाप पर पुण्य की विजय का संदेश मिलता है। यही भावना हमें रास्ता दिखाये। एक बार मैं आप सब को धन्यवाद देती हूँ।”

स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पूंजीवादी देश अमेरिका और साम्यवादी देश सोवियत संघ जो कि विश्व में महान शक्तियां हैं। इन दोनों देशों से भारत के संबंध बराबर से रहे हैं। दोनों ही देशों ने हमारे देश की संकट के समय सहायता भी की है।

सन् 1966 में श्री लालबहादुर शास्त्री के आकस्मिक देहान्त के बाद श्रीमती गांधी देश की प्रधान मंत्री चुनी गईं। श्रीमती गांधी के शासनकाल में सोवियत संघ के साथ रक्षा के संबंध में एक संधि हुई। जिसका उद्देश्य यह था कि दोनों देश संकट के समय में एक दूसरे देश की मदद करेंगे। इस रक्षा संबंधी संधि के कारण भारत और सोवियत संघ के बीच और भी मजबूत संबंध हो गये, जो कि श्रीमती गांधी की अच्छी विदेश नीति की देन थी।

प्रधान मंत्री के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी विदेश नीति के क्षेत्र में सफल रही हैं।



पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए किए गए कार्य

श्रीमती इन्दिरा गांधी गरीबों की मसीहा थीं। पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में श्रीमती गांधी की सरकार की वही नीति रही जो कि उनके पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू की थी। श्रीमती गांधी के शासनकाल में कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कई कारगर कदम उठाये गए एवं कई प्रकार की कल्याणकारी योजनायें देश में लागू की गयी जिसमें उनकी सरकार को उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त हुई।

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 46 एवं अनुच्छेद 14 को दृष्टिगत रखते हुए समाज के कमजोर वर्गों अर्थात् पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत आयोग बठाकर उसकी अनुशंसा के आधार पर उनके कल्याण के लिए कार्यवाही करने की व्यवस्था दी है। अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत अनुसूचित जन जातियों की सूची तथा अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत सेवाओं में तथा अन्य क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की है। पंचम अनुसूची के अन्तर्गत अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष कानून बनाने की व्यवस्था है।

सामाजिक समानता का अधिकार सभी नागरिकों को अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत देते हुए कमजोर वर्गों को समाज के उन्नत वर्गों की श्रेणी में लाने एवं उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में व्यवस्था की गयी है। जिसके अनुसार इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात सरकार को नागरिकों के किसी सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेंगी।

यह उल्लेखनीय है कि मूल रूप से अनुच्छेद 16 (4) के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए राज्य सरकार के अधीन पदों के आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। किन्तु नये खण्ड में राज्य की ओर से सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है। प्रवर समिति के संक्षेप पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने यह अन्तर अनुच्छेद 15 (4) की भाषा को अनुच्छेद 340 की भाषा के अनुसार बनाने के लिए किया गया बताया जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जावे।”

□

जातिवाद का उन्मूलन

कमजोर वर्ग के लोगों के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड के अलावा जातियों एवं समुदायों की एक सूची भी आवश्यक रूप से है, जिसका उद्देश्य स्व० पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “हम उन सभी असीमित वर्गों को समाप्त करना चाहते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन में विकसित हो गये हैं। पूर्व विधि मन्त्री स्व० डा० भीमराव अम्बेडकर ने आगे बढ़कर कहा था जो “भी पिछड़ा वर्ग कहलाते हैं वे और कुछ नहीं केवल कुछ जातियों का समूह है।”

मण्डल आयोग ने 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग में परिगणित करके उन्हें एक समूह होने तथा आपसी मतभेद, भेदभाव मिटाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर दिया जो कि देश की एकता और अखण्डता के लिए एक ठोस कदम सिद्ध होगा। पूरा भारतीय समाज यदि पांच हजार जातियों के बजाय चार वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के रूप में संगठित हो जाता है तो एक समय ऐसा आ सकता है जबकि वे परस्पर एक जुट हो जावें क्योंकि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं।

विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक एम० जी० गास ने समानता को तीन विकल्पों में बांटा है जो है अवसर की समानता, व्यवहार की समानता एवं परिणाम की समानता।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के अन्तर्गत दी गई अवसर की समानता वास्तव में इच्छा स्वतंत्रवाद है न कि समानतावादी सिद्धान्त, क्योंकि यह जीवन के क्षेत्र में प्रत्येक को समान स्वतन्त्रता पदान्तर करते हैं। लेकिन जो लोग अपना जीवन असुविधाओं से शुरू करते हैं वे शायद ही अवसर की समानता का लाभ उठा पाते हैं क्योंकि जब तक वे कुशलता और उन्नतिशील तकनीकों में विशेष दक्षता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे कभी भी सम्पन्न व्यक्ति के मुकाबले सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अवसर की समानता एक सामाजिक सिद्धान्त भी है।

किन्तु यह सुविधाहीन लोगों के रास्ते में बहुत सी अड़थक एवं परेशानियों को नहीं देखता है वस्तुतः जब तक गरीब परिवार में बच्चे को पैदा होते ही उनके माता-पिता से लेकर मध्यमवर्गीय परिवार में उनका लालन पालन नहीं किया जावेगा तब तक अधिकांश अवसर की असमानता से ग्रस्त रहेंगे।

वर्गगत आरक्षण संवैधानिक

शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर पर किया गया आरक्षण ही संवैधानिक है जबकि आर्थिक आरक्षण को संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है।

मण्डल आयोग का निष्कर्ष है कि भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के लिए कानून के समक्ष समानता के दावे का अधिक महत्त्व नहीं है। प्रभावी समानता की वास्तविक परीक्षा परिणामों की समानता रही है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि स्वतन्त्रता, समानता के अवसर एवं व्यावहारिक समानता के लाभों का उचित अंश जब तक पिछड़े वर्गों को उपलब्ध नहीं हो जावे तब तक हमारा प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रीय गणतंत्र गंभीर रूप से दोषपूर्ण रहेगा।

न्यायमूर्ति के. सुब्बाराव ने “सामाजिक न्याय एवं कानून” नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक में कहा है कि जब तक दलित वर्गों को समुचित सुविधायें नहीं दी जावेगी, तब तक यह कहना संभव नहीं होगा कि उन्हें अति विकसित लोगों की तरह ही समान अवसर प्राप्त हो। यही कारण है और सामाजिक न्याय के लिए उचित भी है कि देश के दलित नागरिकों को प्राथमिकता दी जावे ताकि उन्हें समाज के अन्य अतिविकसित वर्गों के बराबर समान अवसर प्राप्त हो सके।

नवीन आरक्षण नीति

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में पिछड़े वर्गों के लिए पच्चीस प्रतिशत तथा गरीबों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण किया गया। 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई। लेकिन इसे केवल पिछड़े वर्गों के 25 प्रतिशत आरक्षण का विरोध ही बताया जाता है। सामान्य वर्ग तो पूरे आरक्षण नीति का विरोध कर रहा है। किन्तु प्रत्यक्ष रूप से पिछड़े वर्गों का विरोध एवं अन्य के बारे में चुप्पी की राजनीति अपना रहा है।

देश के वातावरण को देखते हुए आरक्षण के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग को गरीबी रेखा से नीचे तथा पूर्ण रूप से

योग्यता में बांटना होगा एवं श्रेणी और वर्ग में स्वयं के भीतर प्रतिस्पर्धा करानी होगी ताकि अच्छे से अच्छे उम्मीदवारों का चयन हो सके ।

अपेक्षित सुधार

आरक्षण के सम्बन्ध में सर्व प्रथम मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए किये गए वर्ग गत आरक्षण एवं अतिरिक्त अन्य सभी आरक्षण समाप्त कर उन्हें प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित कर दिया जावे । संवैधानिक रूप से केवल शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये अनुच्छेद 15 (4) तथा अनुच्छेद 16 (4) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं एवं नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है । शेष सभी श्रेणियों को प्राथमिकता दी जा सकती है । आरक्षण नहीं दिया जा सकता है । समाज के सभी वर्गों का दायित्व है कि वे अपने वर्ग की सीटों में से सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा सेवारत सैनिकों के वृद्धों, महिलाओं, विकलांगों तथा तकनीकी व्यक्तियों को आर्थिक आधार पर निर्धारित प्रतिशत तक प्राथमिकता दें ।

जनसंख्या वृद्धि के कारण आरक्षण में वृद्धि न्याय संगत नहीं है क्योंकि इससे परिवार नियोजन की राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध जन संख्या वृद्धि दर को गति मिलेगी जो कि राष्ट्रीय हित में नहीं है । इसलिये अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों की जन संख्या वृद्धि के कारण बढ़ाया गया आरक्षण का प्रतिशत राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में रद्द करना उचित होगा ।

क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण घटाने और बढ़ाने से भी असन्तोष फैलता है अतएव इसके अनुसार किया गया आरक्षण रद्द कर पूरे देश में समान प्रतिशत में आरक्षण किया जावे ।

नौकरी में आरक्षण करना संवैधानिक रूप से एवं नैतिक रूप से उचित है । लेकिन अगले पद पर पदोन्नति में आरक्षण उचित नहीं है क्योंकि इससे दूसरे वर्ग के कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी आती है । पदोन्नति का आधार वरिष्ठता या योग्यता ही होना चाहिये ।

आरक्षण की सीमा

न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार सामान्यतः आरक्षण कुल सीटों एवं स्थानों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । प्रश्न यह उठता है कि

जिन राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्गों की जनसंख्या पचास प्रतिशत से भी अधिक है वहां भी यह सीमा लागू होगी। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियां 14.10 प्रतिशत, अनुसूचित जन जातियां 22.97 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग 48.08 प्रतिशत है। इस प्रकार से कुल 85.15 प्रतिशत पिछड़ी जनसंख्या के लिये 50 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण रखना क्या उचित होगा? संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के अनुसार सभी नागरिकों को रोजगार का समान अवसर प्राप्त रहेगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 85.15 प्रतिशत पिछड़ी जनसंख्या के लिये पचास प्रतिशत की सीमा तक के आरक्षण को अवसर की समानता नहीं कहा जा सकता है। इसी कारण से उच्चतम न्यायालय ने 'अखिल भारतीय शोपित कर्मचारी संघ रेलवे बनाम भारत संघ' के मुकदमें में 70 प्रतिशत तक के आरक्षण को सही ठहराया गया है लेकिन न्यायिक निर्णयों के अनुसार 50 प्रतिशत तक की सीमा में कोई बन्धन नहीं है। यह न्यायाधीशों द्वारा सुविधा के लिये एक निर्धारित मार्गदर्शन नियम है। पर्याप्त कारणों के आधार पर 50 प्रतिशत से भी अधिक आरक्षण संवैधानिक रूप से किया जा सकता है।

आरक्षण हमेशा के लिये जारी नहीं रखा जा सकता है लेकिन आरक्षण को एक साथ समाप्त भी नहीं किया जा सकता है।

जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय तक दलित वर्ग के नागरिकों का शोषण किया जाता था तथा उनके साथ छद्मछद्म भी की जाती थी। 1947 से पूर्व हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। ईसाई मिशनरियां धर्मान्तरण करवाने में जोर शोर से लगी हुई थी।

यह धर्मान्तरण, धन एवं सुविधाओं का लालच देकर के करवाया जाता था।

सन् 1947 से पूर्व हिन्दू धर्म में छद्मछद्म का बोलवाला बहुत ज्यादा था। छद्मछद्म से नाराज होकर दलित वर्ग के मसीहा, संविधान सभा के सदस्य तथा भारत के भू० पू० विधि मन्त्री स्व० श्री भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि "मैं एक हिन्दू के रूप में पैदा हुआ हूँ। लेकिन हिन्दू के रूप में मरना कभी भी पसन्द नहीं करूंगा।"

संविधान निर्माताओं का आरक्षण के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि दलित वर्ग धर्म परिवर्तन न करे। अगर देश में दलित वर्ग को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती तो अब तक पचास प्रतिशत भारतीय जन संख्या धर्मान्तरण की शिकार हो जाती जिससे देश की व्यवस्था भी बिगड़ सकती थी।

अभी कुछ वर्ष पूर्व भी तमिलनाडू के अन्दर कमजोर वर्ग के लोगों को दबाव से एवं धन के लालच से धर्मान्तरण करवाया गया था, जो कि उचित नहीं था ।

आरक्षण समाप्त करने का मसला एक राष्ट्रीय मसला है । जिसके लिये देश के सभी नागरिकों को ठण्डे दिमाग से सोचना चाहिये तथा सरकार का भी नैतिक कर्त्तव्य है कि वह आरक्षण के मामले में देश के नागरिकों की भी सहमति बहुमत के आधार पर जान ले, जो कि राष्ट्रीय हित में ठीक रहेगा ।

आरक्षण समाप्त करने का समय तो नहीं आया है और न ही इसे एक साथ समाप्त ही किया जा सकता है लेकिन देश का वातावरण आरक्षण को लम्बे समय तक जारी रखने के पक्ष में भी नहीं है । इसलिये देश, काल और वातावरण को देखते हुये प्रतिवर्ष दो प्रतिशत के मान से प्रत्येक पांच वर्ष पूरा होने पर आरक्षण में दस प्रतिशत की कमी कर दी जावे तो पचास वर्ष में आरक्षण बिना किसी कठिनाई के समाप्त हो जावेगा । समाज एवं सरकार से यह आशा की जाती है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े तबकों को इस पचास वर्ष की अवधि में सामान्य वर्ग के स्तर पर ला सकने में सफल होगा । जिससे जाति प्रथा का उन्मूलन करने में भी सरकार को एवं समाज को मदद मिलेगी तथा देश भी सम्पन्नता एवं वैभव की तरफ बढ़ेगा ।



धर्म और श्रीमती इन्दिरा गांधी

हमारा देश आवादी में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। जिनमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी प्रमुख हैं।

हमारे देश में लगभग 82 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू धर्म को मानती है। इसलिये हमारे देश में हिन्दू जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर हैं।

भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। देश में संविधान के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय धर्म निश्चित नहीं किया गया है। इसलिये सरकार की तरफ से सभी धर्मों की जनसंख्या को समानता की दृष्टि से देखा जाता है। सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार हैं।

धर्म के दो पक्ष होते हैं एक पक्ष नैतिक तथा दूसरा पक्ष अनुष्ठान होता है। धर्म एक विचारधारा होती है। धर्म का नैतिक पक्ष वह होता है जिसमें मानव मात्र के प्रति सेवा का उद्देश्य हो। अनुष्ठान पक्ष में धर्म विशेष की पूजा पद्धति आती है। इस प्रकार कोई भी धर्म देश और समाज के लिये हानिप्रद नहीं होता है। कुछ व्यक्ति कट्टरता को ही धर्म का जामा पहनाकर धर्म की मूल भावना से परे हट कर संकुचित भावना में धर्म को केन्द्रित कर देते हैं। यह देश और समाज के हित में नहीं है। धार्मिक कट्टरता के कारण देश में साम्प्रदायिक दंगे समय समय पर होते रहते हैं जिससे जन और जन दोनों की ही क्षति होती है। देश में साम्प्रदायिक दंगे समाज कंटकों एवं विदेशी मिशनरियों के द्वारा करवाये जाते हैं। जिनका उद्देश्य देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा करना होता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी देश के सभी धर्मावलम्बियों को समान रूप से देखती थी। श्रीमती गांधी का झुकाव धर्म के नैतिक पक्ष की तरफ अधिक था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया गया तथा धर्म के आधार पर किसी भी धर्मावलम्बी के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया ।

दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं है, न तो उनको राजनैतिक संरक्षण ही दिया जाता है और न ही उनकी सम्पत्तियों की सुरक्षा ही की जाती है, बल्कि वहां की सरकार की नीति ही अल्पसंख्यकों के प्रति शोषण की रहती है ।

हमारी दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में डा० जाकिर हुसैन, श्री फखरुद्दीन अली अहमद एवं वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैलसिंह ने देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया, जो कि सारे विश्व के सामने एक उदाहरण है । यह तीनों ही व्यक्ति देश के राष्ट्रपति इसी वजह से बने कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है । उदाहरण के लिये पाकिस्तान और बांग्लादेश को लीजिये जहां पर अल्पसंख्यक कभी राष्ट्रपति नहीं बना है, और अल्पसंख्यकों को देश के सर्वोच्च पदों से दूर ही रखा जाता है । इन देशों की राजनीति धर्म पर आधारित है तथा अल्पसंख्यकों का राजनीति में कोई महत्व नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी सभी धर्मों का सम्मान करती थी और उनके शासन काल में अल्पसंख्यकों के साथ कभी भी दूसरे दर्जे का व्यवहार नहीं किया गया बल्कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई । जिसे हमारे देश के अल्पसंख्यक कभी भी नहीं भूल सकते हैं ।

भारत की राजनीति धर्म के ऊपर आधारित नहीं है । हमारे देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो धर्म को आधार बनाकर राजनीति चलाती हैं और धार्मिक स्थलों का उपयोग भी सत्ता प्राप्त करने के लिये करती हैं जो कि देश हित में उचित नहीं है ।

धर्म के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा गांधी के विचार धर्मनिरपेक्षता के थे, उन्हीं आदर्शों और मूल्यों के आधार पर देश के प्रत्येक नागरिक को चलना चाहिये । जिससे देश की एकता और अखण्डता बनी रह सके तथा विश्व के सामने विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आ सके ।

देश का प्रत्येक नागरिक पहले भारतीय है उसके बाद हिन्दू, मुसलिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं अन्य धर्मावलम्बी है ।

देश में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने के लिये, देश की सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह साम्प्रदायिक संगठनों पर पाबन्दी लगाये, क्योंकि साम्प्रदायिक संगठन विदेशी शक्तियों के इशारों पर देश में अस्थिरता पैदा करते हैं ।

प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य है कि साम्प्रदायिक तत्त्वों के द्वारा जो गलत अफवायें फैलायी जाती हैं उनसे सावधान रहें । किसी भी धर्म की किसी भी पुस्तक में हिंसा को सही नहीं माना गया है । धर्म के सम्बन्ध में सोचने का ढंग संकीर्ण नहीं होना चाहिये ।

शिक्षा में धर्म का समावेश होना चाहिये । देश के समस्त छात्रों को सभी प्रकार के धर्मों की जानकारी होनी चाहिये जिससे हमारे देश के छात्रों का आध्यात्मिक विकास हो सके ।

आध्यात्मिक विकास से छात्रों की मानसिक शांति प्राप्त होगी जिससे प्रत्येक छात्र का सर्वांगीण विकास हो सकेगा । धार्मिक शिक्षा देने का माध्यम विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हो सकते हैं । इसके लिये देश की सरकार को उचित कदम उठाने चाहिये ।

□

श्रीमती गांधी और देश की महिलायें

श्रीमती इन्दिरा गांधी सारे विश्व की महिलाओं के लिये एक आदर्श थी। श्रीमती गांधी स्वयं महिला थी लेकिन स्पष्ट रूप से स्वयं यह कहती थी कि मैं “महिलावादी” नहीं हूँ। लेकिन महिला-समानता की हिमायती अवश्य हूँ।

दूसरे देशों के नागरिकों की यह अवधारणा थी कि महिला प्रधानमंत्री के रहते हुये देश की महिलाओं की दयनीय स्थिति नहीं हो सकती है। लेकिन श्रीमती गांधी ने भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में कहा था कि “भारत में महिलाओं की कानूनी एवं संवैधानिक स्थिति तो समान है परन्तु आर्थिक व सामाजिक स्थिति अब भी निकृष्ट है। केवल मेरे प्रधानमंत्री बनने से सब महिलायें ऊंची नहीं उठ गयी हैं”।

स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश की महिलायें अपना आदर्श और प्रेरणा का श्रोत ही नहीं मानती थी एक महिला होने के नाते महिलाओं की पीड़ा और अन्तर्मन की बात भी वे जानती थीं।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये कई कल्याणकारी योजनायें देश में लागू की गई जिसका फायदा देश की आम महिला को मिला।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आजादी की लड़ाई से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचने में कई उतार चढ़ाव देखे। श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु-परान्त जब श्री लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तब उन्हें मन्त्री-मण्डल में सूचना एवं प्रसारण मन्त्री बनाया गया। उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी केवल नेहरू जी की बेटी के रूप में जानी जाती थी। उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व बन रहा था। देश की महिलायें इसलिये प्रसन्न थीं कि उनके समुदाय का

प्रतिनिधित्व मन्त्री मण्डल में तो हुआ। जब श्रीमती गांधी सन् 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद देश की प्रधानमन्त्री बनी तो लोगों को उनकी काबलियत का पूर्ण ज्ञान नहीं था।

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमन्त्री के रूप में कार्य करना शुरू किया तो यह सारे भारतवर्ष की महिलाओं के लिये ही नहीं सारे विश्व की महिलाओं के लिये गर्व की बात थी, क्योंकि विश्व के इतिहास में इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश की किसी महिला का प्रधानमन्त्री होना सबसे महत्वपूर्ण घटना थी।

जब सन् 1968 में श्रीमती इन्दिरा गांधी कॉलेज के एक समारोह में भाग लेने के लिये वीकानेर आयी तो उस समय महारानी सुदर्शन कॉलेज की छात्रा यूनियन की जनरल सेक्रेटरी शमीम अख्तर ने पूछा कि अब भी महिलाओं को अवला क्यों समझा जाता है? श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शमीम अख्तर के प्रश्न का जवाब देते हुये कहा कि “अपने को कमजोर और असहाय मत समझो। योग्यता के आधार पर महिलायें पुरुषों से भी आगे निकल सकती हैं।”

हमारी दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने जीवन काल में स्वयं ने सिद्ध कर दिया कि महिलायें भी पुरुषों से आगे निकल सकती हैं। इससे देश की आम महिला के मनोबल में भारी वृद्धि हुयी।

महिलाओं के कल्याण के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने जो कल्याणकारी कदम उठाये वे निम्न हैं—

1. दहेज को संवैधानिक रूप से गैर कानूनी करार दिया गया। जो भी व्यक्ति दहेज लेता है वो अपराधी की श्रेणी में आता है।
2. सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित किये गए।
3. महिलाओं की नियुक्ति सरकार के द्वारा उच्च पदों पर की गयी।
4. महिलाओं का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये कई प्रकार के कारगर कदम उठाये गये।
5. महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये कई प्रकार के कारगर कानून बनाये गये।

हमारी दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 17 वर्षों तक देश की जनता के दिलों पर शासन किया तथा देश की जनता का दिल भी जीता। आज वह हमारे बीच नहीं हैं। फिर भी उनके आदर्श और मूल्य हमेशा जीवित रहेंगे। उनके आदर्शों और मूल्यों के आधार पर हमारी वर्तमान सरकार चली तो हमारा देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिये कई कारगर कदम उठाये गये। मगर समाज के लोगों का पूर्ण समर्थन नहीं मिलने से उनकी सरकार को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई।

दहेज एक दानव है जिसे नष्ट करना देश के आम नागरिक का कर्तव्य है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अन्तिम दम तक संघर्ष किया जिसे हमारे देश की महिलायें कभी भी नहीं भूल सकती हैं।

महिलाओं को समाज में अपना स्थान बनाना है तो उसके लिये स्वयं को ही आगे आना होगा और इसके लिये संघर्ष करना होगा। संघर्ष जब ही किया जा सकता है जब कि महिलायें अधिक से अधिक साक्षर होंगी।

हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी की सरकार ने इन्दिरा जी के सपनों को साकार करने के लिये एवं देश की महिलाओं का स्तर ऊँचा उठाने के लिये उच्च माध्यमिक कक्षा तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं के लिये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करके जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। मनु ने कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं।

×

राष्ट्रीय एकता एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी

हमारा देश एक संघात्मक गणराज्य है। संविधान में इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में इस शब्दावली के प्रयोग से कुछ लोगों में केन्द्र राज्य संबंधों के विषय में शंकाएँ पैदा हुई हैं। वास्तव में हमारा देश संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह राज्यों का संघ नहीं है। क्योंकि वहाँ राज्य पहले बने और देश बाद में बना। इन राज्यों ने अपने अधिकारों का कुछ अंश एक सार्वभौम केन्द्र को देकर संघ राज्य का गठन किया था। वहाँ केन्द्र की शक्ति सीमित है। शेष अधिकार राज्यों के पास हैं।

भारत निश्चित भौगोलिक सीमाओं और प्राचीन संस्कृति वाला देश है इसमें राज्य घटते बढ़ते रहे, लेकिन भारत की मूल एकता हमेशा कायम रही है। हमारे देश में अनेक बार बड़े बड़े साम्राज्य बने। लेकिन इन शासकों ने कभी भी सभी राज्यों के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया। अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे देश के अन्दर एकात्मक शासन था, लेकिन उस समय भी देशी रियासतें थी। इन राज्यों के द्वारा केन्द्र को केवल विदेश नीति, संचार और सुरक्षा के विषय ही दिए हुए थे।

जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य समाप्त होने का समय आया तब मुस्लिम लीग ने पहले कमजोर संघात्मक केन्द्र की बकालात शुरू की। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि मुस्लिम बहुल राज्यों पर केन्द्र सरकार का प्रभाव कम से कम रहे। बाद में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अलग करने की मांग उठाई जिसका प्रभाव यह हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। तब खंडित भारत की संविधान सभा ने भारत को संघात्मक राज्य तो बनाया लेकिन केन्द्र और राज्यों के संबंधों के विषय में ऐसी व्यवस्था की जिसमें केन्द्र मजबूत रहे और कोई भी राज्य देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा न बन सके। इसलिए हमारे देश का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक केन्द्र की ओर झुका हुआ है।

हमारे देश के संविधान में कुछ अधिकार केन्द्र को दिए हुए हैं, कुछ राज्यों को और कुछ पर दोनों का अधिकार माना है बचे हुए अधिकार केन्द्र के पास हैं। जिन विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों का अधिकार है, उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित कानून या फैसले को राज्य द्वारा पारित कानून अथवा फैसले पर वरीयता देने की व्यवस्था है।

केन्द्र और राज्य के संबंधों की यह संवैधानिक व्यवस्था पिछले 39 वर्षों से चल रही है। परन्तु कुछ समय से केन्द्र और राज्यों के संबंधों को लेकर किसी किसी स्थान पर मन मुटाव पैदा हुए हैं और कुछ राज्यों के कुछ लोग अपने अपने राज्य के लिए ऐसे अधिकार मांगने लगे हैं जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होने की संभावना हो गयी है। इस कारण से केन्द्र और राज्यों का संबंध और राष्ट्रीय एकता एक नाजुक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है।

किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता का मूल आधार लोगों की भावात्मक एकता होती है, राज्यों या केन्द्र के अधिकार नहीं। भावात्मक एकता का आधार समान आस्थायें और भावनायें होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से राष्ट्रवाद कहा जाता है।

जिस देश में राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होती है, वहां केन्द्र और राज्यों के संबंध कुछ भी हों, राष्ट्र की एकता के लिए खतरा पैदा कर देते हैं और जिस देश में राष्ट्रवाद की भावना प्रखर हो वहां केन्द्र और राज्यों के संबंध कुछ भी हों, उस देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा नहीं होने देते हैं। इसलिए केन्द्र और राज्यों के संबंधों को राष्ट्रीय एकता के प्रश्न से जोड़ना ठीक नहीं है। राष्ट्रीय एकता का संबंध संवैधानिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना के साथ अधिक होता है।

हमारे देश में उन्हीं राज्यों ने केन्द्र के साथ संबंधों को राष्ट्रीय एकता का मुद्दा बनाया है जहां किन्हीं कारणों से राष्ट्रीय भावना कमजोर है या बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। इसकी शुरुआत जम्मू-कश्मीर राज्य से हुई। इसका कारण यह था कि शेरे-कश्मीर स्व० शेख अब्दुल्ला भारतीय राष्ट्रीयता से अलग कश्मीरी राष्ट्रीयता को वरीयता देते थे। इसी कारण से स्व० शेख अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की अलग पहचान बनाए रखने के लिए इस राज्य को संविधान में विशेष दर्जा देने की मांग की थी। कश्मीर संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों का श्री शेख अब्दुल्ला ने लाभ उठाया।

भारत सरकार ने देश, काल और वातावरण के अनुसार जम्मू-कश्मीर को भारत के संविधान की अस्थाई धारा 370 का लाभ दिया। उस वक्त संविधान सभा ने यह आश्वासन दिया था कि यह धारा अधिक समय तक संविधान का अंग नहीं रहेगी और कश्मीर को भी केन्द्र के साथ संबंधों के बारे में दूसरे राज्यों के स्तर पर लाया जायेगा। इस कारण से संविधान में इस धारा को अस्थाई धाराओं वाले अध्याय में रखा गया।

कश्मीर में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना दूसरे राज्यों की तुलना में पनप नहीं पाई और वहां के लोगों का इस अस्थायी धारा को बनाये रखने में स्वार्थ पैदा हो गया। इसी कारण से अन्य राज्यों में भी अलगाववादी तत्त्व विदेशी ताकतों के इशारों पर अपने अपने राज्यों के लिये विशेष दर्जा और केन्द्र के अधिकार सीमित करने की मांग उठाने लगे हैं। अकाली दल का आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव भी धारा 370 की ही देन है तथा श्री लालडेंगा भी मिजोरम के लिये धारा 370 की जैसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जो कि राष्ट्रहित में नहीं है। यदि केन्द्र और राज्यों के संबंधों को राष्ट्रीय एकता का मुद्दा बनने से रोकना है तो सबसे पहले इस अस्थाई धारा 370 को संविधान से अलग करना होगा। एक ही देश में केन्द्र और राज्यों के बीच दो अलग अलग व्यवस्थायें नहीं चल सकती हैं।

देश के अन्दर राज्यों का बहुत बड़ा या छोटा होना भी केन्द्र राज्य संबंधों पर गलत प्रभाव डाल सकता है और यह देश की एकता और अखण्डता को भी चोट पहुंचा सकता है।

भारत में उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण से इसका प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्य सभा में सबसे अधिक है। इसके सभी प्रतिनिधि यदि मिलकर दबाव डालें तो वे केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश के प्रति अधिक अनुकूल रवैया अपनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यही स्थिति बिहार और कुछ अन्य राज्यों की भी है। प्रशासन और सम्यक् आर्थिक विकास के लिए भी बड़े राज्य उपयुक्त सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिये केन्द्र और राज्यों के संबंधों में तनाव कम करने, केन्द्र को शक्तिशाली बनाने, आर्थिक विकास की गति तेज करने और राष्ट्रीय एकता को बल देने के लिये बहुत बड़े बड़े राज्यों का पुनर्गठन करना भी अत्यन्त आवश्यक है।

पिछले 35 वर्षों के अनुभव से यह लगने लगा है कि केन्द्र और राज्य के अधिकारों और आय के स्रोतों के बंटवारे के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की

आवश्यकता है। राज्यों के पास आय का साधन कम है और विकास की जिम्मेदारियाँ अधिक हैं। इसलिये राज्यों के पास आय के अधिक स्रोत देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ कुछ मामलों में केन्द्र को देश, काल और वातावरण के अनुसार बहुत ही अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

इन विभिन्न कारणों से केन्द्र और राज्य के बीच सम्बन्धों पर पुनर्विचार करने के लिये हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के हित में तथा देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिये न्यायाधीश श्री आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। यह आयोग केन्द्र राज्यों के बीच सम्बन्धों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन आने तक इस विवाद को किसी भी प्रकार के आंदोलन का मुद्दा बनाना राष्ट्रीय हित में उचित नहीं है।

हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी एवं शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हरचन्दसिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब समस्या पर समझौता हुआ है। उस समझौते के अन्तर्गत आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव सरकारिया आयोग को सौंपने पर सहमति हो गई है। अधिकतर राज्यों ने मजबूत केन्द्र की ही वकालत की है।

>

फिल्म उद्योग और श्रीमती इन्दिरा गांधी

श्रीमती इन्दिरा गांधी की फिल्मों के प्रति गहरी दिलचस्पी थी। इस दिलचस्पी का कारण यह था कि वे मानव जीवन के संबंध में फिल्मों से जानकारी प्राप्त करती थी। उन्हें फिल्मों के सम्बन्ध में गहरी जानकारी थी। अपनी राजनैतिक व्यस्तता के बावजूद वीडियो पर फिल्में अवश्य देखती थीं। जब सन् 1965 में हमारे देश के अन्दर फिल्म समारोह हुआ तो वे कुछ समय पूर्व ही सूचना एवं प्रसारण मन्त्री बनाई गई थीं। इस मन्त्री पद पर होते हुए उस अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जाने वाली फिल्मों के पुरस्कारों के स्वरूप एवं जूरी का चयन करने का कार्य उन्होंने स्वयं अपने हाथों से किया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की अच्छे फिल्म कलाकारों के बारे में जानकारी का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्होंने रिचर्ड एटनबरो को गांधी फिल्म बनाने का अवसर प्रदान किया। भारत के सभी बुद्धिजीवियों ने उस समय उनके इस कदम की कड़ी आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि एक विदेशी को गांधी फिल्म बनाने का अधिकार देना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ अन्याय करने के समान है। लेकिन जब गांधी फिल्म बनी तो सभी बुद्धिजीवियों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के निर्णय की सराहना की और कहा कि उनका निर्णय सही था। एटनबरो की गांधी फिल्म राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और मूल्यों को सारे विश्व में प्रचारित करने का बहुत ही अच्छा माध्यम साबित हुआ। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फिल्म उद्योग के विकास के लिये सूचना और प्रसारण मन्त्री के पद पर रहते हुए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये। प्रधान मन्त्री बनने के बाद फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन के माध्यम से अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिये ऋण भी प्रदान किये गये तथा उच्च स्तरीय फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों ने भी प्रेरणा दी। चाहे श्रीमती गांधी देश की राजनीति से प्रभावित रहें पर उन्होंने अच्छी फिल्मों के निर्माण में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचायी। इसका प्रमाण यह है कि "आक्रोश" जैसी फिल्म हमारे देश में बनकर तैयार हुई जो स्पष्टतः शासन तंत्र पर व उसके संचालकों पर खुले रूप से प्रहार करती है, यहां तक कि

यह फिल्म नक्सलवादियों के प्रति सहानुभूति भी जगाती है। सबका इस बात का आश्चर्य है कि श्रीमती गांधी सरकार ने इस फिल्म को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। सत्यजीत रे ने आपातकाल का विरोध किया पर श्रीमती गांधी उन्हें पूर्ववत् भारत का गौरव मानती रही और सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करती रही।

अच्छी फिल्में, अच्छे फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं कलाकार उनकी निगाह में थे। फिल्म अभिनेत्री, स्मिता पाटील को फ्रांस द्वारा सम्मानित करने पर श्रीमती गांधी इतनी अभिभूत हुयी थीं कि इसे प्रकट करने के लिये पेरिस जाने से पूर्व स्मिता पाटील को विशेष डिनर पर बुलाया था। इससे पूर्व गांधी फिल्म की पूरी यूनिट को निजी डिनर पर बुलाया था। कलाकारों के विकास के लिये वे हमेशा रुचि लेती थीं।

अच्छी तथा प्रेरणादायक फिल्म बनाने वालों को यह कहकर प्रोत्साहित करती थीं कि अच्छी फिल्मों के निर्माण से ही जनता का ध्यान फिल्मों की ओर आकर्षित होगा। जब फिल्म निर्माता जी. पी. सिप्पी एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर मिले थे तब श्रीमती गांधी ने कहा था कि "मनोरंजन एक सामाजिक दायित्व है जिसे पूरा करना आप लोगों का कर्तव्य है।"

उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को शुरू से ही फिल्मों से प्रेम था। यह सुविदित है कि श्रीमती गांधी अपनी हत्या से पूर्व प्रख्यात फिल्म निर्देशक व अभिनेता पीटर उस्तीनोव के पास जा रही थी जो प्रधानमंत्री निवास के लॉन में बैठे थे और जो श्रीमती गांधी पर फीचर फिल्म बना रहे थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने अच्छी फिल्मों के निर्माताओं को प्रोत्साहित किया तथा अच्छे कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिये कारगर उपाय किये क्योंकि अच्छी फिल्मों के माध्यम से देश के नागरिकों को अनौपचारिक शिक्षा दी जा सकती है।

फिल्मों के माध्यम से ही देश के नागरिकों का मानसिक विकास सम्भव है। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फिल्म उद्योग के विकास के लिये जो अनुकूल कदम उठाये उससे फिल्म उद्योग को ही फायदा नहीं हुआ बल्कि देश के आम नागरिकों को भी इसका फायदा मिला। जिसे हमारे देश के नागरिक कभी भी नहीं भूल सकते हैं।



विदेशी व्यापार और श्रीमती इन्दिरा गांधी

वर्तमान युग में जिस प्रकार से व्यक्ति का आत्मनिर्भर रहना सम्भव नहीं रहा है, उसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र पूर्णतः स्वनिर्भर नहीं रह सकता है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा करने का प्रयास करता है तो अन्त में उसे इरादा बदलना ही पड़ता है। पूर्ण स्वनिर्भरता से उस देश के निवासियों का जीवन स्तर पर्याप्त रूप से ऊँचा नहीं हो सकता। यही कारण है कि कोई राष्ट्र अपने यहां जो वस्तुएँ दूसरे देशों की तुलना में कम लागत पर बनाता है, उनमें से वह अपने उपयोग की वस्तुएँ रखकर शेष बची वस्तुएँ विदेशों को भेजकर उसके बदले में दूसरी वस्तुएँ मंगाता है जो या तो उस देश में तुलनात्मक अधिक लागत पर बनती हैं या उस देश में निमित्त नहीं हो पाती हैं। ऐसा करने से देश में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग होने लगता है। विदेशी व्यापार होने के दो आधारभूत कारण हैं। प्रथम, इसमें विदेशों से वे वस्तुएँ मंगायी जा सकती हैं जो देश में नहीं बनायी जा सकती जो देश में बनायी तो जा सकती हैं लेकिन विदेशों में कम लागत पर मिल जाने के कारण इन वस्तुओं का देश में उत्पादन नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी करने के लिये रुपये का अवमूल्यन 36.5 प्रतिशत की दर से किया जो कि राष्ट्र हित में एक उचित निर्णय था। लेकिन इसका विशेष लाभ नहीं हुआ। सन् 1968-69 से देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ। सन् 1971-72 में व्यापार शेष की प्रतिकूलता पुनः बढ़कर 216.32 करोड़ रुपये हो गयी। सन् 1972-73 में व्यापार शेष देश के पक्ष में 103.39 करोड़ रुपये हो गया। सन् 1973-74 में खाद्य संकट के साथ ही पेट्रोलियम संकट का सामना करना पड़ा जिससे यह प्रतिकूलता

पुनः बढ़ गयी । सन् 1976-77 में व्यापार शेष 68.46 करोड़ रुपये से हमारे पक्ष में रहा ।

सन् 1977 में हमारे देश में जनता पार्टी की सरकार बनी । इस सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार से व्यापार शेष हमारे देश के पक्ष में 68.46 करोड़ रुपयों से पक्ष का परिणाम प्राप्त किया था । लेकिन एक वर्ष में ही सन् 1977-78 में व्यापार शेष 621.03 करोड़ रुपयों से प्रतिकूल हो गया जो कि एक राष्ट्र हित में उचित परिणाम नहीं था ।

□

वन और श्रीमती इन्दिरा गांधी

हमारे देश में वनों का कुल क्षेत्रफल 746 लाख हेक्टेयर है जो देश की कुल भूमि का लगभग 22.7 प्रतिशत है। भारत में प्रति व्यक्ति केवल 0.14 हेक्टेयर वन आते हैं। भारत का वन क्षेत्र न केवल अनुपात की दृष्टि से ही छोटा है वरन् हमारे देश में वन बड़े ही वेढंग रूप से फैले हैं, तथा इनकी वापिक उत्पादन क्षमता भी बहुत कम है। वन देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक वनों के ऊपर निर्भर है क्योंकि देश के अन्दर कई उद्योग घन्धे वनों से प्राप्त वनस्पति पर आधारित हैं।

वन देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। चाहे वे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, तथा जलवायु को अनुकूल बनाने में भी वन सहायता करते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में वन लगाने का जोरदार अभियान चलाया गया। जिसमें उनकी सरकार को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

यातायात के साधनों का विकास एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में यातायात के क्षेत्र में काफी प्रगति हुयी । चाहे जल यातायात हो, वायु यातायात हो या थल यातायात हो । इन तीनों ही क्षेत्रों में हमारे देश ने प्रगति की है ।

वर्तमान समय में हमारे देश के काफी गांव सड़क यातायात से जुड़ गये हैं । जिससे ग्रामीण जनसंख्या को काफी राहत महसूस हुई ।

यातायात के साधनों के विकास के बिना व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों का विकास भी सम्भव नहीं है । अगर देश को तेज गति से आगे ले जाना है तो यातायात के साधनों का समुचित विकास करना आवश्यक है ।

देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक यातायात के साधनों पर निर्भर है । जिस देश में यातायात के साधन विकसित नहीं होंगे वह देश भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता है ।

खनिज सम्पत्ति एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी

खनिज सम्पदा की दृष्टि से हमारा देश एक धनी देश है। आज के युग में हमें जो औद्योगिक विकास दिखाई देता है, वह बहुत कुछ खनिज सम्पदा के उपयोग के कारण ही सम्भव हो पाया है। नित्य प्रति जो नये आविष्कार हो रहे हैं वे पृथ्वी से प्राप्त खनिजों के कारण ही हैं।

हमारे देश के अन्दर दो प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं।

1. धातु वर्ग—इस वर्ग में आने वाले खनिजों को ताप से पिघलाया जा सकता है। इनको भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में लोह वर्ग के खनिज जैसे लोहा तथा मैगनीज दूसरे में अलौह वर्ग में ताँबा, सीसा आदि तीसरे में मूल्यवान खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लैटीनम आदि आते हैं।

2. अधातु वर्ग—इस वर्ग में आने वाले खनिजों को ताप से पिघलाया नहीं जा सकता वरन् इन्हें दूसरी चीजों में मिलाकर काम में लिया जाता है। इनको भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। इसमें ईंधन, अणुशक्ति तथा अन्य। अन्य भाग में अभ्रक, गंधक, चूना, जिप्सम, पारा आदि आते हैं।

हमारी दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने खनिज उत्पादन को बढ़ाने के लिये ठोस कदम उठाये जिसमें सरकार को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

3. खनिज अन्वेषण निगम की स्थापना—श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार ने खनिजों का गहन अन्वेषण करने के लिये सन् 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान मुख्य आधारभूत योजनाओं में अपना परामर्श तथा तकनीकी सहायता भी देता है।

पूर्व में खनिज सम्पदा का पता लगाने के लिये कई संस्थानों की स्थापना की गई थी। इन संस्थानों को गतिशील बनाने में श्रीमती गांधी सरकार का महत्त्वपूर्ण योगदान था।

ऊर्जा संकट का मुकाबला करने के लिए तथा कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने 11 अक्टूबर, 1974 को ऊर्जा मंत्रालय के अन्दर नये कोयला विभाग का गठन किया।

4. सार्वजनिक स्वामित्व में खनिज—देश में खनिज का विकास तथा उपयोग पर उचित ध्यान देने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने देश हित में जिन खनिजों को अपने स्वामित्व में लिया वे निम्नलिखित हैं—

- (1) कोलार की सोना खानों को सरकारी कम्पनी भारत गोल्ड माईन्स लि० गोरगाम, कर्नाटक ने 1 अप्रैल, 1973 से अपने हाथ में ले लिया है।
- (2) सन् 1972 में भारत सरकार ने सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया।
- (3) सार्वजनिक क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों की स्थापना की गयी।
- (4) लोहा एवं इस्पात तथा अन्य रासायनिक खनिजों के क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों की स्थापना की गयी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में ही सभी प्रकार के खनिज पदार्थों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुयी तथा देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण श्रीमती गांधी की सरकार की उपयुक्त खनिज नीति रही। खनिज उत्पादन के क्षेत्र में श्रीमती गांधी ने जो कार्य किये उन्हें हमारे देश की जनता कभी भी नहीं भूल सकती है।

□

विज्ञान और श्रीमती इन्दिरा गांधी

हमारे देश में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने का गौरव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को दिया जावेगा, जिनकी प्रेरणा से ग्यारह राष्ट्रीय प्रयोगशालायें बनी, आणविक ऊर्जा विभाग बना और वैज्ञानिकों को काम करने की सुविधायें तथा आजादी दी गयी परन्तु विज्ञान को भारतीय जनता की सेवा में सक्रिय शक्ति बनाने का श्रेय स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है। 1950-51 में भारत में वैज्ञानिक अनुसन्धान पर कुल 4 करोड़ 70 लाख रुपये व्यय हुये थे। सन् 1976-77 में इन कामों पर व्यय होने वाले धन की मात्रा 400 करोड़ रुपयों से अधिक थी। पांचवी योजना में विज्ञान और टेक्नाॅलोजी के विकास पर 1570 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित किया गया था, लेकिन 1980 से 1985 में छठी पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्र ने सार्वजनिक क्षेत्र में 3367 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान रखा था।

इस समय हमारे देश में 130 शोध संस्थान, 119 विश्वविद्यालय, 150 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, 100 मेडीकल कॉलेज, 5 केन्द्रीय टेक्नाॅलोजी संस्थान और 350 पॉलीटेक्निक हैं, जिनसे प्रतिवर्ष एक लाख पचास हजार वैज्ञानिक व तकनीशियन निकलते हैं। देश में इस समय 30 लाख वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं। इनकी संख्या की दृष्टि से भारत का संसार में तीसरा स्थान है।



श्रीमती गांधी का दृष्टिकोण

श्रीमती इन्दिरा गांधी की वैज्ञानिक प्रगति और तकनीक के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने विज्ञान को एक पृथक् साध्य मानने के साथ-साथ उसे मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक आवश्यक साधन बना दिया। जिस प्रकार से किसी योजना के परिपालन के लिये धन, जनशक्ति, कुशल प्रशासक और कुशल कारीगर आवश्यक अंग होते हैं उसी तरह विज्ञान और तकनीक की विकास का एक आवश्यक अंग बना दिया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि उन क्षेत्रों में भी, जहां हमारे पास ने साधन थे ने तकनीक थी, विज्ञान के प्रयोग से वह प्रगति हो गयी जो सारे साधनों के होते हुये भी नहीं हो सकी थी। उदाहरण के लिये कृषि के क्षेत्र को ही देखें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी थी। सिंचाई की व्यवस्था की गई, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, अच्छी किस्म के सुधरे हुये बीजों का भी इस्तेमाल हुआ परन्तु इन सबके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में केवल चार दशमलव एक प्रतिशत की ही वृद्धि हुयी। दूसरी योजना और तीसरी योजना में तीन प्रतिशत की ही वृद्धि हुयी। हमारे देश की जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही थी और यदि एक भी अकाल पड़ जाता तो राष्ट्र की अनाज के मामलों में पश्चिमी देशों के सम्मुख हाथ पसारना पड़ता था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनीं तब विहार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अन्य राज्यों में भी सूखा पड़ा। जिससे खाद्य स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गयी। इस विगड़ी हुई खाद्य स्थिति का मुकाबला करने के लिये संकर किस्म के गेहूं के बीजों का प्रयोग किया गया। पहले यह प्रयोग केवल चालीस हेक्टेयर में किया गया, लेकिन इसके बाद यह प्रयोग इतना सफल हुआ कि गेहूं का उत्पादन प्रतिशत में नहीं, गुणा में बढ़ने लगा। गेहूं का उत्पादन सात गुना हो गया। जिस प्रकार से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुयी उसी प्रकार से अन्य फसलों

के उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुयी। भारत अन्न के मामले में आत्म-निर्भर देश बन गया। हमारे देश का गेहूं और चावल दूसरे देशों को निर्यात होने लगा तथा गरीब देशों के अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिये जाने लगा। भारतीय किसान सम्पन्न हुआ, उद्योगों की उन्नति हुई। क्रय शक्ति बढ़ी, रहन सहन और जीवनयापन के ढंग में परिवर्तन भी आया।

मानव सेवा के लिए विज्ञान

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में विज्ञान का प्रयोग मानव सेवा के लिये किस प्रकार से किया गया, उसके दो बड़े सटीक उदाहरण हैं हमारा अन्तरिक्ष कार्यक्रम और अणुशक्ति कार्यक्रम। तारापुर में पहला आणविक विजलीघर स्थापित किया गया, जिससे गुजरात एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विजली पहुंची उद्योगों और कृषि की उन्नति हुई। लेकिन यह विजलीघर अमेरिका सरकार के सहयोग से तथा अमेरिकन इंजीनियरों के द्वारा हमारे देश में स्थापित किया गया था इस विजलीघर का ईंधन भी अमेरिका से आता था और अब भी विदेशों से ही आता है।

राजस्थान के अन्दर कोटा में भी आणविक विजलीघर बना। जिसके बहुत से हिस्से कनाडा से आयात किये गये। लेकिन इसमें भारतीय इंजीनियरों का महत्वपूर्ण योगदान था तथा इसमें ईंधन भी भारत का प्राकृतिक यूरेनियम था। कोटा का दूसरा आणविक विजलीघर बना जिसमें हमारे देश ने अधिक आत्मनिर्भरता दिखाई। इसके बाद मद्रास में कलपक्कम में जो विजलीघर बना वह पूर्ण रूप से भारतीय इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया था और उसमें काम आने वाला ईंधन भी हमारे देश ने ही उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश में तरौरा में एक ऐसा विजलीघर और खड़ा हो रहा है जिसमें जितना ईंधन लगेगा, उससे अधिक निकलेगा। इन विजलीघरों को चलाने के लिये भारी पानी (हैवी वाटर) के कारखाने भी लग चुके हैं।

भारत ने अन्तरिक्ष आयोग की स्थापना की और सन् 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को अन्तरिक्ष में भेजा उसके बाद भास्कर-1, भास्कर-2 व रोहिणी आदि उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजे। इन सब का डिजाइन व निर्माण भारत में ही हुआ था। इस प्रगति को देख कर कई देशों ने कहा था कि भारत अपनी गरीबी की समस्या को हल क्यों नहीं करता, इस प्रकार के महंगे प्रयोग क्यों करता है। किन्तु भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिये ये सब परमावश्यक थे।

जून 1981 में एप्पल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया और उसके द्वारा दो वर्ष तक डाक और तार विभाग ने अपनी बहुत सी सेवाओं में सुधार किये तब अंतरिक्ष कार्यक्रम की मानव कल्याण के लिये उपयोगिता सिद्ध होने लगी। इन्सेट-1 वी अमेरिका से 31 अगस्त, 1984 को छोड़ा गया। वह आज भी न केवल भारत के सैकड़ों टेलीविजन केन्द्रों को तत्काल कार्यक्रम पहुंचाने में सहायता करता है वल्कि सैकड़ों टेलीफोन और टेलेक्स की लाइनें भी इस इन्सेट-1 वी के कारण दूर दराज के क्षेत्रों को सैकण्डों में मिला देता है। अब भविष्य के लिये यह सोचा जा रहा है कि इसके द्वारा समाचार ऐजेन्सियां अपने समाचार और चित्र भारत के प्रत्येक कोने में किसी भी भाषा में देने के अन्दर समर्थ हों और इस प्रकार अन्य देशों की भाषा और विदेशी मशीनों से हमारे देश की निर्भरता समाप्त हो।

इसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा को भारत और सोवियत संघ की संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान में दो सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोवियत उपग्रह में भेजा गया। उन्होंने वहां से भारत के जो चित्र लिये हैं वे हमारे कृषि, खनिज तथा अन्य क्षेत्रों के लिये उपयोगी हैं। आज तो भारत में मौसम इन्सेट वी द्वारा भेजे गये चित्रों से ही प्राप्त होता है और आने वाली काली आंधियों, तूफानों और बरसातों का बहुत पहले पूर्वानुमान हो जाता है।



वैज्ञानिक आत्म-निर्भरता

श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रेरणा से भारत ने अण्टार्क्टिका में कदम रखा और अब हमारा दल प्रति वर्ष वहां जाता है। समुद्र विकास विभाग की स्थापना से अब हमारा देश समुद्र से प्राप्त खनिजों को बाहर निकालने में समर्थ हुआ है जिससे प्राकृतिक सम्पदा का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। समुद्र से हम लोग इस काल में तेल निकालने में सफल ही नहीं हुये, बल्कि इतने समृद्ध हो गये हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा पर जो दबाव पड़ रहा था वह बहुत कम हो गया है।

वर्तमान में तो हमारा देश दूसरे देशों को तेल निकालने में सहायता भी देने लगा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 16 जनवरी, 1984 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर कहा था, “ग्रामीण भारत विज्ञान का प्यासा है। ग्रामीण भारत के पास वैज्ञानिकों के उपयोग के लिये उपलब्ध सामग्री की अथाह क्षमता है। हमारे वैज्ञानिकों को इन आवश्यकताओं के लिये कुछ जरूर करना होगा”।

श्रीमती इन्दिरा गांधी वैज्ञानिकों का सम्मान करती थी इसलिये सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की सलाह पर विज्ञान और तकनीक का नया विभाग ही नहीं बनाया, बल्कि अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग, समुद्री विकास विभाग और पर्यावरण विभाग भी बनाये तथा गैर परम्परागत ऊर्जा के लिये भी एक अलग विभाग बनाकर उन में वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित किया। मन्त्री मण्डल के सहयोग के लिये एक वैज्ञानिक समिति बनायी और एक विज्ञान परामर्शदात्री समिति बनाई गई।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में कृषि, चिकित्सा, उद्योग, ऊर्जा, तेल, गैस और प्रतिरक्षा मन्त्रालयों में वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के ऐसे उल्लेखनीय काम हुये कि हमारा देश प्रतिरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो गया । तोप, टैंक, विमान, मिसाइल तथा राडार जैसे उपकरण बनाने में देश आत्म-निर्भर हुआ । इससे न केवल हमारे सैनिकों में बल्कि सारे देश के नागरिकों में आत्म-विश्वास बढ़ा और वह मनोबल पैदा हुआ जो किसी राष्ट्र को स्वाधीन रखने के लिये और शक्तिशाली बनाने के लिये बहुत आवश्यक है ।



कला एवं साहित्य और श्रीमती इन्दिरा गांधी

श्रीमती इन्दिरा गांधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। प्रत्येक महान नेता एक राजनीतिक इन्सान नहीं होता, उसके विचरण के क्षेत्र बहुत से होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लेखक भी थे तथा विज्ञान में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जॉन० एफ० केनेडी, लेनिन, चर्चिल, रुजवेल्ट, माओ इनमें कोई ऐसा नहीं था जिसका लगाव सिर्फ राजनीति तक सीमित रहा हो।

लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी के मामले में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह राजनेतावाद में बनी नियति के चमत्कार से बनी, किसी योजना या स्वप्रेरण से नहीं। श्रीमती गांधी सबसे पहले सौन्दर्याभिलाषिणी थी। सन् 1960 तक उनकी रुचियों का क्षेत्र राजनीति से बहुत हट कर था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सन् 1977 में अपने परिचितों को मुद्रित करा करके एक पुर्जा भेजा था। जिसमें लिखा था कि “मैं एक नृत्यांगना बनना चाहती थी, मैं पर्वतों पर, एक लम्बी दोपहर की तरह जीवन बिताना चाहती थी, मैं जंगलों में हरी छायाओं में चलती जाना चाहती थी। मगर नियति ने.....” इस कविता से स्पष्ट होता है कि यह एक कलाकार का प्रलाप था।

सन् 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद श्री लालबहादुर शास्त्री ने इन्दिरा जी की रुचियों को पहचानते हुये उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्य सौंपा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम सम्भाला उस समय इस विभाग की भूमिका स्पष्ट नहीं थी और दूर दर्शन की तो कोई कल्पना ही नहीं थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी समस्या की जड़ तक गयी उनकी मान्यता थी कि शिक्षा और मनोरंजन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । शिक्षा से अलग होकर मनोरंजन भोंडा और मूल्यहीन होगा और मनोरंजन से अपना नाता तोड़कर शिक्षा निष्प्राण और हृदयहीन होगी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नया, प्रयोगशील और अर्थवान व्यक्ति को महत्व दिया । श्रीमती गांधी के सूचना और प्रसारण मन्त्री रहते हुये नई फिल्मों को मान्यता मिली, सत्यजीतराय का सम्मान बढ़ा, फिल्मों को सरकारी ऋण और सहायता का फंसला लिया गया और सेंसर बोर्ड का ढांचा व्यापक और नीति उदार की गयी ।

कला से अगाध प्रेम

श्रीमती इन्दिरा गांधी का पश्चिमी वाख प्रिय संगीत रचनाकार था और चित्रकला पिकासो, मातीस, मिरो, वैनगाग में थी, उतनी दिलचस्पी उनकी भारतीय संगीत और लोक संगीत कलाओं में थी । उनकी मान्यता थी कि आधुनिक कला रूपों और लोक कलाओं में आश्चर्यजनक समानता है ।

सन् 1982 में भोपाल में आधुनिक एवं आदिवासी कला के समानान्तर संग्रह और प्रदर्शन से वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुई । कई स्थानों पर जिक्र किया, यहां तक की कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में भी उन्होंने इन संग्रह का उल्लेख किया और आदिवासी कला तथा आधुनिक कला रूपों की समानता पर टिप्पणी करते हुये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा यह समानता इस बात की परिचायक है कि कोई भी कला रूप पहले से ही स्थित एवं वर्तमान होता है । आधुनिक कला जिन रूपों का संघान कर रही है वे संयोगवश नहीं, नियमानुसार आदिम एवं आदिवासी कला में मौजूद है ।

सन् 1966 में प्रधानमन्त्री निर्वाचित होने के कुछ समय बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी से एक छोटे से समारोह में श्रीकांत वर्मा ने इधर के साहित्य की चर्चा की तब श्रीमती गांधी ने आधुनिक भारतीय साहित्य में अपना रुझान जाहिर करते हुये कहा, "मैं अत्यधुनिक भारतीय लेखन से बहुत परिचित नहीं हूं" । इसके कुछ ही दिनों पश्चात् उनकी सचिव, कुमारी उषा भगत का पत्र और फोन श्री कांत वर्मा के पास आया कि प्रधानमन्त्री आधुनिक लेखकों से मिलना चाहती है ।

वताया गया था कि प्रधानमन्त्री सिर्फ चालीस मिनट तक रहेंगी। मगर वह उपस्थित लेखकों के साथ लगभग ढाई घण्टे तक चर्चा करती रही। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने लेखकों की जवान में लेखकों से बात की। कहीं भी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लेखकों को यह आभास नहीं होने दिया कि वे पहले प्रधान मन्त्री हैं, वाद में कुछ और।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्रीमती गांधी ने लेखकों से उन तमाम विषयों पर बातचीत की और सवाल किये जो उन दिनों साहित्य में प्रासंगिक माने जाते थे।

यह सत्य है कि कला की चर्चा आने पर, वह एक कलाकार की जवान बोलती थी। वह इससे वाकिफ थी। अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष उन्होंने कलाकारों और साहित्यकारों के बीच बिताये थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने पिता श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ बीसवीं शताब्दी के प्रमुख बुद्धिजीवियों और लेखकों से मिलती रही थी। अभिनेता स्व० चार्ली चैप ने अपनी आत्मकथा में श्रीमती इन्दिरा गांधी से अपनी छोटी सी मुलाकात का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, "लेडी माउण्टवेदन ने मुझे सूचित किया कि श्री जवाहरलाल नेहरू शीघ्र ही स्वीटजरलैण्ड आ रहे हैं। क्या ही अच्छा हो, मैं उनसे मिलूँ। मैं उनसे तथा उनकी पुत्री इन्दिरा से, जो उनके साथ थी, मिला। हम दोनों और जवाहरलाल नेहरू एक कार में थे और श्रीमती इन्दिरा गांधी दूसरी कार में, हमारी कार 70 मील की रफ्तार से दौड़ रही थी और उत्तनी ही तेजी से नेहरू जी के विचार। एक जगह जाकर के गाड़ी रुकी और मैंने देखा नेहरू की आंखें चमकी। उन्होंने इन्दिरा गांधी को विदा दी, जो कहीं और जा रही थी। उन्होंने एक पिता की तरह अपनी बेटी को गले लगाते हुये कहा, "अपना ध्यान रखना" मैंने गौर किया ये एक पिता के शब्द थे।

रोमै रोलां ने भी अपनी डायरी में श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ अपनी मुलाकातों का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध लेखक श्री जैनेन्द्र ने "रोमै रोलां का भारत" ग्रन्थ प्रधानमन्त्री निवास पर आयोजित एक छोटे से समारोह में, श्रीमती इन्दिरा गांधी को भेंट किया। इस अवसर पर श्रीमती गांधी ने कहा, रोमै रोलां की मेरे मन में अनेक स्मृतियां हैं। स्वीटजरलैण्ड में हमारा मकान रोमै रोलां के मकान से बहुत दूर नहीं था। मैं छोटी थी। अक्सर अपने पिता के साथ उनसे मिलने जाया करती थी।

हमारे देश में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विचारधारा और साहित्य को लेकर एक लम्बे अर्से से बहस होती रही है । किस हद तक विचारधारा साहित्य की बनावट में भूमिका अदा करती है । क्या साहित्य का मूल्यांकन विचार-धाराओं के आधार पर किया जाना चाहिये ? क्या विचारधारा से मुक्त साहित्य अधिक दिनों तक टिक सकता है ?

यह कितना बड़ा व्यंग्य है कि साहित्यकारों के मन में अब भी इन प्रश्नों को लेकर धुन्ध है लेकिन श्रीमती गांधी के मन में कोई शंका नहीं थी । कम से कम मूल्यांकन के प्रश्न को लेकर । वह आश्चर्य की विचारधारा के आधार पर मूल्यांकन संभव नहीं है ।

फिल्म निदेशक स्व० ऋत्विक् घटक को जब पद्मश्री का सम्मान दिया गया था । उस पर संसद एवं समाचार पत्रों ने तीव्र आपत्तियां प्रकट की थी । यह आपत्तियां इसलिये प्रकट की गयी थी कि उन्होंने महात्मा गांधी को “सूअर का बच्चा” कहा था । ऋत्विक् घटक शराबी था अण्ट-सण्ट बकना उनके स्वभाव में था । शराव पीकर कह दिया होगा, उन्होंने गांधी जी को “सूअर का बच्चा” स्वयं गांधी जी मौजूद होते तो भी इस बात को इतना महत्व नहीं देते ।

लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरोधियों ने ऋत्विक् घटक की टिप्पणी का छड़ी की तरह इस्तेमाल किया । श्रीमती गांधी ने संसद में इतने बड़े प्रचारतंत्र को यह कह कर निरस्त कर दिया कि हमने ऋत्विक् घटक की विचारधारा का नहीं, कला का सम्मान किया है ।

अपने विरोधियों का आदर करना श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्वभाव में था । लेकिन कलाकारों और साहित्यकारों को उन्होंने कभी भी अपना विरोधी नहीं माना ।

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी सन् 1980 में प्रधानमंत्री बनी तब वह अनेक लेखकों, चित्रकारों और बुद्धिजीवियों से मिली जो एक अर्से से उनके विरोध में थे ।

कला और साहित्य के विषय में उनकी निश्चित मान्यतायें थी । उनका पक्का विश्वास था कि अधिनायकवादी व्यवस्था में कला का विकास नहीं हो सकता है । ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं, जो आज भी यह कहेंगे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं एक अधिनायक थी । लेकिन यह एक गलत और बेबुनियाद धारणा है ।

अधिनायक सबसे पहले कला का गला घोटता है तथा कवियों और साहित्यकारों को सूली पर चढ़ाता है ।

जो लेखक और कलाकार आपातकाल की तुलना यूरोपी नाट्यी शासन से करते हैं, वे सिर्फ एक रोमान्टिक भावना से पीड़ित हैं । वे नहीं जानते कि फासिज्म क्या होता है । यह दूसरी बात है कि आपातकाल के दौरान अनेक अनाचार हुये ।

आपातकाल के साथ ही लागू की गई थी सेंसरशिप । आपातकाल और सेंसरशिप दोनों को लेकर 1977 में अपदस्थ होने के बाद इन्दिरा जी ने लोगों से अनेक बार क्षमा याचना की ।

सन् 1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि मैं तो शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं थी मगर मेरे साथियों ने मुझ पर दबाव डाला और प्रेस बिल स्वीकार करना पड़ा ।

कहा जा सकता है, बाद में तो सभी पश्चाताप करते हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने क्या किया ?

आपातकाल कुछ समय पहले लागू हुआ ही था । समाचार आने लगे कि न केवल समाचार बल्कि कवितायें और कहानियां भी सेंसर की जा रही हैं । यह सच भी थी जो तन्त्र हमने बनाया है उसमें यही सम्भव था । यह तन्त्र पटवारी, क्लर्क और कान्सटेबल चला रहे हैं । उन पर किसी की हुकुमत नहीं । वे जैसा चाहते हैं, करते हैं और सम्भव है क्लर्कों ने कवितायें सेंसर की हों ।

प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीकांत वर्मा के नेतृत्व में साहित्यकारों और प्रकाशकों का एक प्रतिनिधि मण्डल श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला और अपनी समस्या उनके सामने रखी । श्रीमती गांधी ने साहित्यकारों की शिकायतें गौर से सुनी फिर कहा, मैं जरूर इस मामले में कार्यवाही करूंगी ।

दूसरे दिन जब श्रीकांत वर्मा उनसे मिले, तब उन्होंने पूछा, “क्या यह सही है कि कवितायें सेंसर की जा रही हैं ? अगर यह सच है तो चिन्तनीय है । यह कैसे सम्भव है ? केन बी सेंसर ताजमहल ?” श्री वर्मा ने कहा, “यू केन रिमूव ए ब्रिक फ्रॉम ताजमहल एण्ड स्टिल कॉल इट ताजमहल” । श्रीमती गांधी ने कहा “यू आर रींग । इट विल नो मोर बी ताजमहल” ।

क्या सैंसरशिप पर इससे अच्छी टिप्पणी सम्भव है ? और यह टिप्पणी किसी और ने नहीं उसने की थी, जो कानूनी और नैतिक रूप से सैंसरशिप के लिये जिम्मेदार थी ।

आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय लेखक मंच के अन्तर्गत साहित्यकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया । राष्ट्रीय लेखक मंच का गठन, वैसे तो, कांग्रेस की “अभियान समिति” के मातहत हुआ था । मगर श्रीकांत वर्मा ने संयोजक के नाते उसका स्वरूप स्वतन्त्र रखा और अनेक प्रख्यात एवं तटस्थ लेखकों का सहयोग प्राप्त करने में श्री वर्मा को सफलता भी मिली ।

इस सम्मेलन में साहित्य एवं भाषा से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों पर उत्तेजक वृहत् हुई । सवाल राजनीति में जाकर नहीं उलझे अन्यथा ऐसे प्रश्नों की परिणति अक्सर दलगत हाथापाई में होती है ।

इस सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधि बहुत ज्यादा प्रसन्न थे । क्योंकि सवालों पर खुलकर बातचीत हुयी थी ।

श्रीकांत वर्मा स्वयं भी नहीं जानते थे कि प्रधानमन्त्री को इस सम्मेलन के विषय में विस्तार से जानकारी थी । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण पढ़े थे । अगले दिन श्री वर्मा के पास समाचार आये कि प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी लेखकों से मिलना चाहती हैं तथा उन्होंने लेखकों को चाय पर आमंत्रित किया है ।

आपातकाल जारी था । साहित्यकार, श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार से नाराज थे । लेकिन लगभग 60 महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों ने प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मुलाकात की । लेखकों और प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी के बीच बातचीत हुई । न तो लेखकों ने कोई कसर छोड़ी, और न ही प्रधानमन्त्री ने उत्तर देने में कोई संकोच किया ।

श्री दिलीप ण्डगांवकर ने कहा—आपने इमर्जेन्सी लागू की । इससे वाणी की स्वतन्त्रता रौंद दी गयी । लोग घुटन अनुभव कर रहे हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा, यह सही है । मैं सैंसरशिप की समर्थक कभी नहीं रही और मैं लम्बे अर्से तक वाणी की स्वतन्त्रता को स्थगित करने के पक्ष में नहीं हूँ । मेरा लोकतन्त्र में यकीन है और आप यकीन कीजिये, यह स्थिति अधिक दिनों तक बनी नहीं

रहेगी। कुछ लोग लोकतन्त्र को नष्ट करने पर आमादा हो गये थे। इसलिये इमर्जेंसी लागू करनी पड़ी।

कृष्णा वारियर ने कहा कि इमर्जेंसी से सिर्फ चापलूसों को लाभ होगा। आपके आसपास चापलूस पनपेंगे।

श्रीमती गांधी ने कहा, यह भी सही है। मगर मैं इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहती हूँ। मैं फालतू लोगों को अपने पास फटकने नहीं देती।

साहित्यकारों और प्रधानमन्त्री के बीच अधिकतर बातचीत आधुनिक साहित्य को लेकर हुयी। लेकिन भारतीय राजनीति में बहुत कम राजनेता हैं, जिनकी दिलचस्पी आधुनिक साहित्य में है। श्रीमती इन्दिरा गांधी को आधुनिक साहित्य न केवल पसन्द था, बल्कि वह उसके मुहावरे से वाकिफ थी, उसमें बात करती थी।

उस दिन लेखकों को सम्बोधित करते हुये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा, साहित्य का कोई तर्क नहीं होता। प्रत्येक रचना एक घटना होती है। प्रत्येक लेखक एक विशेष पीड़ा से लिखता है।

आधुनिक साहित्य से ही नहीं, आधुनिक चित्रकला के मुहावरे से भी वह अच्छी तरह परिचित थी। अनेक पश्चिमी एवं भारतीय चित्रकारों से उनका निकट सम्पर्क था। शांतिनिकेतन में वह नन्दलाल बोस के प्रभाव में आयी थी। प्रधानमन्त्री बनने के बाद भी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिल्ली के अनेक चित्रकारों एवं मूर्तिकारों से अपना सम्पर्क बनाये रखा। इनमें प्रमुख थे, मकवूल फिदा हुसेन, सतीश गुजराल, रामकुमार, शंखों चौधरी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमन्त्री बनने के कुछ वर्षों के भीतर ही फ्रांस की यात्रा की। पेरिस में श्रीमती गांधी ने फ्रेंच चित्रकारों को आमंत्रित किया। उन चित्रकारों में प्रख्यात चित्रकार मिरो भी उपस्थित थे। मिरो लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे। एक कौने में बैठे श्रीमती इन्दिरा गांधी को गौर से देख रहे थे और अपने आप बड़बड़ा रहे थे, क्या स्त्री है? अद्भुत है, यह स्त्री।

उसी समय उठकर श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रसिद्ध चित्रकार मिरो के नजदीक गयी और काफी देर तक उनसे बातचीत की। इससे जाहिर होता है कि, मिरो, श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये अपरिचित नाम नहीं था।

लेखकों एवं कलाकारों के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वार हमेशा खुले रहते थे । कोई भी कलाकार एवं लेखक कभी भी उनसे मिल सकते थे ।

सन् 1982 में तन्म्विमुत्तु दिल्ली आये वह जन्म से सिंहली थे । लगभग पचास वर्षों से लन्दन में रह रहे थे । उन्होंने "पोयट्री" पत्रिका का सम्पादन किया था और टी० एस० इलियट, एजरा पाउण्ड, स्टीफेन स्पेण्डर तथा डब्ल्यु० एच० आडेन की मण्डलियों में अपनी युवावस्था के दिन बिताये थे । इंग्लैण्ड के लेखकों और कवियों ने यह स्वीकार किया है कि अंग्रेजी कविता के लिये उन्होंने जितना किया, उतना किसी अमेरिकी या ब्रिटिश लेखक ने भी नहीं किया था ।

तन्म्विमुत्तु की पिछले कुछ वर्षों से भारतीय कला एवं भारतीय कविता में दिलचस्पी पैदा हुयी थी और वे उसे अन्य देशों में प्रस्तुत करना चाहते थे । इसके लिये उन्होंने 'इण्डियन काउंसिल आफ आर्ट्स' की स्थापना की थी । जिसके एक डायरेक्टर श्रीकांत वर्मा, संसद सदस्य थे ।

तन्म्विमुत्तु गुण ग्राहक थे । मगर शराब उनकी लत थी । उनकी लड़की शकुन्तला भी उनके साथ भारत आयी थी लेकिन वो भी उनको सम्भाल नहीं पा रही थी ।

थोड़े ही दिनों में तन्म्विमुत्तु ने सारा धन, वियर एवं शराब पर खर्च कर दिया । जिसे वे पानी की तरह पीते थे । जबकि उनको कई महीनों भारत में रहना था, भारत में रहते हुये भारतीय कला और कविता का संग्रह करना था ।

श्रीकांत वर्मा ने उन्हें सलाह दी कि वह प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिलें और अपनी अड़चनें उन्हें बतायें ।

तन्म्विमुत्तु ने अपनी दिक्कतों की चर्चा करते हुये श्रीमती इन्दिरा गांधी से अनुदान का अनुरोध किया । श्रीमती गांधी ने भारत सरकार के कोप से तुरन्त इसकी व्यवस्था कर दी ।

तन्म्विमुत्तु कुछ महीने बाद इंग्लैण्ड वापिस चले गये । लेकिन उनके कार्य में श्रीमती इन्दिरा गांधी की दिलचस्पी बनी रही । सन् 1982 के अन्तिम दिनों में तन्म्विमुत्तु ने प्रसिद्ध लेखक श्रीकांत वर्मा को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, "श्रीमती गांधी की ओर से लन्दन स्थित भारतीय दूतावास का एक अधिकारी मेरे कार्यालय आया था और मेरा हालचाल तथा मेरे कार्य की प्रगति के बारे में पूछकर गया है ।"

कलाकारों और लेखकों की मदद करने में श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रसन्नता होती थी। वह समय समय पर कलाकारों और लेखकों की मदद करती थी।

हमारी दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि थी। इसके विकास के लिये श्रीमती गांधी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये। जिसे हमारे देश के कलाकार, लेखक एवं चित्रकार कभी भी नहीं भूल सकते हैं।

हमारी वर्तमान सरकार ने कला और संस्कृति का विकास करने के लिये हमारी दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने एशिया का सबसे बड़ा 'इन्दिरा गांधी कला केन्द्र' की आधारशिला इन्दिरा जी के जन्म दिवस 19 नवम्बर, 1985 को रखी। जिसका लाभ देश के ही नहीं विश्व के साहित्यकारों और कलाकारों को प्राप्त होगा तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी का कला और संस्कृति के विकास का जो सपना था वो भी साकार होगा।



श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनका दर्शन

श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधानमन्त्री के पद पर इसलिये सफल हुयी कि उनका किसी न किसी महापुरुष के दर्शन में विश्वास था। दर्शन के आधार पर ही उन्होंने सत्रह वर्ष तक शासन किया तथा विकास में गति दी जिसे देशवासी कभी भी नहीं भूल सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्व की मानी हुई दार्शनिक थीं। उनके दर्शन से हमारे देश को ही लाभ नहीं हुआ बल्कि सारे विश्व को लाभ मिला। श्रीमती गांधी का दर्शन निम्न प्रकार से है—

1. प्रकृतिवादी—श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रकृति में पक्का विश्वास था उनका मानना था कि धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक जीव प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति के सहयोग के बिना धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक प्राणी अपग है। किसी भी मनुष्य की सफलता और असफलता काफ़ी हद तक प्रकृति पर निर्भर है। उदाहरण के लिए चाहे किसान हो, व्यापारी हो, उपभोक्ता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो जब तक प्रकृति सहयोग नहीं देगी तब तक इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगा।

प्रकृति के सहयोग के बिना किसान अनाज एवं चारा पैदा नहीं कर सकता है, खानों में से खनिज पदार्थ भी नहीं निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पर सम्पन्न होने वाला प्रत्येक कार्य प्रकृति पर निर्भर है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि “पहाड़ों ने मुझे हमेशा आवाज दी है”। इसी कारण से श्रीमती गांधी की अस्थिरियों को उनकी इच्छा के अनुसार गंगोत्री की बर्फीली पहाड़ियों पर उनके पुत्र एवं हमारे देश के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने विसर्जित किया।

2. **अकेले चलो**—श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी आखिरी राजस्थान यात्रा 7 अक्टूबर, 1984 को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन से शुरू की थी। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पं० श्री नवलकिशोर शर्मा ने की थी। उस समय एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को कहा कि हमारी कोई भी बात कोई भी मन्त्री नहीं सुनता है, जिससे रचनात्मक कार्य पूरे करवाने में कठिनाई महसूस होती है। श्रीमती गांधी ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि समस्याएँ अनेक आती हैं उन समस्याओं का मुकाबला धैर्य के साथ करना चाहिए। जब मैं एवं मेरी पार्टी 1977 का चुनाव हार गयी थी, उस समय बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता मुझे एवं कांग्रेस को छोड़कर चले गये थे। मैं उस समय अकेली महसूस कर रही थी लेकिन मेरा मनोबल काफी ऊँचा था इसलिए मेरी पार्टी को 1980 के चुनावों में शानदार सफलता मिली। किसी भी बड़े कार्य को अकेले चलकर पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिये जब इन्जन चलने लगता है तो डिव्वे अपने आप चलने लगते हैं।

3. **वसुधैव कुटुम्बकम्**—श्रीमती इन्दिरा गांधी का वसुधैव कुटुम्बकम् में पक्का विश्वास था। वसुधैव कुटुम्बकम् जगतगुरु शंकराचार्य के दर्शन का एक हिस्सा है। वसुधैव कुटुम्बकम् से तात्पर्य यह है कि सारे विश्व की धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी को वसुधैव कुटुम्बकम् के दर्शन पर विश्वास करने के कारण ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने दसवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का दिल्ली में अध्यक्ष चुना।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष पद पर रहते हुये उन्होंने गरीब, शोषित तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुये देशों की भलाई के लिये महत्त्वपूर्ण कार्य किए तथा शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धान्तों को सारे संसार में प्रसारित करवाया, जिसमें श्रीमती गांधी को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

उन्होंने गरीब देशों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए जीवनपर्यन्त संघर्ष किया तथा स्वयं भी “वसुधैव कुटुम्बकम्” के आदर्श पर चलती रही तथा अपने देशवासियों में भी “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना जाग्रत की जिससे हमारे देश के नागरिकों में संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना पैदा नहीं हुई। इसी वजह से

हमारे देश को सारे विश्व में सम्मान प्राप्त हुआ तथा दूसरे देशों से परस्पर सद्भावना भी बढ़ी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की विश्व राजनीति में जो भूमिका रही उसे सारे विश्व के राजनेता आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं ।

4. पक्का इरादा—श्रीमती इन्दिरा गांधी कहा करती थी, कि अगर किसी भी व्यक्ति को विकास करना हो तो उसमें कार्य को पूरा करने का इरादा पक्का होना चाहिए, जब ही उद्देश्य पर पहुंचा जा सकता है । किसी भी कार्य को पूरा करने का उद्देश्य तो सरलता से तय किया जा सकता है, लेकिन उसको पूरा करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कठिनाइयों के सम्बन्ध में गहराई से जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसके बाद ही जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने का उद्देश्य तय करना चाहिए । अगर इरादा पक्का है तो निश्चित रूप से मंजिल भी हांसिल होती है ।

5. अनुशासन—कोई भी देश जब ही उन्नति कर सकता है जब उस देश के नागरिक अनुशासन में रहें, अनुशासन के बिना उन्नति सम्भव नहीं है । अनुशासन के अभाव में असन्तोष रहता है, देश का उत्पादन गिरता है तथा देश की एकता और अखण्डता को भी खतरा रहता है ।

अनुशासन दो प्रकार का होता है । एक सकारात्मक अनुशासन तथा दूसरा नकारात्मक अनुशासन । किसी भी देश में या संस्थान में दोनों प्रकार से ही अनुशासन लाया जा सकता है । अप्रजातान्त्रिक एवं साम्यवादी देशों में नकारात्मक प्रणाली से अनुशासन लाया जा सकता है । जबकि प्रजातान्त्रिक देशों में सकारात्मक प्रणाली से अनुशासन लाया जाता है ।

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनुशासन के सम्बन्ध में कहा था, देश का प्रत्येक नागरिक सकारात्मक रूप से देश के प्रति अनुशासित होना चाहिए ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का सकारात्मक अनुशासन में विश्वास था ।

6. दूरदर्शिता—श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कई बार कहा कि जीवन के हर पहलू को दूरदर्शिता से सोचना चाहिए । जो व्यक्ति कोई भी बात दूरदर्शिता से नहीं सोचता है वह व्यक्ति जीवन के हर पहलू पर असफल रहता है ।

7. कड़ी मेहनत—श्रीमती इन्दिरा गांधी का “कड़ी मेहनत” के सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास था । कड़ी मेहनत के सम्बन्ध में भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “आराम हराम है” । किसी भी क्षेत्र में जब तक कड़ी मेहनत नहीं की जावेगी तब तक उस क्षेत्र के विकास की गति भी धीमी होगी ।



खेल और श्रीमती इन्दिरा गांधी

श्रीमती इन्दिरा गांधी का खेलों की तरफ बहुत ही अधिक रुझान था। इसी रुझान के कारण हमारे देश में सन् 1982 में एशियाड खेलों का आयोजन किया गया। भारत में एशियाड खेलों का होना इस बात का प्रमाण है कि श्रीमती गांधी देश का स्तर खेलों के क्षेत्र में ऊंचा उठाना चाहती थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का एशियाड खेलों के आयोजन के पीछे यह उद्देश्य था कि देश की युवा पीढ़ी का ध्यान खेलों की तरफ आकर्षित हो।

खेलों के स्तर में दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश ने कम तरक्की की है। अंग्रेज शासकों ने खेलों के विकास की बात कभी सोची ही नहीं। आजादी के बाद खेलों के विकास की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ।

हमारे देश में खेलों का विकास कम होने के निम्न कारण हैं—

1. गर्म जलवायु—किसी भी खेल के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त नहीं है। गर्म जलवायु के अन्दर खिलाड़ी अधिक समय तक कोई भी खेल नहीं खेल सकता है इसलिए हमारे देश के खिलाड़ी दूसरे देश के खिलाड़ियों की तुलना में कम अभ्यास करते हैं।

2. खिलाड़ियों का तुरन्त चयन—हमारे देश में खिलाड़ी शुरू से तैयार नहीं किये जाते हैं अन्य देशों में बचपन से ही खिलाड़ी को रुचि के अनुसार अभ्यास करवाया जाता है। जिससे वो खेल दुनिया में एकाएक ही कम उम्र में नाम कमा लेते हैं। जिसका उदाहरण 17 वर्ष की उम्र में बंकर के द्वारा 1985 में पुरुष विम्बलडन कप जीतना है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में भारतीय क्रिकेट टीम ने सन् 1983 में कप्तान कपिलदेव की कप्तानी में पहली बार फुडेलिशियल कप जीता। जो कि सारे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात थी। दूसरे देशों में कम उम्र से ही क्रिकेट का अभ्यास शुरू करवा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में खिलाड़ी एकाएक तैयार होते हैं इसलिए खिलाड़ियों का सही चयन नहीं हो पाता।

3. खेल संस्थानों में राजनीति—खेल संस्थानों की राजनीतिक लड़ाइयों के कारण, खेल संस्थान के पदाधिकारी खेलों के विकास के सम्बन्ध में पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं।

4. खिलाड़ियों को कम प्रोत्साहन राशि—खिलाड़ियों को अपने शरीर को सही ढंग से स्वस्थ रखने के लिए भत्ता कम दिया जाता है। इस कारण से खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि कम होती है। खिलाड़ी अपने खेल की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाता है।

5. खेल प्रशिक्षण स्थानों का अभाव—हमारे देश में खेल प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव होने के कारण खेलों का विकास कम सम्भव हो पाया है।

खेलों का विकास जब ही सम्भव है जबकि सरकार इनके विकास के लिए कारगर उपाय करे।

खेलों के विकास के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने उपयुक्त नीति बनायी है जो कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के सपनों को साकार करेगी। हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इन्दिरा गांधी के जन्म दिन पर उनकी समाधि "शांति स्थल" से राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के आयोजन की शुरुआत की है। इस प्रकार के आयोजन से अच्छे खिलाड़ियों के चयन में मदद मिलेगी जिससे देश के स्तर में भी सुधार होगा।

खेल मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। स्वस्थ नागरिक तैयार करने के लिए खेलों का विकास होना आवश्यक है। □

श्रीमती गांधी और राजस्थान

नेहरू परिवार का सम्बन्ध राजस्थान से काफी पुराना है। पण्डित मोती लाल नेहरू के बड़े भाई पण्डित नन्दलाल नेहरू खेतड़ी के दीवान थे। श्री मोती लाल नेहरू का बचपन खेतड़ी में बीता और श्री नेहरू बड़े होकर विश्व के प्रसिद्ध बैरिस्टर बने। इन पुरानी यादों के झरोखे में श्रीमती इन्दिरा गांधी अक्सर भांक लिया करती थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक जगह लिखा है—मेरे दादा जी पण्डित मोतीलाल नेहरू का लालन पालन राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर हुआ। मेरे ननिहाल के रिश्तेदार जयपुर में थे। इसी कारण मेरी मां श्रीमती कमला नेहरू कुछ समय जयपुर में रही। हम सभी को राजस्थान में घूमने का मौका मिला। मैंने अपने माता पिता के साथ और अकेले में भी राजस्थान का दौरा किया। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की बहुत सी यादें हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी शायद ही कभी इस राजस्थान राज्य को भूल पायी होंगी। श्रीमती इन्दिरा गांधी की मां श्रीमती कमला नेहरू तो जयपुर की ही थी। जयपुर के अटल हाऊस में हा वह पली और बड़ी। राजस्थान श्रीमती इन्दिरा गांधी का ननिहाल था।

इतिहास के पन्नों में लगभग एक शताब्दी पहले के पन्ने खोलें तो वे भी नेहरू परिवार का राजस्थान के प्रति जो दर्द था उसे दर्शाता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के दादा पण्डित मोतीलाल नेहरू सन् 1899 में जब योरोप यात्रा पर गये थे, उस समय भी राजस्थान में घोर अकाल की छाया मंडरा रही थी। पण्डित मोती लाल नेहरू को उस समय खेतड़ी की बहुत ज्यादा चिन्ता हुई। उन्होंने खेतड़ी के राजा साहब को एक सच्चे दोस्त की तरह सलाह देते हुये लिखा, मुझे भय है कि खेतड़ी में अकाल पड़ रहा है, आप अकाल पीड़ितों की मदद करें, अन्य मदद करने वालों को सम्मानित करें, अकाल पीड़ितों की सहायता करना अपना धर्म बना लें।

पण्डित मोतीलाल नेहरू की चिन्ता उतनी ही गहरी थी जितनी चिन्ता पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी महसूस की तथा आराम के क्षणों में भी हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने महसूस की। इसे राजस्थान के दूध का असर ही कहा जा सकता है। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने राजस्थान का दूध पिया था। श्री मोतीलाल नेहरू के लिए खेतड़ी में धाय रखी गयी थी, जिस धाय ने स्तनपान कराकर श्री नेहरू को बड़ा किया था। दूध का असर कई पीढ़ियों तक रहता है।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी राजस्थान को तहे दिल से चाहते थे तथा इस राज्य को भारत का दिल कहा करते थे। जब 1945 में श्री नेहरू ने राजस्थान की यात्रा की तो उनके दिल की कसक को महसूस किया जा सकता था। उन्होंने राजपूती वीरता और शौर्य की यादों में डूबे लोगों को चेतावनी देते हुये कहा था, “राजपूताना में आज शूरवीरता तो रही नहीं और उसकी जगह गरीबी का बोलवाला है” श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस राजस्थान यात्रा को स्वराज्य यात्रा का नाम दिया था। “भारत छोड़ो आंदोलन में वन्दी बनकर लम्बी जेल यात्रा के बाद उन्होंने यह यात्रा राजस्थान के पूर्वी द्वार अलवर से प्रारम्भ की थी। अलवर में जब एक हजार रुपये की थैली भेंट करते हुए पण्डित जवाहरलाल नेहरू को यह कहा गया कि यहां से राजपूताना शुरू होता है, इस बात का जवाब देते हुए पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, राजपूताना और भारत अलग अलग नहीं है जो कुछ भारत में होगा, उसका प्रभाव राजपूताना पर भी पड़ेगा।

इस यात्रा में उन्होंने एक जगह कहा था, इस स्वराज्ययात्रा का अन्त बहुत निकट है—मंजिल की आखिरी सीढ़ी साफ दिखाई दे रही है। लगभग दो वर्ष बाद ही हमारे देश हिन्दुस्तान ने आजादी प्राप्त करली।

हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के कई रंग देखे। एक बार जयपुर के रामनिवास बाग में रंग विरंगी जन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा—जितने रंग मुझे यहां पर देखने को मिलते हैं अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कायम रखें।

राजस्थान प्रदेश की वह रोमांचक घटना थी, जब सन् 1955 में गाडोलिया लुहारों ने चित्तोड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग में प्रवेश किया। गाडोलिया लुहारों के वंशजों ने शपथ लेकर प्रण किया था कि चित्तोड़गढ़ स्वतन्त्र न होने तक वे उसमें

नहीं लौटेंगे। आजादी का यह प्रण पूरा हो चुका था, इन गाड़ोलिया लुहारों को इस दुर्ग में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने प्रवेश करवाया था। इस दिन एक समारोह का आयोजन भी किया गया था, उसमें पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी शरीक हुये थे।

इससे पूर्व डेढ़ करोड़ जनसंख्या वाली वाईस रियासतों को एक सूत्र में बांध कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनने की कठिन प्रक्रिया चार चरणों में 30 मार्च, 1949 को पूरी हुयी और “राजस्थान” बना। इसके तीसरे चरण में रियासतों के विलय का उद्घाटन 18 अप्रैल, 1948 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने किया। राजस्थान राज्य ने पहले आम चुनाव में मतदान करके पहली बार अपने निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की विधानसभा बनायी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने भी पण्डित जवाहरलाल नेहरू जयपुर पधारे, जो कि राजस्थान की जनता के लिए सौभाग्य की बात थी।

लम्बे समय तक दोहरी और तिहरी गुलामी की जंजीरों से जकड़े रहे राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया। उस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे।

यशस्वी पत्रकार पण्डित भावरमल शर्मा ने एक जगह लिखा है—नागौर के मेला मैदान में जिन्होंने 2 अक्टूबर, 1962 को दीप जला कर पण्डित जवाहरलाल नेहरू की पंचायती राज का शुभारंभ करते हुए देखा और सुना है वे उस दिन को नहीं भूल सकते और न ही इस बात को कि देशी राज्य लोक परिषद् और उसके उदयपुर अधिवेशन से लेकर नागौर के इस समारोह तक का इतिहास ही तो राजस्थान के कायाकल्प का इतिहास है। पंचायती राज राजस्थान को पण्डित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा उपहार था।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू कई दफा राजस्थान की यात्रा पर आये और इसे बड़ी ही आत्मीयता से गले लगाया। वे जब सन् 1963 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में आये, तभी उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम का शिलान्यास किया। इससे पहले जयपुर में वैज्ञानिकों के सम्मेलन, वनस्पती विद्यापीठ व पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज के समारोह में और राजस्थान नहर का निरीक्षण करने आये। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने हर बार राजस्थान के विकास का नया सपना देखा। उनकी इच्छा यह थी कि राजस्थान न केवल कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बने, बल्कि इतना तकनीकी विकास करे कि देश का हर कोना

उससे सबक ले। वे चाहते थे कि यहां के नागरिक आधुनिकतम बनें। राजस्थान में लहलहाती फसलों के सपनों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने 'राजस्थान नहर' की नींव रखी। चम्बल परियोजना भी उनकी सोच का नतीजा है। उन्होंने एक बार कहा था—यदि मुझे अणु शक्ति मिल जाये तो मैं उसे एक पेटी में बन्द कर राजस्थान के कोने कोने में बिखेर दूंगा, जिससे वह नखलिस्तान बन जाये।

राजस्थान को नखलिस्तान बनाने का यह सपना लेकर ही बाद में उनकी बेटी एवं भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी आगे बढ़ी और उन्होंने इस सूखे राज्य को कई नये आयाम दिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में, पोकरण में पहले बम विस्फोट के साथ आणविक शक्ति के विकास का रास्ता पकड़ा और हमारे देश भारत को उन्नत राष्ट्रों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हीं की रणनीति का कमाल था कि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में दुश्मन सेना ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिये।

हमारी दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की राजस्थान के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। भारत-पाक युद्ध के समय उन्होंने सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया और अकाल पीड़ितों की हालत को नजदीक से देखा। वे प्रधानमन्त्री बनने के बाद ऋषभदेव आदिवासी सम्मेलन में पधारी। सन् 1967-68 में कोटा में राणा प्रताप सागर बांध राष्ट्र को समर्पित किया। सन् 1982 में वे बाढ़ की स्थिति देखने आयीं। सन् 1983 में उन्होंने माही परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी राजस्थान के विकास के लिये उतनी ही चिन्तित थी जितने कि उनके दादा पण्डित मोतीलाल नेहरू और पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राजस्थान का विकास करने के लिए कई कारगर कदम उठाये जिसे राजस्थान की जनता कभी भी नहीं भूल सकती है। □

श्रीमती इन्दिरा गांधी की नरेना यात्रा

श्रीमती इन्दिरा गांधी का राजस्थान की जनता के साथ रागात्मक एवं भावात्मक संबंध था । 1980 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्यासी श्री सी. एल. कंवरिया का चुनाव प्रचार करने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी नरेना आयी । श्रीमती गांधी ने एक जन सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे आजादी के पूर्व भी नरेना आयी थीं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी सभी घमों का आदर करती थीं । उन्होंने नरेना आने का कार्यक्रम, आध्यात्मिक दृष्टि से बनाया था ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ज्यों ही वायु सेना के विमान से उतरी उस समय उनका स्वागत नगर कांग्रेस कमेटी (ई) नरेना के अध्यक्ष पंडित जगन्नाथ शर्मा ने किया । स्वागत कार्यक्रम के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी मंच पर आयी, उन्होंने कहा कि काफी लोग अभी भी आ रहे हैं । जब तक आने वाले लोग भी आ जावें मैं दाहू द्वारा मैं "दाहू वाणी" के दर्शन करके आती हूं ।

श्रीमती गांधी कंार में बैठकर सर्वप्रथम गुरुद्वारा गयीं । उस समय उनके साथ श्री रामकिशोर व्यास थे । इस गुरुद्वारे का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैलसिंह ने किया था तथा समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने की थी । नरेना में गुरुद्वारा का निर्माण, एक इतिहास के आधार पर किया गया । गुरु गोविन्दसिंह लगभग 275 वर्ष पूर्व संत जंतराम दास जी महाराज से मिलने के लिये पधारे थे, जिस समय गुरु गोविन्दसिंह नरेना आये थे, उस समय उन्होंने हिन्दुओं की रक्षा करने के लिये कमर कस रखी थी । गुरु गोविन्दसिंह ने हिन्दुओं की रक्षा करने के लिये ही खालसा पंथ की स्थापना की थी । गुरु गोविन्दसिंह और जंतरामदास जी महाराज के मध्य काफी प्रकरणों पर बातचीत हुई, जंतरामदास जी महाराज ने हिन्दुओं की रक्षा

करने के लिये बहुत से सुभाव दिये । उन सुभावों को संत गुरु गोविन्दसिंह ने माना तथा कार्यरूप में परिणित भी किये ।

संत गुरु गोविन्दसिंह हमेशा अपने साथ वाज रखते थे । संत जंतरामदास जी महाराज ने संत गुरु गोविन्दसिंह को भोजन करने का आग्रह किया । गुरु गोविन्दसिंह ने भोजन करने का आग्रह तो स्वीकार कर लिया लेकिन उसमें एक शर्त यह रख दी, कि जब तक मेरा वाज भोजन नहीं करेगा तब तक मैं भी भोजन नहीं कर सकता हूँ । संत जंतरामदास जी महाराज महान संत थे । उन्होंने कहा कि आप भी भोजन करेंगे तथा आपका वाज भी भोजन करेगा, गुरु गोविन्दसिंह जानते थे कि वाज मांस के अलावा कुछ नहीं खाता है, उसी समय संत जंतरामदास जी महाराज ने वाज के सामने अपने हाथों से ज्वार रखी, वाज ने ज्वार खाना शुरू कर दिया, इस घटना पर गुरु गोविन्दसिंह को काफी आश्चर्य हुआ, मांस खाने वाला वाज ज्वार कैसे खा गया । गुरु गोविन्दसिंह इस घटना से इतने प्रभावित हुये कि उन्होंने अपने तीर से संत दादूदयाल की समाधि को नमस्कार किया । गुरु गोविन्दसिंह को, दादूदयाल की समाधि को नमस्कार करने के कारण तनख्खा घोषित कर दिया । गुरु गोविन्दसिंह के नरेना आगमन के कारण ही सिखों ने इस नगर में बहुत ही अच्छे गुरुद्वारे का निर्माण किया है ।

संत गुरु गोविन्दसिंह जब नरेना पद्वारे तब संत जंतरामदास जी महाराज ने कहा था कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिये आपकी सहायता करने में असमर्थ हैं, आपके इस कार्य में श्री वन्दा वीरागी मदद कर सकता है । इसलिये आप श्री वन्दा वीरागी से सम्पर्क करें ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद, नरेना की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुये संत दादू दयाल के दादूद्वारे में पहुँची, वहाँ पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लगभग दस मिनट तक दादू सम्प्रदाय के पीठासीन श्री श्री १००८ स्वामी हरिराम जी महाराज से वार्तालाप किया तथा दादू वाणी की आरती भी उतारी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का आध्यात्मिकवाद में पक्का विश्वास था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि नरेना में पर्यटन केन्द्र का विकास किया जाना चाहिये, क ऐतिहासिक नगर है तथा यहाँ की स्थिति भी पर्यटन केन्द्र के लिये उपयुक्त है । प्रमुख समाज सेवी सेठ रामजीदास मोदानी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी

के स्वागत में, नरेना की जनता की ओर से जनसभा में ग्यारह हजार रुपये की थेली भेंट की ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे बीच नहीं रही लेकिन नरेना को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की नैतिक जिम्मेदारी, हमारी सरकार की है, उम्मीद की जाती है कि हमारी वर्तमान सरकार श्रीमती गांधी की इच्छा के अनुसार इस नगर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करेगी, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जनसभा को भी गुरुद्वारे के सामने इन्दिरा गांधी मैदान में सम्बोधित किया । जो मंच श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए तैयार किया गया था वो मंच आज भी नरेना नगर में मौजूद है ।



श्रीमती इन्दिरा गांधी क अंतिम राजस्थान यात्रा

राजस्थान में पंचायती राज के सपने को 2 अक्टूबर, 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साकार किया था, उसी की पच्चीसवीं वर्ष गांठ 7 अक्टूबर, 1984 को राजस्थान सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ मनायी, उस समय राजस्थान के पंचायत राज मंत्री श्री शीशराम ओला थे, जिनकी पंचायत राज और स्त्री शिक्षा में विशेष रुचि रही है।

श्री शीशराम ओला ने अपने भागीरथी प्रयत्नों से अरडावता (भुम्भनू) में इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन की स्थापना की। यह बालिका निकेतन बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में श्री हीरालाल शास्त्री के बाद अगर श्री शीशराम ओला का नाम लिया जावे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री बनने से पहले सन् 1980 में बीकानेर के पंचायत राज सम्मेलन में शामिल हुये, जो कि राजस्थान के पंचायती राज के विकास के लिये श्री गांधी की रुचि का सूचक है।

श्रीमती गांधी ने 7 अक्टूबर, 1984 को जयपुर में पंचायती राज भवन की आधारशिला रखी।

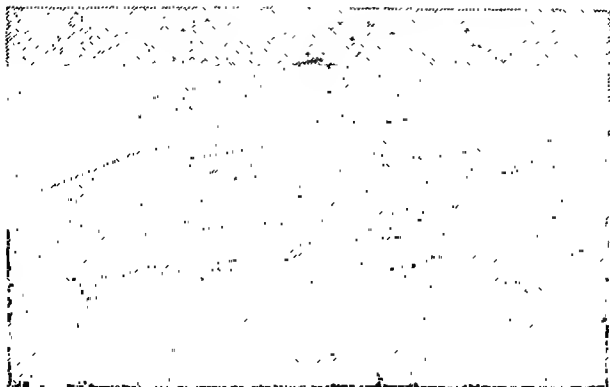
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी अंतिम राजस्थान यात्रा में कांग्रेस जनों के सम्मेलन को भी सम्बोधित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ई) अध्यक्ष पंडित श्री नवलकिशोर शर्मा ने की।

7 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अखिल भारतीय रंगर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में रंगर समाज की ओर से श्री धर्मदास

शास्त्री, सांसद ने श्रीमती गांधी का स्वागत किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान के भू० पू० स्वास्थ्य मंत्री श्री छोगालाल कंवरिया ने की। अखिल भारतीय रंगर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर ने रंगर समाज की महिलाओं की ओर से श्रीमती गांधी का स्वागत किया। इस सम्मेलन में लगभग 6-7 लाख स्त्री, पुरुषों ने भाग लिया था, जाति विशेष के सम्मेलन में भाग लेने का श्रीमती गांधी का यह पहला अवसर था। श्रीमती इन्दिरा गांधी जाति विशेष की समस्या सुनने के लिये इस जाति के लोगों के बीच आई जो कि इस जाति के लिये सौभाग्य की बात है।

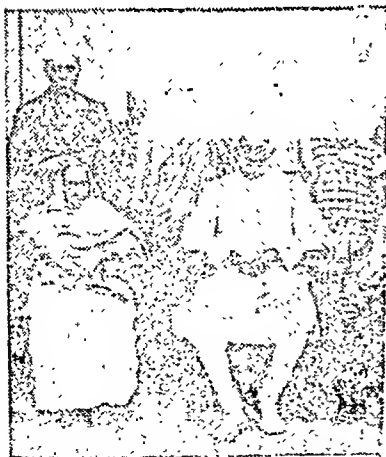
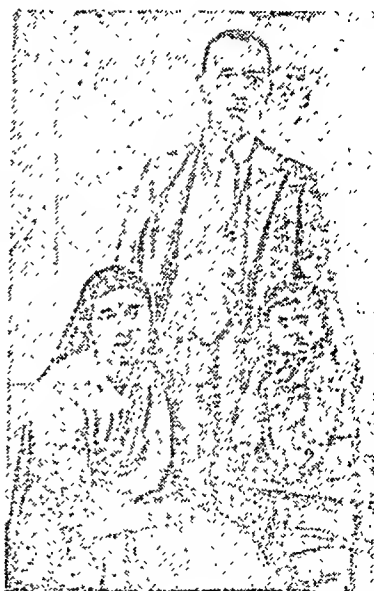
7 अक्टूबर, 1984 की यात्रा श्रीमती इन्दिरा गांधी का अंतिम जयपुर यात्रा थी। श्रीमती गांधी आज हमारे बीच नहीं रही लेकिन अन्तिम यात्रा में राजस्थान की जनता के दिलों में स्वयं की याद एवं आदर्शों और मूल्यों को छोड़कर गयीं जिसे हमारे राजस्थान राज्य की जनता कभी भी नहीं भूल सकती है।

श्रीमती गांधी देश के लिए जीयी और अन्तिम दम तक देश की सेवा में रत रहीं। वे भारत को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा देखना चाहती थीं। यही उनका स्वप्न था और जीवन पर्यन्त वे इसी के लिए प्रयास करती रहीं। गरीबी जो कि भारत के लिए अभिषाप है उसे दूर करने के लिए अनेकानेक योजनायें बनायी और पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने का भी उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। ऐसी महान नेता और युग दृष्टा का नाम भारतीय इतिहास में सदब्र अमर रहेगा। □



इलाहाबाद का
आनन्द भवन
इन्दिरा जी का
जन्म-स्थान

इन्दिरा जी के जन्म के बाद पंडित
जवाहर लाल नेहरू एवं श्रीमती
कमला नेहरू

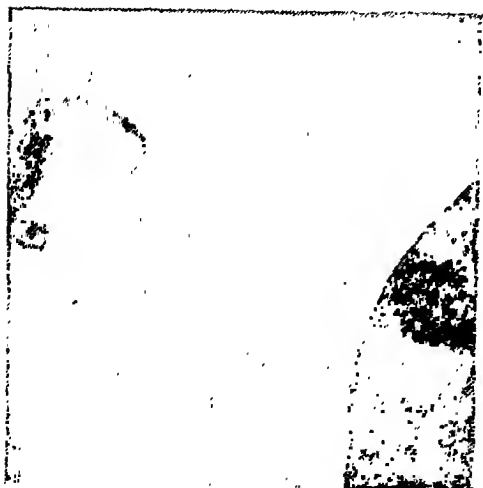
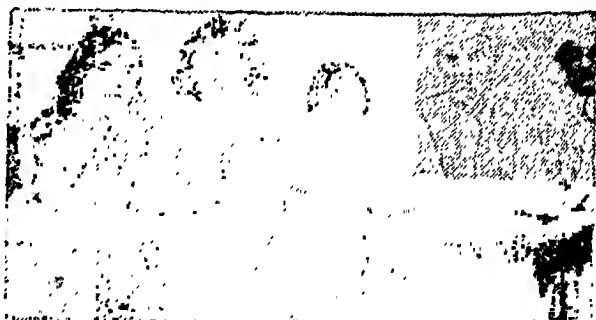


प्रियदर्शनी इन्दिरा जी वचपन में अपने
दादा-दादी एवं परिवार के साथ



इन्दिरा जी
बचपन में
महात्मा गांधी
के साथ

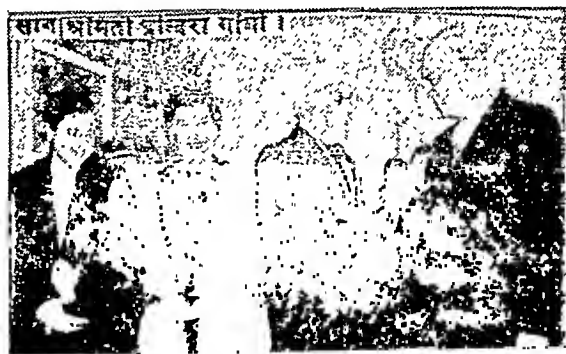
अध्ययन के
लिए यूरोप
जाते हुए
इन्दिरा जी



इन्दिरा जी अपने पिता पंडित
जवाहर लाल नेहरू के साथ

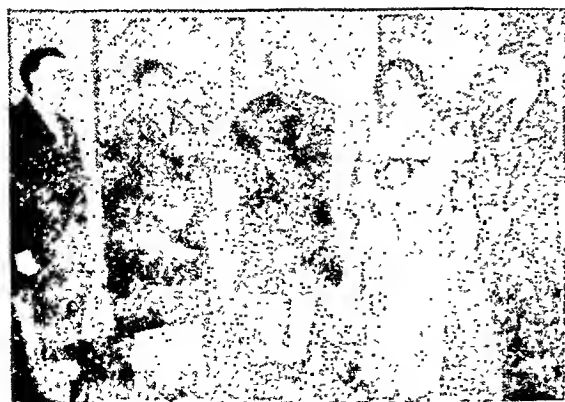


1949 में संयुक्त राष्ट्र सभ के मुख्यालय पर
पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ श्रीमती
इन्दिरा गांधी



सांग श्रीमती इन्दिरा गांधी ।

वाशिंगटन में राष्ट्रपति
आइजन हावर एवं
उनकी पत्नी के साथ
श्रीमती इन्दिरा गांधी
एवं पंडित नेहरू



विदेशी मेहमानों के बीच श्रीमती गांधी
एवं पंडित जवाहर लाल नेहरू

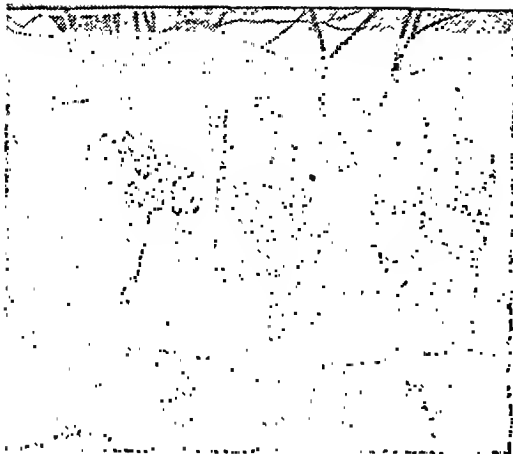


इन्दिरा जी अपने
पति फीरोज
गांधी के साथ

रूस भ्रमण के अवसर पर उजबेक
की परम्परागत वेशभूषा में श्रीमती
गांधी एवं पंडित जवाहर लाल नेहरू



वम्बई में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर
श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं पंडित जवाहर-
लाल नेहरू

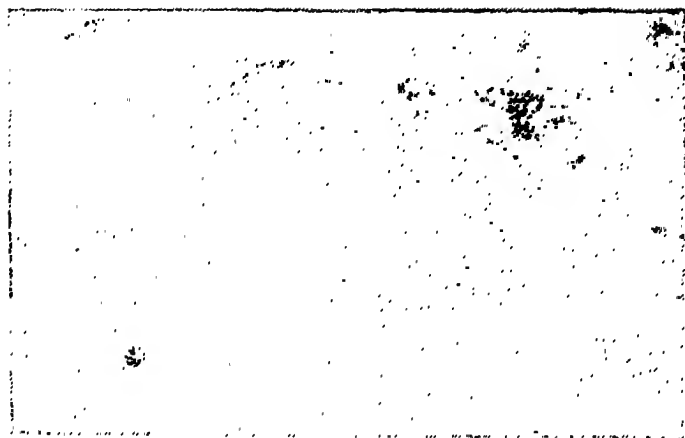


कनाडा के गवर्नर जनरल
के साथ ओटावा के राज-
निवास में श्रीमती गांधी
एवं पंडित नेहरू

उप राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की वर्षगांठ के
अवसर पर बधाई देते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी
एवं पंडित जवाहर लाल नेहरू

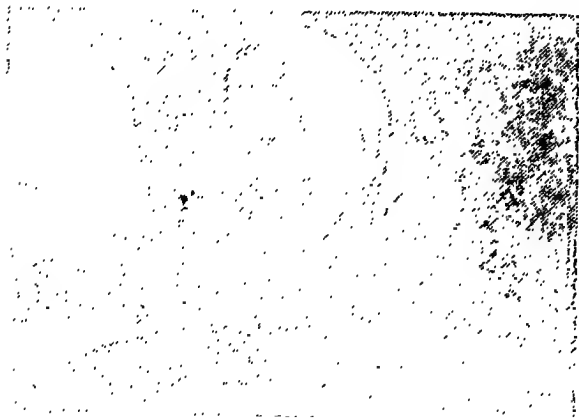
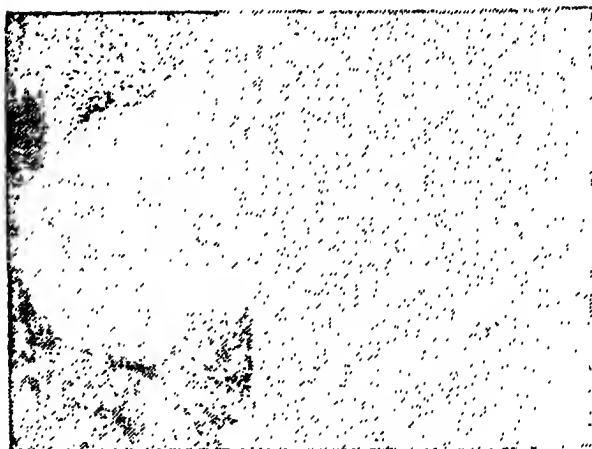


मोतीलाल, जवाहरलाल
इन्दिरा गांधी एवं
राजीव गांधी



प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी
देश की सोमा का निरीक्षण करते हुए

गुरु ग्रंथ साहिब की
अर्चना करते हुए श्रीमती
इन्दिरा गांधी

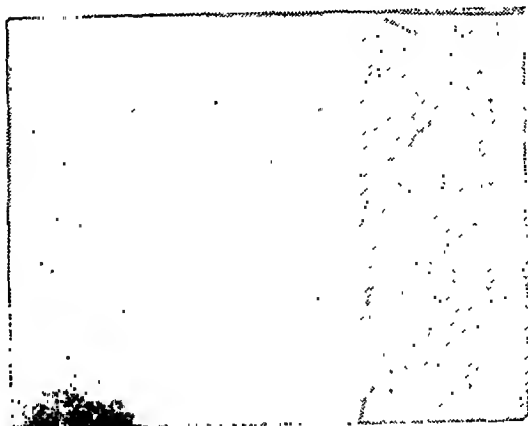


क्या कहने राजस्थानी
व्यञ्जनों के

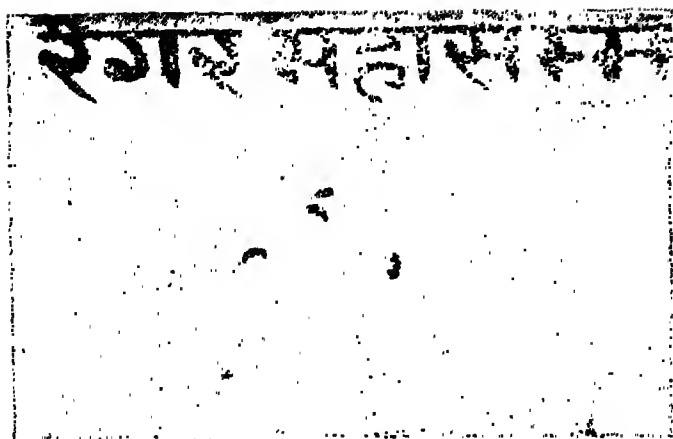


राजस्थान के एक किसान के साथ वार्त्ता करते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी, साथ में मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाडिया

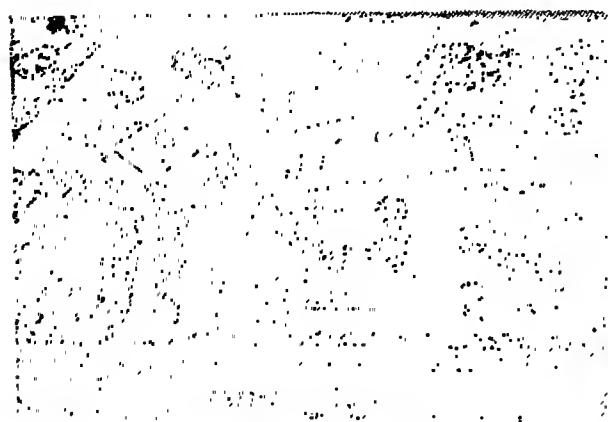
रैगर सम्मेलन में दलित महिलाओं की ओर से श्रीमती गांधी का स्वागत करते हुए दिल्ली करोल बाग की सांसद सुन्दरवती नवल प्रभाकर साथ में खड़े हैं श्री मोर्त राम बाकोलिया, पार्श्वद, नई दिल्ली



श्रीमती गांधी की नरेना यात्रा के अवसर पर जनता की ओर से प्रमुख समाज सेवी सेठ रामजो दास मोदानी थंलो भेंट करते हुए



श्री वर्मदास शास्त्री
सम्मेलन में समाज की
से श्रीमती इन्दिरा गांधी
आभार प्रकट करते हु



इन्दिरा गांधी का शहीद-स्थल



श्रीमती गांधी का हस्ति कलश ले जाते हुए
श्री राजीव गांधी



श्रीमती गांधी की हत्या के व
दुःखद क्षणों में श्री राजीव गांधी
राहुल गांधी